वायु प्रदूषण रोकने के लिए हो जरूरी साझी पहल

यूनिसेफ और अमेरिका के स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान ह्यहेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूटह्न की साझेदारी में जारी रिपोर्ट के वे आंकड़े परेशान करने वाले हैं, जिसमें वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से 21 लाख भारतीयों के मरने की बात कही गई है। दुखद बात यह है कि मरने वालों में 1.69 लाख बच्चे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया ठीक से देखी ही नहीं थी। निश्चय ही ये आंकड़े जहां व्यथित व परेशान करने वाले हैं। वहीं नीति-नियंताओं को शर्मसार करने वाले भी हैं कि इस दिशा में अब तक गंभीर प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण प्रदूषण संकट से अकेला भारत ही जूझ रहा है। चीन में भी इसी कालखंड में 23 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरे हैं। जहां तक पूरी दुनिया में इस वर्ष मरने वालों की कुल संख्या का प्रश्न है तो यह करीब 81 लाख बताई जाती है। चिंता की बात यह है कि भारत व चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की कुल संख्या के मामले में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54 फीसदी है। जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में शासन-प्रशासन की कोताही को ही दर्शाती है। आम आदमी को पता ही नहीं होता है कि किन प्रमुख कारणों से यह प्रदूषण फैल रहा है और किस तरह वे इससे बचाव कर सकते हैं। सड़कों पर लगातार बढ़ते निजी वाहन,गुणवत्ता के ईंधन का उपयोग न होना, निर्माण कार्य खुले में होना, उद्योगों की घातक गैसों व धुएं का नियमन न होने जैसे अनेक कारण वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आवासीय कॉलोनियों व व्यावसायिक संस्थानों का विज्ञानसम्मत ढंग से निर्माण न हो पाना भी प्रदूषण बढ़ाने की एक वजह है। दरअसल, अनियोजित कॉलोनियों व बहुमंजिली इमारतों के निर्माण से हवा का वह स्वाभाविक प्रवाह बाधित हुआ है जो वायु प्रदूषण रोकने में मददगार होता था। दिवाली के आसपास पराली जलाने का ठीकरा किसानों के सिरों पर फोड़कर प्रदूषण नियंत्रण की जवाबदेही से मुक्त होने का जो उपक्रम होता है, वह जगजाहिर है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से वर्ष 2021 में जिन 21 लाख लोगों की मौत होने का जिक्र है, दुर्भाग्य से उनमें 1,69,400 बच्चे हैं। जिनकी औसत आयु पांच साल से कम बतायी गई है। जानलेवा प्रदूषण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होने से बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं, इनका शारीरिक विकास भी सही से नहीं हो पाता। इससे बच्चों का कम वजन का पैदा होना, अस्थमा तथा फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि बेहद गरीब मुल्कों नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इथोपिया से ज्यादा बच्चे हमारे देश में वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। विडंबना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के संकट ने वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या को बढ़ाया ही है। एक अरब चालीस करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत के लिये यह संकट बहुत बड़ा है। चिंता की बात यह है कि दक्षिण एशिया में मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण ही है। उसके बाद उच्च रक्तचाप, कुपोषण तथा तंबाकू सेवन से होने वाली मौतों का नंबर आता है। दरअसल, गरीबी और आर्थिक असमानता के चलते बड़ी आबादी येन-केन- प्रकारेण जीविका उपार्जन में लगी रहती है, उसकी प्राथमिकता प्रदूषण से बचाव के बजाय रोटी ही है। वहीं ढुलमुल कानूनों, तंत्र की काहिली तथा जागरूकता के अभाव में वायु प्रदूषण रोकने की गंभीर पहल नहीं हो पाती। हर साल शीत ऋतु की दस्तक होने पर वायु प्रदूषण का जो बड़ा संकट राष्ट्रीय राजधानी में पैदा होता है, उसे शासन फौरी उपायों से दूर करने का प्रयास करता है। वाहनों की गुणवत्ता के मानकों पर प्रवेश, ऑड-ईवन की तर्ज पर वाहनों का चलाना, फैक्ट्रियों में उत्पादन पर रोक, निर्माण कार्य पर रोक जैसे फौरी उपायों का सहारा लिया जाता है। फिर साल भर के लिये तंत्र हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। सवाल यह है कि ये नीतियां साल भर के लक्ष्य को रखकर क्यों नहीं बनायी जाती? राष्ट्रीय राजधानी के अलावा भी देश में यह संकट लगातार गहरा हो रहा है, तो विभिन्न राज्यों में दिल्ली जैसी पहल क्यों नहीं होती?

दिल-दिमाग तक पहुंच रहे हैं प्लास्टिक कण

मुकुल व्यास

पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची है जहां माइक्रोप्लास्टिक नहीं पहुंचा हो। हमारे पर्यावरण को दूषित करने के पश्चात प्लास्टिक के अत्यंत सूक्ष्म कण अब मानव अंगों में भी दाखिल हो चुके हैं। मस्तिष्क और हृदय में माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। प्लेसेंटा (नाल) और मां के दूध में भी प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। अपनी व्यापक उपस्थिति और संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के कारण माइक्रोप्लास्टिक नई चिंताओं को जन्म दे रहा है। इस साल की शुरूआत में एक बड़े अध्ययन में हृदय की अवरुद्ध धमनियों में जमा वसा के 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सों में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए थे। यह माइक्रोप्लास्टिक और मानव स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करने वाला अपनी तरह का पहला डेटा था। अब चीन के शोधकताओं ने एक नए अध्ययन में हृदय और मस्तिष्क की धमनियों तथा निचले पैरों की नसों से शल्य चिकित्सा द्वारा निकाले गए रक्त के थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की जानकारी दी है।

ताजा चीनी अध्ययन में 30 रोगियों को शामिल किया गया जबकि मार्च में प्रकाशित इतालवी अध्ययन में 34 महीनों तक 257 रोगियों का अनुसरण किया गया था। इतालवी विज्ञानियों की नेतृत्व वाली टीम ने पता लगाया था कि धमनियों की जमावट अथवा प्लेक में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी लोगों में दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाती है। अब चीनी टीम ने भी रक्त के थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक के स्तर और बीमारी की गंभीरता के बीच संभावित संबंध को रेखांकित किया है। अध्ययन में शामिल 30 रोगियों को स्ट्रोक, दिल का दौरा या डीप वेन थ्रोम्बोसिस का अनुभव होने के बाद रक्त के थक्कों को हटाने के लिए सर्जरी करानी पड़ी थी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैरों की गहरी नसों में रक्त के थक्के बनते हैं।

अध्ययन में सम्मिलित औसतन 65 वर्ष की आयु के रोगियों में उच्च रक्तचाप या डायबिटीज जैसी विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी और उनकी जीवनशैली में धूम्रपान और शराब का सेवन शामिल था। वे प्रतिदिन प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग करते थे। रक्त के 30 थक्कों का अध्ययन किया गया। इनमें से 24 में रासायनिक विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न आकारों के माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाया गया। परीक्षण में उसी प्रकार के प्लास्टिक की पहचान की गई जो इतालवी अध्ययन में पाए गए थे। ये प्लास्टिक हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और पॉलीइथिलीन (पीई)। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि पीवीसी का अक्सर निर्माण में उपयोग किया जाता है। ये दो सबसे अधिक उत्पादित प्लास्टिक हैं।

नए अध्ययन में थक्कों में ह्यपॉलियामाइड 66ह्न का भी पता चला, जो कपड़े और वस्त्रों में इस्तेमाल होने वाला एक आम प्लास्टिक है। अध्ययन में पहचाने गए 15 प्रकारों में से, पीई सबसे आम प्लास्टिक था। विश्लेषित कणों में इसका हिस्सा 54 प्रतिशत था। शोधकताओं ने यह भी पाया कि जिन लोगों के रक्त के थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर अधिक था, उनमें डी-डिमर का स्तर भी उन रोगियों की तुलना में अधिक था,जिनके रक्त थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक नहीं पाया गया था। डी-डिमर प्रोटीन का एक टुकड़ा है जो रक्त के थक्कों के टूटने पर निकलता है। यह सामान्य रूप से रक्त प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। इसलिए रक्त परीक्षण में डी-डिमर का उच्च स्तर रक्त के थक्कों की उपस्थिति का संकेत दे सकता है।

शोधकताओं को संदेह है कि माइक्रोप्लास्टिक रक्त में जमा होकर थक्के को बदतर बना सकता है। मानव स्वास्थ्य के लिए माइक्रोप्लास्टिक नुकसानदेह है। लेकिन इसकी जांच के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। चीनी वैज्ञानिक टिंग टिंग वांग और उनके सहयोगियों ने अपने पेपर में लिखा है कि उनके निष्कर्ष बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक धमनियों और नसों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा जोखिम कारक हो सकते हैं। शोधकताओं ने चेतावनी दी कि पर्यावरण और रोजमर्रा के उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक की सर्वव्यापकता के कारण मानव का माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आना अपरिहार्य है। अतः दुनिया को प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाना पड़ेगा।

इस बीच, अमेरिका के न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए शोध में कुत्तों और मनुष्यों, दोनों से लिए गए अंडकोष के ऊतक के नमूनों की जांच की गई। शोधकताओं ने प्रत्येक नमूने में माइक्रोप्लास्टिक पाया, जिसकी प्रचुरता कुत्तों की तुलना में मनुष्यों में लगभग तीन गुना अधिक थी। टीम ने कुत्तों में ऊतक के प्रति ग्राम औसतन 122.63 माइक्रोग्राम माइक्रोप्लास्टिक पाया। मनुष्यों में यह मात्रा प्रति ग्राम 329.44 माइक्रोग्राम थी।

यह अध्ययन हमें यह याद दिलाने के अलावा कि प्लास्टिक प्रदूषण हमारे शरीर के हर हिस्से में कैसे प्रवेश कर रहा है, एक चिंताजनक सवाल उठाता है कि क्या प्लास्टिक के सूक्ष्म टुकड़े पुरुष प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं? न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के पर्यावरण स्वास्थ्य वैज्ञानिक ज़ियाओ सोंग यू कहते हैं, शुरूआत में मुझे संदेह था कि माइक्रोप्लास्टिक प्रजनन प्रणाली में प्रवेश कर सकता है। जब मुझे पहली बार कुत्तों के लिए परिणाम मिले तो मैं हैरान रह गया। जब मुझे मनुष्यों के लिए परिणाम मिले तो मैं और भी हैरान रह गया।

पहचाने गए 12 अलग-अलग प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक में से, शोधकताओं को कुत्तों और मनुष्यों दोनों में पॉलीइथिलीन (पीई) प्लास्टिक सबसे ज्यादा मिला जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक की बोतलों के निर्माण में होता है। हमारी प्लास्टिक प्रदूषण समस्या में पीई का प्रमुख योगदान है। मानव ऊतक में शुक्राणुओं की संख्या के लिए परीक्षण नहीं किया जा सका लेकिन शोधकताओं ने कुत्तों के नमूनों में ऐसा किया। उन्होंने पाया कि पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) प्लास्टिक का उच्च स्तर जानवरों में शुक्राणुओं की कम संख्या से संबंधित है। पीवीसी का व्यापक रूप से कई औद्योगिक और घरेलू उत्पादों में उपयोग किया जाता है, इसलिए चिंता यह है कि प्लास्टिक दुनिया भर में शुक्राणुओं की संख्या में कमी लाने में नकारात्मक भूमिका निभा सकता है। शुक्राणुओं की कमी को पहले से ही भारी धातुओं, कीटनाशकों और कई तरह के रसायनों से जोड़ा गया है। हालांकि, कुत्तों में देखे गए पीवीसी के इन परिणामों को पुरुषों में भी दोहराए जाने की आवश्यकता होगी, ताकि हम समझ सकें कि क्या मनुष्यों में भी ऐसा ही हो रहा है।

सनातन हिंदू संस्कृति का पूरे विश्व में फैलना विश्व शांति के लिए जरूरी

प्रहलाद सबनानी

आज जब कई मुस्लिम देश शिया एवं सुन्नी सम्प्रदाय के नाम पर आपस में ही लड़ रहे हैं तो उनका ईसाई पंथ को मानने वाले नागरिकों के साथ सामंजस्य किस प्रकार रह सकता है, अतः यूरोपीयन देशों के नागरिकों को अब अपने किए पर पश्तावा होने लगा है। ब्रिटेन में भी आज मुस्लिम समाज की आबादी बहुत बढ़ गई है एवं यहां का ईसाई समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है क्योंकि मुस्लिम समाज द्वारा ईसाई समाज पर कई प्रकार के आक्रमण किया जाना आम बात हो गई है। ब्रिटेन के कई शहरों में तो मेयर आदि जैसे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर भी मुस्लिम समाज के नागरिक ही चुने गए है अतः इन नगरों में सत्ता की चाबी ही अब मुस्लिम समाज के नागरिकों के हाथों में है, जिसे ईसाई समाज के नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार, इजरायल (यहूदी समुदाय) एवं हम्मास (मुस्लिम समुदाय) के बीच युद्ध लम्बे समय से चल रहा है। ईरान (शिया समुदाय) - सऊदी अरब (सुन्नी समुदाय) के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं है।

यूरोप में हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में दक्षिणपंथी कहे जाने वाले दलों की राजनीतिक ताकत बढ़ी है। हालांकि सत्ता अभी भी वामपंथी एवं मध्यमार्गीय नीतियों का पालन करने वाले दलों की ही बने रहने की सम्भावना है परंतु विशेष रूप से फ्रांस एवं जर्मनी में इन दलों को भारी नुक्सान हुआ है। इटली की देश प्रेम से ओतप्रोत दल की मुखिया जोरजीया मेलोनी को अच्छी सफलता हासिल हुई है। कुल मिलाकर यूरोपीय देशों के नागरिकों में देश प्रेम का भाव धीमे धीमे लौट रहा है एवं वे अब अपने अपने देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों का विरोध करने लगे हैं। विशेष रूप से यूरोप के आस पास के मुस्लिम बहुल देशों से भारी संख्या में मुस्लिम नागरिक अवैध रूप से इन देशों में शरण लिए हुए हैं एवं अब वे इन देशों की कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। जर्मनी एवं फ्रान्स ने मुस्लिम नागरिकों को मानवीय आधार पर अपने देश में बसाने में शिथिल नीतियों का पालन किया था और अब ये दोनों देश इस संदर्भ में विभिन्न समस्याओं का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं।

आज जब कई मुस्लिम देश शिया एवं सुन्नी सम्प्रदाय के नाम पर आपस में ही लड़ रहे हैं तो उनका ईसाई पंथ को मानने वाले नागरिकों के साथ सामंजस्य किस प्रकार रह सकता है, अतः यूरोपीयन देशों के नागरिकों को अब अपने किए पर पश्तावा होने लगा है। ब्रिटेन में भी आज मुस्लिम समाज की आबादी बहुत बढ़ गई है एवं यहां का ईसाई समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है क्योंकि मुस्लिम समाज द्वारा ईसाई समाज पर कई प्रकार के आक्रमण किया जाना आम बात हो गई है। ब्रिटेन के कई शहरों में तो मेयर आदि जैसे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के पदों पर भी मुस्लिम समाज के नागरिक ही चुने गए है अतः इन नगरों में सत्ता की चाबी ही अब मुस्लिम समाज के नागरिकों के हाथों में है, जिसे ईसाई समाज के नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार, इजरायल (यहूदी समुदाय) एवं हम्मास (मुस्लिम समुदाय) के बीच युद्ध लम्बे समय से चल रहा है। ईरान (शिया समुदाय) - सऊदी अरब (सुन्नी समुदाय) के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं है। पाकिस्तान में तो अहमदिया समुदाय एवं बोहरा समुदाय को मुस्लिम ही नहीं माना जाता है एवं इनको गैर मुस्लिम मानकर इन पर सुन्नी समुदाय द्वारा खुलकर अत्याचार किए जाते हैं। कुल मिलाकर, मुस्लिम समाज न केवल अन्य समाज के नागरिकों (यहूदी, ईसाई, हिंदू आदि) के साथ लड़ता आया है बल्कि इस्लाम के विभिन्न फिर्कों के बीच भी इनकी आपसी लड़ाई होती रही है। इसके ठीक विपरीत, सनातन हिंदू संस्कृति का अनुपालन करते हुए कई भारतीय मूल के नागरिक भी अन्य देशों में रह रहे हैं एवं लम्बे समय से स्थानीय स्तर पर ईसाई समाज एवं अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। इन देशों में भारतीय मूल के नागरिकों एवं स्थानीय स्तर पर अन्य धर्मों के अनुयायियों के बीच कभी भी बड़े स्तर पर आक्रोश उत्पन्न होता दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि सनातन हिंदू संस्कृति में ह्लवसुधैव कुटुम्बकमह्व एवं ह्लसर्वे भवंतु सुखिनःह्व का भाव हिंदू नागरिकों में बचपन से ही भरा जाता है।

इसी प्रकार के भाव का संचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पिछले 99 वर्षों से अपने स्वयंसेवकों में जगाता आया है। संघ चाहता है कि संसार में सद्गुणों का बोलबाला हो। 27 सितम्बर 1933 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, शस्त्र पूजा समारोह में अपने उद्बोधन में कहते हैं कि ₹संघ एक हिंदू संगठन है। संसार के सभी धर्मों में हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है, जिसका मुख्य गुण सद्गुण है और जो 'आत्मवत् भूतेषु' (सभी प्राणियों में अपने को देखना) की भावना से सभी जीवों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना सिखाता है। यह धर्म संसार में व्याप्त हिंसा और अन्याय को स्वीकार नहीं करता। इसलिए स्वाभाविक है कि प्रत्येक हिंदू ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहता है। लेकिन केवल उपदेश देने से संसार का स्वभाव नहीं बदलेगा। जब संसार को लगेगा कि हिंदू समाज सुसंगठित और सशक्त हो गया है, तो हमारे प्रति जो अनादर का भाव सर्वत्र दिखाई देता है, वह समाप्त हो जाएगा और संसार हमारी बात सुनेगा। हिंदू धर्म अनादि काल से यही करता आ रहा है और ऐसे पवित्र धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ही संघ की शुरूआत हुई है।ह्व ₹आजकल हिंदू समाज बहुत अव्यवस्थित हो गया है। संघ का एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को इस तरह संगठित करना है कि हिंदू, हिंदुस्तान में गर्वित हिंदू के रूप में खड़े हो सकें और दुनिया को यह विश्वास दिला सकें कि हिंदू कोई ऐसी जाति नहीं है जो मरणासन्न अवस्था में हो। संघ चाहता है कि संसार में सद्गुणों का बोलबाला हो। संघ का लक्ष्य मानव जाति में व्याप्त राक्षसी प्रवृत्ति को दूर करना और उसे मानवता सिखाना है। संघ का गठन किसी से घृणा करने या उसे नष्ट करने के लिए नहीं हुआ है। यह बात ध्यान रखने वाली है कि ईरान कभी आर्यों का अर्थात पारसियों का देश था। इराक, सऊदी अरब ,पश्चिम एशिया के समस्त मुस्लिम देश 1400 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले देश थे। तलवार के बल पर 57 देश इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 1400 वर्ष पहले से अर्थात सनातन की भांति सृष्टि के प्रारंभ से मुस्लिम देश था। 1398 ईसवी में ईरान भारत से अलग हुआ, 1739 में नादिरशाह ने अफगानिस्तान को अपने लिए एक अलग रियासत के रूप में प्राप्त कर लिया, बाद में 1876 में यह एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आ गया,1937 में म्यांमार बर्मा अलग हुआ, 1911 में श्रीलंका अलग हुआ और 1904 में नेपाल अलग हुआ। सांप्रदायिक आधार पर देश विभाजन का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका इसके पश्चात 1947 में पश्चिमी एवं पूर्वी पाकिस्तान देश बना। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में मानचित्र पर उपलब्ध है।

आज एक बार पुनः भारत के भीतर जहां-जहां इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या बहुलता को प्राप्त हो गई है, वहां वहां पर अनेक प्रकार की सामाजिक विसंगतियां, दमन और शोषण के नए-नए स्वरूप देखे जा रहे हैं। केरल, कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, बंगाल जहां जहां उनकी संख्या बहुलता में है, वहां -वहां दूसरे धर्म और जाति के लोग परेशान हैं। उपस्थित तथ्यों से सत्य को समझना चाहिए। इन आंकड़ों के आलोक में हमें समझना चाहिए कि हमारी बहू, बेटियां, महिलाओं की इज्जत कब तक सुरक्षित रह सकती है? निश्चित रूप से तब तक जब तक कि भारतवर्ष सनातनी हिंदुओं के हाथ में है। हमें इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए कि अब हम सांप्रदायिक आधार पर देश का पुनः विभाजन नहीं होने दें। नोआखाली जैसे नरसंहारों की पुनरावृत्ति अब हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। भारत-पाकिस्तान के विभाजन के समय जिस प्रकार लाखों करोड़ों लोगों को घर से बेघर होना पड़ा था, उस इतिहास को अब दोहराया नहीं जाना चाहिए। भारत में आंतरिक स्थिति ठीक नजर नहीं आती है परंतु विश्व के कई अन्य देशों में सनातन संस्कृति को तेजी से अपनाया जा रहा है, तभी तो कहा जा रहा है कि विश्व में आज कई समस्याओं का हल केवल हिंदू सनातन संस्कृति को अपना कर ही निकाला जा सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अभिमत

अस्सी के दशक की बात है। हिमालय की तरह पश्चिमी घाट में वनों की कटाई होने लगी। यह उष्ण कटिबंधीय वन जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। जंगलों पर लोगों की आजीविका व जीवन निर्भर था। लेकिन सरकार की वननीति के चलते यहां की जैव विविधता व पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा। इससे न केवल यहां के लोगों का जीवन कठिन हुआ बल्कि यहां के पीने के पानी और खेती की सिंचाई का भी संकट बढ़ने लगा। चिपको से प्रेरणा लेकर यहां भी अप्पिको (कन्नड़ भाषा का शब्द) नाम से जिसका अर्थ भी चिपको ही होता है, आंदोलन चला।

चिपको की तरह दक्षिण भारत का अप्पिको

नवाचार

■ बाबा मायाराम

इस आंदोलन का असर हुआ कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट में हरे पेड़ों को कटने पर सरकार ने रोक लगाई, जो अब भी जारी है। यह अहिंसक व गांधीवादी तरीके का आंदोलन था। पेड़ों से लोग चिपक गए थे। यह प्रतीकात्मक ही नहीं था, वास्तव में वनों की कटान रोकने के लिए वनों से लोग चिपक गए। बिलकुल उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की तरह।

चिपको आंदोलन की 50 वीं वर्षगांठ पूरी हो रही है। इस आंदोलन ने हिमालय में वन कटाई पर रोक लगवाने में सफलता पाई थी। इसका देश-दुनिया में काफी असर हुआ था। कई जगहों पर इससे प्रभावित होकर लोगों ने पेड़, पहाड़, पानी, पत्थर और खेती को बचाने के लिए पहल शुरू की थी। इसके साथ, शराब बंदी आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और पर्यावरण जागरूकता के लिए मुहिम छेड़ी। आज मैं इस कॉलम में चिपको से प्रेरणा लेकर कर्नाटक में चलने वाली एक महत्वपूर्ण पहल अप्पिको के बारे में बताना चाहूंगा।

हाल ही में मुझे चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेकर अप्पिको आंदोलन के सूत्रधार पांडुरंग हेगड़े से मिलने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ के राजिम कस्बे में वे एक बैठक में हिस्सा लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने मुझे अप्पिको आंदोलन की प्रेरणादायक कहानी सुनाई। वे देश-दुनिया में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं।

आगे बढ़ने से पहले चिपको आंदोलन के बारे में जानना उचित होगा। मुझे एक-दो बार चिपको के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को भी देखने व सुनने का मौका मिला है। मुझे उनकी एक बात याद है, जो उन्होंने इन्दौर की एक बैठक में कही थी। उन्होंने कहा था कि पेड़ भी जिंदा हैं,और वे बातें भी करते हैं। अगर उन्हें गले से लगाते हैं तो सुकून मिलता है।

चिपको आंदोलन महिलाओं की अगुआई में हुआ था। इसका श्रेय बहुगुणा जी भी महिलाओं को देते थे। वे कहते थे महिलाएं जंगल का महत्व अच्छे से जानती हैं, क्योंकि वह उनका मायका है, जो हर संकट के समय उनके साथ रहता है। जंगल से ही उनकी सब जरूरतें पूरी होती हैं। फल, फूल, शहद, ईंधन, चारा, पानी, रेशे सब कुछ। इस आंदोलन ने वन कटाई पर न केवल रोक लगाने में सफलता पाई थी, पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था। बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण के प्रति चेतना जगाई थी।

पांडुरंग हेगड़े दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान ही हिमालय के चिपको आंदोलन में शामिल हो गए थे और कई गांवों में घूमे थे और कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। वे शुरूआत से स्वभाव से घुमक्कड़ हैं, और पर्यावरण के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको की प्रेरणा से उनकी जीवनधारा ही बदल गई। उन्हें बड़ी नौकरियों के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने उनकी कर्मभूमि कर्नाटक को ही बनाया, जहां के वे रहने वाले हैं।

पांडुरंग हेगड़े जब पढ़ाई के बाद उनके गांव वापस लौटे तब तक घने जंगल उजाड़ में बदल रहे थे। हरे पेड़ कट रहे हैं। इससे पांडुरंग व्यथित हो गए, उन्हें उनका बचपन याद आ गया। बचपन में वे खुद घर के मवेशी जंगल में चराते थे, तब बहुत घना जंगल देखा था। हरे पेड़, शेर, हिरण,जंगली सुअर,जंगली भैंसा, बहुत से पक्षी और तरह-तरह की चिड़ियाएं देखी थीं। पर कुछ सालों के अंतराल में इसमें कमी आई।

अस्सी के दशक की बात है। हिमालय की तरह पश्चिमी घाट में वनों की कटाई होने लगी। यह उष्ण कटिबंधीय वन जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। जंगलों पर लोगों की आजीविका व जीवन निर्भर था। लेकिन सरकार की वननीति के चलते यहां की जैव विविधता व पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा। इससे न केवल यहां के लोगों का जीवन कठिन हुआ बल्कि यहां के पीने के पानी और खेती की सिंचाई का भी संकट बढ़ने लगा। चिपको से प्रेरणा लेकर यहां भी अप्पिको (कन्नड़ भाषा का शब्द) नाम से जिसका अर्थ भी चिपको ही होता है, आंदोलन चला।

उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर हस्तक्षेप करनी की सोची। इसी समय सुंदरलाल बहुगुणा जी कर्नाटक आए और उन्होंने चिपको आंदोलन का अनुभव ग्रामीणों को बताया और कहा कि आप भी इस काम को आगे बढ़ाएं। उनसे प्रेरणा लेकर सालकनी गांव से विरोध शुरू हुआ और आसपास के गांवों में फैला। यहां पदयात्रा की, जिनमें महिलाएं व युवा शामिल थे। इस आंदोलन का विस्तार जल्द ही पड़ोसी गांव सिद्दापुर तालुका तक हो गया।

इसके पहले पांडुरंग हेगड़े चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा के साथ कश्मीर से कोहिमा तक की पदयात्रा में शामिल हुए थे, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। इसीलिए पदयात्राओं का महत्व लोगों को जोड़ने व चेतना जगाने में क्या है, उसे अच्छी तरह समझते थे।

पांडुरंग हेगड़े ने इसमें सभी तबके को जोड़ा, राजनीतिक पार्टियों को भी शामिल किया। उनका कहना था कि हमारा मुख्य उद्देश्य वनों की रक्षा करना है, जो हमारे और सभी जीव-जगत के जीवन का आधार है। हमें इसमें सबकी भागीदारी की जरूरत है, पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। हमें वननीति में बुनियादी बदलाव चाहते हैं, जो कृषि में मददगार हो। जिस पर देश की बड़ी आबादी आश्रित है।

ग्रामीणों का कहना था कि कृषि उपज घट रही है, क्योंकि जंगल कट रहा है। फसलों में रोग लग रहे हैं। आर्थिक हालत खराब हो रही है। कर्ज बढ़ रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले में 80 प्रतिशत जंगल था, जो वन दोहन के कारण काफी कम हो गया था। और उसकी जगह सागौन व यूकेलिप्टस लगाया था। जलस्रोत सूख गए थे। बारिश भी कम हो रही थी। जंगल से फल, चारा, ईंधन, जैव खाद और रेशा मिलते थे, उनमें कमी आ रही थी। अप्पिको आंदोलन से वनों को फिर से हरा-भरा करने में मदद मिली और लोगों की आजीविका भी इससे जुड़ी।

हिमालय के चिपको आंदोलन की तरह पश्चिमी घाट में अप्पिको आंदोलन भी प्रसिद्ध हुआ। वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। इसे न केवल लोगों का समर्थन हासिल हुआ बल्कि मीडिया में अच्छा कवरेज मिला, सरकारी महकमे में मान्यता मिली।

इस आंदोलन का असर हुआ कि कर्नाटक के पश्चिमी घाट में हरे पेड़ों को कटने पर सरकार ने रोक लगाई, जो अब भी जारी है। यह अहिंसक व गांधीवादी तरीके का आंदोलन था। पेड़ों से लोग चिपक गए थे। यह प्रतीकात्मक ही नहीं था, वास्तव में वनों की कटान रोकने के लिए वनों से लोग चिपक गए। बिलकुल उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की तरह।

इस आंदोलन से नया नारा निकला। उलीसू, बेलासू और बालूसू। यानी जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ और उनका किफायत (टिकाऊ) से इस्तेमाल करो। यह आंदोलन आम लोगों और उनकी जरूरतों से जुड़ा है, यही कारण है कि इतने लम्बे समय तक चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन को आजीविका की रक्षा से जोड़ा।

पांडुरंग हेगड़े का कहना है कि यह आंदोलन किसी संस्था, व्यक्ति का काम नहीं, यह जनसाधारण का आंदोलन था, जो आज भी कई रूपों में जारी है। गांव-गांव संपर्क, पदयात्राएं, रैली और जुलूस निकले, लेकिन यह सभी स्थानीय लोगों के सहयोग, संसाधन व भागीदारी से हुए।

अप्पिको के साथ दक्षिण भारत में पर्यावरण बचाने के लिए कई और पहल हुई हैं, जिसमें पांडुरंग हेगड़े ने महती भूमिका निभाई है। हालांकि कई पहलों में इस आंदोलन को सफलता भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी यह मुहिम जारी है। पांडुरंग हेगड़े ने पर्यावरण की जागरूकता की इस मुहिम को रचनात्मक गतिविधियों के साथ जोड़ा, नाटक व गीतों का भी इसमें इस्तेमाल किया।

जैव विविधता की एक कड़ी में मधुमक्खी बचाने की पहल की जा रही है। इसके लिए हनी फेस्टिवल (शहद मेला) का आयोजन किया जाता है। इस मेले में युवा बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और मधुमक्खी व जैव विविधता क्यों जरूरी है, इस पर विस्तार से बात होती है। इसमें मधुमक्खी की देशी प्रजातियों को बचाने पर जोर दिया जाता है।

चिपको और अप्पिको अब वन संरक्षण का पर्याय बन गए हैं। इससे प्रेरणा लेकर कई जगहों पर लोग पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए हैं। पांडुरंग, इसकी पहचान और चेहरा भी माने जाते हैं। अप्पिको से शुरूआत के बाद छह राज्यों में पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन भी चल रहा है, जो पर्यावरण बचाने की महत्वपूर्ण पहल है।

पांडुरंग हेगड़े अब देश-दुनिया में पर्यावरण जागरूकता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें विदेश के कई देशों में जाने का मौका भी मिला है। वहां के पर्यावरण और जनजीवन को देखने का करीब से देखने का मौका मिला है। उनका मानना है कि हमारे देश में जितनी विविधता है, उतनी ही विकल्पों की भी विविधता है। यहां कई रूपों में समाज, व्यक्ति व संस्थाएं विकल्प गढ़ने की कोशिश कर रही हैं। हर क्षेत्रों में यह विकल्प उभर रहे हैं, जो उम्मीद जगाते हैं।

अप्पिको आंदोलन अहिंसक पर्यावरण का आंदोलन था, जो आज भी अलग- अलग तरह से जारी है। इस आंदोलन ने पर्यावरण रक्षा को लोगों की आजीविका की रक्षा से जोड़ा। गांव के टिकाऊ जीवन पद्धति व टिकाऊ विकास, गांवों की आजीविका और दीर्घकालीन दृष्टि से पर्यावरण बचाने की राह अपनाई। अप्पिको आंदोलन का पर्यावरण रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो अनुकरणीय व प्रेरणादायक है। लेकिन क्या सचमुच इस दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हैं?

बीता सप्ताह

15 जून

- पीएम मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में इटली में भाग लिया।
- कुवैत में आगजनी में मारे गए 45 भारतीयों के शव कोच्चि एयरपोर्ट पर लाए गए।
- सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई ने जांच शुरु की और कहा कि सिलेक्ट केंडीडेंट को आंसरशीट और इंटरव्यू पैनल के डाक्यूमेंट की फॉरेंसिक जांच होगी।
- बिहार सरकार ने बेरोजगार को महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की।

16 जून

- छत्तीसगढ़ के बस्तर रे अबूझमाड में नक्सलियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद व 8 नक्सली मारे गए।
- उत्तराखंड में रूद्र प्रयाग के समीप टेम्पो ट्रेवलर अलकनंदा नदी में गिरा जिसमें सवार 14 लोगों की मौत हो गई।
- दक्षिण अफ्रीका से सत्तारूढ़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता सिरिल रामफोसा फिर से राष्ट्रपति बनाए गए।
- जी-7 सम्मेलन में भारत का दृष्टिकोण रखने के बाद पीएम मोदी भारत लौटे।

17 जून

- दुनिया के सबसे अणीर व्यक्ति एलन मस्क ने कहा-ईवीएम मशीन हैक हो सकती है।
- एनसीईआरटी की किताब के पाठ्यक्रम से बाबरी मस्जिद, भगवान श्रीराम रथयात्रा, विध्वंस के बाद हुई हिसां की जानकारी पुस्तक से हटा दी गई।
- भारतीय टीम की महिला ओपनर स्मृति मंधाना 7000 रन बनाने वाली दूसरी महिला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनीं।
- नामीबिया के मध्यम क्रम के बल्लेबाज डेविड वीजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास ले लिया।

18 जून

- प. बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास कंचनजंगा से मालगाड़ी भिड़ी जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई।
- छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद बनने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया।
- नीडरलैंड्स के क्रिकेटर साईब्रांड एंगलब्रेक्ट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया।
- ओलम्पिक और विश्व चैंपियन भारतीय नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलीट्स कांटीनेंटल गोल्ड टूर 2024 पावो नूरमी गेम्स में हिस्सा लिया।

19 जून

- बिहार में अररिया में बकरा नदी में 12 करोड़ का पुल टूटकर नदी में समा गया।
- मशहूर फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमैंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- टी-20 विश्वकप के 40वें मुकाबले में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रनों से हराया।
- विश्व के तीसरे नंबर की खिलाड़ी आर्मना सब्गलेंका स्वास्थ्य कारणों से पेरिस ओलंपिक से हट गई।

20 जून

- छत्तीसगढ़ के केबीनेट शिक्षा मंवे बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद बनने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।
- पीएम नरेन्द्र मोदी 14 खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी दी।
- कनाडा की संसद ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के सम्मान में मौन रखा।
- आस्ट्रेलिया के आलराउंडर मार्कस स्टोइलिस मौजूदा टी-20 विश्वकप में आलाराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया।

21 जून

- विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल पर संगलदान से रियासी तक मेमू ट्रेन का पहली बार संचालन शुरू हुआ।
- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दशम संस्करण पर देशभर में 21 जून को योग दिवस मनाया गया।
- श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघ ने भारत की मदद से तैयार योजनाओं का विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी में किया उद्घाटन
- अमेरिका के अलास्का प्रांत में एक विमान दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई।

उप्र और महाराष्ट्र ने रोका भाजपा का रथ

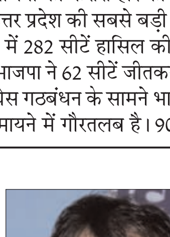

प्रो. रविकांत

बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति भावुक और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दलितों ने भाजपा को हराने में बड़ी भूमिका अदा की। अम्बेडकरवादी वैचारिक पृष्ठभूमि होने के कारण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दलितों ने एकजुट होकर भाजपा और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान बदलने के मंसूबों पर ताला लगा दिया और यह संकेत दे दिया है कि आने वाले वक्त में भी जब इस तरह की हिमाकत होगी तो दलित समाज अपने निजी हितों को छोड़कर हिंदुत्ववादियों को रोकने के लिए अपने मताधिकार का ही प्रयोग नहीं करेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहेगा।

2024 की लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से रोकने में दो राज्यों की सबसे बड़ी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े राज्य हैं। दोनों ही राज्य हिंदुत्व की प्रयोगशाला माने जाते हैं। दोनों राज्यों में लंबे समय से भाजपा सत्ता में है। इन राज्यों में भाजपा का अनेक छोटे-बड़े सहयोगी दलों के साथ गठबंधन भी है। महाराष्ट्र में भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार में है। जून 2022 में उद्धव ठाकरे की महा विकास अघाड़ी की सरकार को गिराकर भाजपा ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे से बगावत करके एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर कब्जा कर लिया। ठीक इसी तरह भतीजे अजित पवार ने दो तिहाई से ज्यादा विधायक तोड़कर चाचा शरद पवार की एनसीपी पर कब्जा कर लिया। जाहिर तौर पर यह तोड़फोड़ केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हुई थी। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनाने के पीछे असली मकसद लोकसभा चुनाव था। लेकिन महाराष्ट्र की 48 सीटों में से केवल 17 पर महायुति गठबंधन जीत सका। इसमें 9 पर भाजपा, 7 पर शिवसेना और 1 पर एनसीपी ने जीत हासिल की। इसके बरक्स उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर 30 सीटों पर जीत हासिल की। आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस को सर्वाधिक 13, शिवसेना (यूबीटी) को 9 और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) को 8 सीटें मिलीं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए पार्टियों को तोड़कर और तमाम सामाजिक समीकरण साधकर भी महाराष्ट्र में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा।

2014 में भाजपा की जीत में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका थी। यूपी की 80 सीटों में से 71 सीटें जीतकर भाजपा ने पूरे देश में 282 सीटें हासिल की थीं। इसके बाद 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के सामने भी भाजपा ने 62 सीटें जीतकर 303 सीटों का बड़ा बहुमत हासिल किया। 2024 के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के सामने भाजपा केवल 33 सीटों पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार कई मायने में गौरतलब है। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश भाजपा के हिंदुत्व का केंद्र बना। भाजपा के उभार में राम मंदिर आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। बाबरी मस्जिद तोड़कर (6 दिसम्बर, 1992) भाजपा और संघ ने जिस राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया था, वह इस साल बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को हुए उद्घाटन के समय पूरे देश को भगवा झंडों से पाठ दिया गया। गोरखपुर मठ के महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ की छवि उग्र हिंदुत्ववादी नेता की है। यूपी में कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया। गुंडे खत्म करने के नाम पर सैकड़ों छोटे-मोटे अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया गया। इनमें भी ज्यादातर मुस्लिम थे। ईद, मुहर्रम और बकरीद पर मुसलमानों को सख्त हिदायतें दी जाती हैं, जबकि हिंदू त्योहारों पर नौजवान हिंदुओं को धर्म की अफीम चटाकर मस्जिदों के सामने डीजे बजाने और समुदाय विशेष को अपमानित करने का पूरा मौका मिलता है। इनमें अधिकतर पिछड़े और दलित नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब यही नौजवान नौकरी मांगते हैं या समुचित आरक्षण लागू करने की मांग करते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती हैं। इस व्यवस्था को गोदी मीडिया की भाषा में राम राज्य कहा जाता है।

उत्तर प्रदेश राम मंदिर आंदोलन की ही नहीं बल्कि मान्यवर कांशीराम की बहुजन आंदोलन की भी जमीन है। सांप्रदायिक उग्रता और सामाजिक विभाजन के बावजूद भाजपा कभी नितांत हिंदुत्व के बलबूते चुनाव नहीं जीत सकी। भाजपा ने दलित पिछड़ा कार्ड खेला। गैर जाटव दलित और गैर यादव पिछड़ों में जाटवों और यादवों के खिलाफ नफरत पैदा करके भाजपा मजबूत जनाधार बनाने में कामयाब हुई। इसके बावजूद उसने समय-समय पर अनेक छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। इस चुनाव में भी मोदी और योगी को अपशब्द कहने वाले ओमप्रकाश राजभर से भाजपा ने गठबंधन किया। राम का अपमान करने वाले संजय निषाद को साथ लिया। कांशीराम के साथी रहे सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल के अपना दल के साथ भी भाजपा ने गठबंधन किया। इतने प्रयोग और आक्रामक प्रचार के बावजूद भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा।

सामाजिक समीकरण, कट्टर हिंदुत्व और पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद भाजपा को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में क्यों पराजय मिली? दरअसल, विपक्षी इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार में संविधान और लोकतंत्र बचाने का मुद्दा जोर-जोर से उठाया। कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय, आरक्षण, समान प्रतिनिधित्व और सम्मान देने का वादा किया। नतीजे जाहिर करते हैं कि विपक्ष के इस एजेंडे का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। इन दो राज्यों ने भाजपा और मोदी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े सूबे हैं। करीब एक चौथाई सीटें इन राज्यों से आती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 और महाराष्ट्र की 48 यानी कुल मिलाकर 128 सीटों में से भाजपा केवल 50 सीटें जीत सकी। इन प्रदेशों में भाजपा 40 फ़ीसदी सीटें भी जीतने में कामयाब नहीं हुई। नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत से रोकने में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी भूमिका है।

18वीं लोकसभा का यह चुनाव क्यों बेहद खास रहा? आरएसएस की स्थापना के शताब्दी वर्ष में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बेताब नरेंद्र मोदी ने पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। पिछले दो साल से बार-बार संविधान बदलने की बात की जा रही थी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाकर नया संविधान लागू करने के लिए देश में माहौल तैयार किया जा रहा था। विदित है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई और उपराष्ट्रपति जगदीप धनगढ़ ने संसद में मूलभूत ढांचे की वैधता पर पुनर्विचार करने की बात उठाई। जाहिर तौर पर यह सब मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा था। इसी दरमियान 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देवराय ने बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को औपनिवेशिक विरासत का प्रतीक बताते हुए नया संविधान लिखने की वकालत की। यह सिलसिला चुनावी ऐलान के बाद और आगे बढ़ा। अनंत कुमार हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अरुण गोविल और गिरिराज सिंह जैसे बड़बोले भाजपा नेताओं ने संविधान बदलने के लिए 400 सीटें जीतने का दावा किया। यह मुद्दा चुनाव में इतना भारी पड़ जाएगा खुद मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा। गौरतलब है कि संविधान बदलने की बात कतई हवा में नहीं थी। आरएसएस के शताब्दी वर्ष में संघ के प्रचारक से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी अपनी पितृ संस्था की हसरत को पूरा करने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन दो बड़े राज्यों ने उनके मनसूबों पर पानी ही नहीं फेर दिया बल्कि उनकी हैसियत भी बता दी।

इसको समझने की जरूरत है कि आखिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने मोदी के प्रचार की हवा क्यों निकाल दी? दरअसल, महाराष्ट्र बाबासाहेब अंबेडकर की कर्मभूमि है और उत्तर प्रदेश मान्यवर कांशीराम की बहुजन राजनीति की प्रयोगशाला। मोदी सरकार के आने के बाद आरएसएस के साए में हिंदुत्व की राजनीति लगातार परवान चढ़ रही है। हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के लिए अंबेडकरवादी विचारधारा और बुद्धिस्ट संस्कृति के जरिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार जमीनी संघर्ष जारी है। दिवंगत होने के बाद बाबासाहब का जो काम छूट गया था, 2014 के बाद उसमें गति आई है। हिंदुत्व के आक्रमण की प्रतिक्रिया में हिंदू त्योहारों को त्यागकर दलितों ने बहुजन नायकों की जयंतियों को अपना त्यौहार बना लिया। तथागत बुद्ध, कबीर ,रैदास , ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और अंबेडकर दलितों के भगवान बन गए। संविधान उनकी सबसे पवित्र किताब बन गई। इसलिए जब भाजपा ने संविधान बदलने का ऐलान किया तो दलित समाज नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ लामबंद हो गया।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत बहुत मायने रखती है। इन राज्यों में दलित राजनीति की नुमाइंदगी होने के बावजूद दलितों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। बसपा के पास एक मजबूत जनाधार है। लेकिन इस चुनाव में बसपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। दरअसल, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाओं को नकारते करते हुए जब मायावती ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो 21.50 फीसदी दलित समाज बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ चला गया। बसपा का कोर वोटर जाटव समाज के शिक्षित और जागरूक तबके ने मायावती से मुंह मोड़ लिया। कोरी, पासी, धोबी, वाल्मीकि, सोनकर आदि जातियों का बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के साथ हो गया। नतीजे में इंडिया गठबंधन को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। जबकि बसपा किसी सीट पर दूसरे स्थान पर भी नहीं आ सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 19.4 फीसदी वोट हासिल करने वाली बसपा का वोट घटकर 9.39 फीसदी यानी करीब आधा रह गया। इसी तरह महाराष्ट्र में बहुजन वंचित अघाड़ी की मौजूदगी के बावजूद दलित मतदाता कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ चला गया। महाराष्ट्र में 11 से 12 फीसदी दलित आबादी है। इसमें आधी आबादी महारों की है। बाबा साहब अंबेडकर भी महार थे। उनके आह्वान पर महारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बुद्धिस्ट बने महार सुशिक्षित और संपन्न हैं। बाबा साहब के पोते प्रकाश आंबेडकर की बहुजन वंचित अघाड़ी मूल रूप से महारों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले भी महार राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वह आजकल भाजपा के साथ हैं। महारों के अतिरिक्त महाराष्ट्र में मांग, कोरी, खटीक, मातंग, ढेड़, चमार, ढोर, डोम, औलख और गोतराज आदि दलित जातियां हैं। आमतौर पर ये जातियां राजनीतिक रूप से महारों के प्रतिरोध में खड़ी होती हैं। लेकिन संविधान बदलने की मुनादी के कारण पूरा दलित समाज भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ लामबंद हो गया। महारों ने इस चुनाव में प्रकाश अम्बेडकर को भी छोड़ दिया। 38 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बहुजन वंचित अघाड़ी को केवल 15 लाख 67 हजार वोट मिले। अकोला और हिंगोली को छोड़कर शेष सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। खुद प्रकाश अम्बेडकर अकोला सीट पर तीसरे स्थान पर रहे।

बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति भावुक और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दलितों ने भाजपा को हराने में बड़ी भूमिका अदा की। अम्बेडकरवादी वैचारिक पृष्ठभूमि होने के कारण उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के दलितों ने एकजुट होकर भाजपा और आरएसएस के हिंदू राष्ट्र बनाने और संविधान बदलने के मंसूबों पर ताला लगा दिया और यह संकेत दे दिया है कि आने वाले वक्त में भी जब इस तरह की हिमाकत होगी तो दलित समाज अपने निजी हितों को छोड़कर हिंदुत्ववादियों को रोकने के लिए अपने मताधिकार का ही प्रयोग नहीं करेगा अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर संघर्ष करने के लिए भी तैयार रहेगा। उनका इतिहास कैसा भी रहा हो लेकिन दलित समाज अपनी औलादों के मुस्तकबिल को हिंदुत्ववाद के नाम पर ब्राह्मणवाद की गुलामी में नहीं जाने देगा। उन्हें बाबा साहब का यह संदेश याद है कि लोकतांत्रिक तरीके से ही अन्याय और असमानता का समाधान ढूंढना होगा। संविधान और बाबा साहब ने मताधिकार दिया है। उसी के द्वारा संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने और जीतने का सबक दलित समाज ने आज पूरे देश को दे दिया है।

मोदी पर आरएसएस का छुपा वार

जगदीश रत्तनानी

कई ऐसे लोग हैं जो इसमें आरएसएस का दोमुंहापन देखते है और जो मानते हैं कि संघ भाजपा का वैचारिक अभिभावक है एवं उसे उन सभी ज्यादतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो हमने मोदी-युग के दौरान देखी हैं। आखिरकार मोदी आरएसएस की विचारधारा के विद्यार्थी हैं और वे वही ढोल बजा रहे हैं जो संगठन ने उन्हें सिखाया है। बाकी सब जो हो रहा है वह आरएसएस की छत्रछाया में नूरा कुश्ती है और नियंत्रण का अस्थायी बदलाव है।

इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि 2024 के चुनावों पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का भाषण सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा करता है। यह कहा जाता है कि भागवत ने उनकी निंदा किए या उनका नाम लिए बिना सब कुछ कह दिया है और अपने इच्छित लक्ष्य के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि चुनाव युद्ध नहीं है, दोनों पक्षों को सुनने के लिए एक दृष्टिकोण है और सच यह है कि सेवक वह है जो मर्यादा में रहकर और अहंकार के बिना सेवा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर में मुद्दों को एक साल से अधिक समय से उपेक्षित किया गया है। समझदारी का इशारा देने वाले इन शब्दों को और किसकी ओर निर्देशित किया जा सकता है? भागवत के बयान के बाद इसे व्यापक रूप से मोदी विरोधी वक्तव्य के रूप में देखे जाने के बाद अज्ञात स्रोतों के माध्यम से संघ ने यह स्पष्ट करना उचित समझा है कि वह उस व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई इरादा नहीं रखता है जिसने अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।

कई ऐसे लोग हैं जो इसमें आरएसएस का दोमुंहापन देखते है और जो मानते हैं कि संघ भाजपा का वैचारिक अभिभावक है एवं उसे उन सभी ज्यादतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो हमने मोदी-युग के दौरान देखी हैं। आखिरकार मोदी आरएसएस की विचारधारा के विद्यार्थी हैं और वे वही ढोल बजा रहे हैं जो संगठन ने उन्हें सिखाया है। बाकी सब जो हो रहा है वह आरएसएस की छत्रछाया में नूरा कुश्ती है और नियंत्रण का अस्थायी बदलाव है। फिर भी यह विचार है कि आरएसएस के हालिया बयानों में कुछ और भी है, खासकर जब वे भाजपा के चुनावी हार के मद्देनजर आते हैं। इसमें आंशिक रूप से निर्मित और जल्दबाजी में उद्घाटित राम मंदिर के निर्वाचन क्षेत्र में सीट खोना भी शामिल है।

यह देखते हुए कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के हाथों में सिमट गई है और अपने दम पर सोच नहीं सकती है तो इन हालातों में यह चुनाव आरएसएस में कुछ वास्तविक पुनर्विचार के लिए ट्रिगर हो सकते हैं। आज यह आरएसएस की उस दुविधा को सामने ला रहा है कि इसके एजेंडा को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया है, संघ एक ऐसी सरकार से शक्ति और संसाधन प्राप्त कर सकता है जो अब एक दशक से अधिक समय से पूर्ण नियंत्रण में है लेकिन ऐसा लगता है कि यह उस तौर तरीके को नापसंद कर रहा है जिसे इस प्रक्रिया में मोदी ने अपने चारों ओर बनाया है।

दूसरे शब्दों में कहें तो आरएसएस के नजरिए से नीतियां 'अच्छी' हैं लेकिन उन्हें व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति सही नहीं है। संघ के द्वितीय सरसंघचालक एमएस गोलवलकर ने एक बार कहा था कि- आरएसएस कार्यकर्ता की 'असाधारणता' ठीक ऐसी होनी चाहिए कि हर कार्यकर्ता खुद को 'साधारण' माने। आज आरएसएस को भाजपा के एक ऐसे प्रधानमंत्री से जूझना होगा जो खुद को इश्वर का भेजा हुआ और गैर-जैविक अवतार बताते हुए स्वयं को प्रधान सेवक कहता है और जो यह कहते नहीं थकता कि वह कितना असाधारण है।

आरएसएस के नजरिए से यह सरल सवाल है कि क्या आपके काम करने के भुगतान की यह बहुत अधिक कीमत है या क्या ऐसा नहीं है? क्या यह आरएसएस की वर्षों पुरानी इच्छाओं के सच होने का स्वर्णिम काल है जिसमें अयोध्या का राम मंदिर, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना, अधिकांश राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध, नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) का एजेंडा, समान नागरिक संहिता की ओर कदम, ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध आदि शामिल है या ये उस सड़ी हुई संस्कृति के 'उपहार' हैं जो एक ऐसी पार्टी में अंतर्निहित हो गई है जिसने हमें चुनावी बांडों में देखा गया भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा, भारत की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट, गैर-भाजपा सरकारों को तोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और यह सब कुछ अगर बढ़ती संपत्ति और आय असमानता को लेकर है जो राष्ट्र की गर्म बहस बनने और बने रहने का वादा करता है? यह आरएसएस को खुश करने के लिए साध्य हैं लेकिन इस साध्य के साधनों के बारे में क्या कहा जाए? आखिरकार अपने स्वयंसेवकों के बीच चरित्र निर्माण करना संघ का घोषित लक्ष्य है। यह लक्ष्य धनबल, ग्लैमर मार्केटिंग और घृणा की भाषा के युग में कैसे साध्य है जिसमें चुनाव अभियान में जहर घोलने के लिए प्रधानमंत्री मटन, मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं?

गांधी ने हमें बताया कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में वे केवल साधनों के बारे में चिंतित थे, उसके अंत के बारे में नहीं। वे कहते हैं कि, 'साधन सभी चीजों से ऊपर हैं। मैं कहूंगा कि साधन सब कुछ के बाद हैं। साधन जैसा है, अंत वैसा ही होगा। मुझे लगता है कि लक्ष्य की दिशा में हमारी प्रगति हमारे साधनों की शुद्धता के सटीक अनुपात में होगी।'

प्रबंधन गुरु स्वर्गीय जैक वेल्च ने प्रबंधकों की उपलब्धियों (परिणाम) और उनके मूल्यों (साधन) को एक सांचे में फिट किया था- कुछ नतीजे देते हैं और मूल्यों का सम्मान करते हैं (उन्होंने कहा कि उन्हें बढ़ावा दें), अन्य न तो परिणाम लाते हैं और न ही मूल्यों का सम्मान करते हैं (उन्हें खारिज कर दीजिये), कुछ अन्य के पास मूल्य हैं लेकिन परिणाम कम हैं (उन्हें समर्थन दें) और अंतिम किस्म, जो किसी भी प्रणाली के लिए सबसे खतरनाक है- वे प्रबंधक जिसके पास कोई मूल्य नहीं है लेकिन तिमाही दर तिमाही आंकड़े पर आंकड़े देते रहते हैं। ये सबसे नुकसानदेह है और सुझाव यह है कि अगर संगठन को जीवित रखना है, उसे पनपने देना है तो यही वे लोग हैं जिसे पहले और तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। फिर भी, यदि सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो यह सबसे कठिन निर्णय हो सकता है। यह ढांचा तब लागू होता है जब अंतिम परिणाम वैध, न्यायसंगत और विवेकसम्मत होते हैं।

एक पल के लिए भूल जाइए कि आरएसएस अपने आप में समाप्त हो जाता है। फिर भी, इन संकरे सिरों के साथ उसने अपने घोषित साधनों के साथ रास्ते पार कर लिए हैं। इसलिए अपने स्वयं के विश्व के भीतर और अपनी संरचनात्मक अखंडता के लिए साधन-साध्य वे प्रश्न हैं जिसका जवाब आरएसएस को देना होगा। इस आलोक में मोहन भागवत के शब्द बेचैनी का संकेत देते हैं, पर मोदी का नाम लेने और उन्हें बाहर निकालने में उनकी हिचकिचाहट इस बात की ओर इशारा करती है कि वह अपने ही बनाए जाल में फंस गया है।

संघ को लाभ भी मिला है। नए और आलीशान दफ्तरों, सरकारी पदों की तो बात ही छोड़िए, अधिकारियों में सम्मानजनक स्वागत, मोहन भागवत के साथ चलने वाले एसपीजी जैसे गार्डों के समूह की भी बात को छोड़िए- यह सब संगठन के ग्लैमर और सत्ता के स्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आप कह सकते हैं कि मोदी सत्ता के नशे में चूर हैं परन्तु भाजपा भी पलट सकती है और कह सकती है कि आज आरएसएस भी उसी गिलास से सत्ता का नशा पी रहा है!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंडिकेट : द बिलियन प्रेस)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

संपादकीय

मापदंड बदलने से सत्य नहीं बदल जाता

ऐसा कैसे संभव है कि जब सब्जी, दूध, दाल, अनाज, तेल और रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान पर हों और लगातार बढ़ रहे हों, तब खुदरा महंगाई पिछले साल भर के मुकाबले सबसे कम हो। पता चला कि सरकार ने पैमाना ही बदल डाला। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खुदरा खर्च के सामान की सूची में खाद्यान्न के अलावा रिहाइश, परिधान, ट्रांसपोर्ट, चिकित्सा व मनोरंजन, शिक्षा और तमाम तरह की सेवाएं हैं। इनमें खाद्यान्न भार, जो पहले 46% था, घटा कर 39% कर दिया। खाद्यान्न की महंगाई अपने शबाब पर (17%) है, इसमें भी रोजाना के खाने-पीने वाले चीजें जैसे प्याज, आलू और दाल के दाम क्रमशः 55, 44 और 27% बढ़े हैं। गरीब या निम्न मध्यम वर्ग (जो 70% से ज्यादा है) का व्यक्ति न तो मनोरंजन करता है ना ही पेट्रोल खरीदता है। उसकी आय का 70 फीसदी खर्च खाने पर होता है। लिहाजा पेट्रोल या ट्रांसपोर्ट या फीस में वृद्धि उसे उतना नहीं सताती, जितना सब्जियों या तेल का महंगा होना। जनमत से बनी सरकार के लिए ऐसी महंगाई जनाक्रोश पैदा करती है लिहाजा वह निर्यात रोक पर अंकुश लगाती है, लेकिन इससे किसान की आय घटती है। सरकार को बेहतर पैदावार के लिए किसानों को वैज्ञानिक खेती की ओर ले जाना होगा और सिंचाई के भी नए तरीके अपनाने के लिए तत्पर करना होगा।

प्रेरणा

छोटी-छोटी बातों में विश्वास रखें क्योंकि इनमें ही आपकी शक्ति निहित है। यही आगे ले जाती हैं। **- मदर टेरेसा**

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

मंदिरों में व्यवस्थाओं को गंभीरता से लेना चाहिए

अब भारत में एक नई समस्या तेजी से उजागर होगी और समय पर नहीं संभाला तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये समस्या है धार्मिक शहरों का भीड़ प्रबंधन, क्योंकि जो भीड़ उस शहर के प्रतिष्ठित मंदिर में पहुंचती है, वो पहुंचने के पहले और दर्शन के बाद उस शहर को नापती है। और अधिकांश धार्मिक शहरों में प्रशासन यातायात, आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य के मामले में सोया हुआ है। कई नौकरशाहों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसका करें क्या। राजनेता का काम है, प्रचार-प्रसार करना और भीड़ देख कर तो कौन बावला नहीं होता। लेकिन इसे अभी से व्यवस्थित करना होगा। धार्मिक शहरों के प्रबंधन से जुड़े लोगों का मानना है कि भक्तों की भीड़ में कोई अक्ल होती नहीं है, जैसे चाहे वैसे हांक दो। अस्थाई और क्षणिक आवेश व्यक्त करेंगे, लेकिन अपने धर्म-कर्म में डूबे रहेंगे। और भक्तों की भीड़ का मानना है कि हमारे साथ चाहे जो हो जाए, बस दर्शन हो जाएं। लेकिन यह भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। व्यवस्थाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नजरिया • समस्याओं के समाधान पर नहीं है ध्यान...

आरोप-प्रत्यारोप के दुष्चक्र में फंस चुकी है देश की राजनीति

पवन के. वर्मा
लेखक, राजनयिक,
पूर्व राज्यसभा सांसद
pavankvarma1953@gmail.com

लोकतंत्र में मेरा भरोसा पुख्ता है, लेकिन क्या हमारे देश में लोकतंत्र सुशासन के विपरीत हो गया है? हमारे यहां जितनी मर्तबा चुनाव होते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जैसी कटुता दिखाई देती है, उसके मद्देनजर क्या हम आम जनता की वास्तविक जरूरतों को हल करने के लिए संयुक्त कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? आरोप-प्रत्यारोप का लगातार चलने वाला खेल और अगले विधानसभा चुनाव को जीतने की होड़ के बीच यह एक दूर की संभावना बनकर रह जाती है।

एक लोकतंत्र में अंदरूनी टकराहटों के बावजूद शासन-व्यवस्था सुचारु होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय चुनावों के बाद भी राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी रखते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद भाजपा कमजोर हुई है और विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। ऐसे में उनके बीच अप्रिय टकराव के कारण आगामी संसदीय सत्र के ठप होने का अंदेशा है। वहीं दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाले देश की राजधानी में लाखों लोग पानी जैसी बुनियादी चीज की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गर्मी के दौरान पानी के टैंकर के पीछे भागती भीड़ के भयावह दृश्य लगातार दिखाई देते रहे। उधर राजनेता इस पर चर्चा करने में व्यस्त हैं कि राहुल गांधी को वायनाड या रायबरेली में से किसे चुनना चाहिए था या मोहन भागवत के भाषणों में क्या संकेत निहित थे।

आरोप-प्रत्यारोप के अंतहीन प्रहसन से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाकर पानी की कमी का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भाजपा पर जानबूझकर इस संकट को बढ़ाने का आरोप लगा रही है। लेकिन न तो वो दोनों, न ही दूसरे राजनीतिक दल इस राष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधानों पर रचनात्मक चर्चा के लिए सहमत हो रहे हैं। महाराष्ट्र में पानी की कमी के कारण सूखे का खतरा मंडरा रहा है। असहाय किसान और ग्रामीण समुदाय हर कुएं की तलहटी तक छान चुके हैं। लेकिन राज्यों के नेता आगामी विधानसभा चुनावों की योजना बनाने में व्यस्त हैं।

हर मुद्दे पर दोषारोपण की निरर्थक होड़ हावी है। अगर कोई रेल दुर्घटना होती है- जैसा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुआ- तो विपक्ष भाजपा पर और भाजपा विपक्ष पर हमला बोलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन रेलवे सुरक्षा की समग्र स्थिति या वंदे भारत के अलावा आमजनों की अन्य रेलगाड़ियों की दयनीय स्थिति के बारे में संयुक्त रूप से विचार-विमर्श नहीं किया जाता। देवगौड़ा के पोते रेवन्ना और उन पर लगे यौन शोषण के कथित आरोपों या वाराणसी लोकसभा सीट पर पीएम मोदी की जीत के घटते अंतर को लेकर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन क्या हमारे राजनेता वास्तव में राष्ट्रीय राजधानी सहित पूरे देश में बढ़ती बिजली कटौती के बारे में चिंतित हैं?

चुनावी प्राथमिकताओं को देखते हुए मुफ्त सौगातों के वादे चलन में हैं। फिर भले उन्हें वास्तव में पूरा किया जाए या नहीं। लगभग 80 करोड़ लोग केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले मासिक राशन पर जीवित हैं, जिसे कोविड के दौरान एक अस्थायी समाधान माना गया था। लेकिन आज किसी भी राजनीतिक दल के पास मुफ्त सौगातों को जारी रखने से परे कोई विजन नहीं दिखाई देता है कि वे मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान खोज सकें। बड़े पैमाने पर ग्रामीण समस्याओं और घटती कृषि उत्पादकता से कैसे निपटें? अधिक नौकरियां कैसे पैदा करें? युवाओं को बेहतर कौशल कैसे प्रदान करें? प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को कैसे सुधारें? आर्थिक विषमता और महंगाई को कैसे पाटें? उन लाखों युवाओं के लिए क्या करें, जिनका भविष्य बार-बार पेपर लीक होने और विसंगतिपूर्ण परीक्षा प्रणाली के कारण खतरे में पड़ जाता है?

एक बड़े बदलाव की जरूरत है। हमारी राजनीति का तरीका ही आज शासन-प्रशासन की गुणवत्ता में बाधा बनकर रह गया है। लोगों का धैर्य चुक रहा है। आखिरकार, उन्हें ही तय करना होगा कि कब यह कह बैठें : 'बस, बहुत हुआ!'

मानसून सिर पर हैं और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे व्यापक पैमाने पर लोगों की परेशानी बढ़ेगी। लेकिन इनमें से कोई भी बात लुटियंस-दिल्ली को प्रभावित नहीं करती, जहां नीति-निर्माता रहते हैं। साल के अंत में, हमें फिर से प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हर साल की इस समस्या का कोई व्यवस्थित समाधान नहीं दिख रहा है। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे और नागरिक अदूरदर्शी राजनीति के शिकार होंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस आलेख पर सुझाव एवं प्रतिक्रिया देने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

विश्लेषण • तीन नए आपराधिक कानूनों पर दुविधा

नए सिरे से चर्चा और बहस से ही दूर हो सकेगा गतिरोध

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील, 'अनमास्किंग वीआईपी' पुस्तक के लेखक
viraggupta@hotmail.com

तीन नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से लागू करने पर सरकार के सामने दुविधा की स्थिति है। संविधान की समवर्ती सूची से जुड़े इन कानूनों को जोर-जबर्दस्ती से राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। कृषि कानून की तरह ये कानून सरकार के गले की हड्डी नहीं बनें, उसके लिए 6 पहलुओं की पड़ताल जरूरी है।

1. इतिहास में नाम दर्ज कराने की हड़बड़ी : चुनावों के पहले आनन-फानन में कानूनों को पारित करने के पीछे इतिहास में नाम दर्ज कराने का भाव ज्यादा प्रबल था। विपक्ष के अनुसार ये कानून संसद के सामूहिक विवेक को प्रतिबिंबित नहीं करते। डाटा सुरक्षा नियम, डिजिटल इंडिया और ई-कॉम्पीटिशन जैसे अनेक बिलों पर कई सालों से विदेशी कंपनियों से विमर्श हो रहा है। तो फिर आपराधिक कानूनों पर वकील, पुलिस, जज, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जैसे स्टेकहोल्डर के साथ पर्याप्त और पारदर्शी सहमति क्यों नहीं ली गई? गतिरोध दूर करने के लिए संसद में इन कानूनों पर नए सिरे से बहस होनी चाहिए।

2. कैदियों की रिहाई : चुनाव के पहले यह खबर उड़ाई गई कि नए कानूनों को गणतंत्र दिवस में लागू करके 82 हजार कैदियों की रिहाई की जाएगी। हकीकत यह है कि कैदियों की रिहाई और वर्तमान मुकदमों का ट्रायल पुराने कानूनों के अनुसार ही होगा। कैदियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार, जेल प्रशासन और अदालतों का महत्वपूर्ण सहयोग चाहिए। चुनावों के पहले नए कानूनों को ट्रायल बेसिस पर केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की बात भी कही गई थी। लेकिन अलग-अलग राज्यों में दो तरह के क्रिमिनल कानून लागू करने से संवैधानिक संकट की स्थिति बन सकती थी।

3. अन्य कानूनों में बदलाव : ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद 'हिट एंड रन' प्रावधानों में रोक पर सरकार सहमत हो गई थी। दहेज उत्पीड़न के 498-ए प्रावधान को बीएनएस की नई धाराओं में शब्दशः शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। नए कानूनों के अनुसार पीएमएलए, पॉक्सो, एससी/एसटी, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे कई कानूनों में बदलाव नहीं होने पर अपराधियों की मौज बढ़ सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के अनुसार हिंदी या संस्कृत में कानूनों का नाम संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन है। इस बारे में कुछ हाईकोर्ट जजों ने भी अनावश्यक टिप्पणी की है। अगर ये तर्क सही माने जाएं तो 'यतो धर्मस्ततो जयः' और 'सत्यमेव जयते' जैसे ध्येय वाक्यों को भी सुप्रीम कोर्ट और सरकारी दस्तावेजों से हटाना पड़ सकता है।

4. नई बोतल में पुरानी शराब : नए कानूनों में तीन-चौथाई से ज्यादा पुराना मसाला है। नएपन के चक्कर में पुरानी धाराओं का क्रम बेवजह बदलने से वकील, पुलिस और जज भ्रमित हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। इनमें ऑनलाइन एफआईआर के साथ छोटे अपराधों के जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल का प्रावधान है। सनद रहे कि नए कानून बनने से पहले ही 8 करोड़ एफआईआर ऑनलाइन तरीके से हो चुकी हैं। गिरफ्तारी, जांच, आरोप-पत्र, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति, ट्रायल, जमानत, फैसला और सजा के लिए नए कानून में समय-सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए स्पष्ट रोडमैप नहीं है। कानून में भारतीय नामों के साथ जल्द न्याय के अधिकार को लागू करने पर ही तारीख पे तारीख के मर्ज से मुक्ति मिलेगी।

5. राज्यों का सहयोग जरूरी : राज्यों से इन्फ्रा और कोर्ट रूम नहीं मिलने की वजह से जिला अदालतों में लगभग 5850 जजों के पद खाली हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की गाड़ी भी हाईकोर्ट और राज्य सरकारों की वजह से अटकी है। गुजरात के फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का सभी राज्यों में परिसर बनाने के लिए अगले पांच साल में गृह मंत्रालय ने लगभग 2254 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। लेकिन इनके शुरू होने में समय लगेगा। लगभग 17,389 पुलिस थानों में से 16,733 थाने सीसीटीएनएस नेटवर्क से जुड़े हैं। नए कानून के अनुसार एफआईआर के फॉर्मेट में एकरूपता के साथ सॉफ्टवेयर में बदलाव की जरूरत है।

गलत गिरफ्तारी पर पुलिस की जवाबदेही हो। बेवजह मुकदमा दायर करने वालों के खिलाफ सख्त जुर्माना लगे। निर्दोष कैदियों को मुआवजा मिले। इन्हें हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मुकदमा नीति पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है।

6. राष्ट्रीय मुकदमा नीति : 'न्यायमूलं स्वराज्यं स्यात्' के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता और स्वशासन का मूल है। लेकिन 'दागो और भागो' रवैए की वजह से अधकचरे सुधारों की गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही पंक्चर हो जाती है। अदालतों में लगभग 5.13 करोड़ लंबित मुकदमों में से 3.59 करोड़ यानी 69.9 फीसदी आपराधिक मामले हैं। इन्हें हासिल करने के लिए नए आपराधिक कानून से ज्यादा राष्ट्रीय मुकदमा नीति पर सख्ती से अमल जरूरी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

The Economist | 22 जून के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में | इकोनॉमिस्ट ने सोलर एनर्जी के बढ़ते उपयोग और चीन में वैभव प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई पर फोकस किया है। | दैनिक भास्कर | अब आप द इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

बिजनेस ब्रीफ

बोइंग विमानों में खराब पुर्जे लगाने की शिकायत

बोइंग के सीइओ डेव कैलहाउन से अमेरिकी सीनेटर्स ने कंपनी के विमानों से संबंधित दुर्घटनाओं के बारे में सवाल किए हैं। कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड ब्लूमेंथल ने बोइंग को आईकॉनिक कंपनी बताने के साथ कहा कि वह रास्ता भटक गई है। इस्तीफा दे रहे कैलहाउन ने दुर्घटनाओं के लिए माफी मांगी है। इस बीच एक व्हिसल ब्लोअर ने शिकायत की है कि बोइंग विमानों में कुछ खराब पुर्जे लगाए गए हैं। बोइंग के शेयर मूल्य इस साल 30% गिरे हैं।

स्टडी : एआई से जॉब कम होंगे और असमानता बढ़ेगी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक स्टडी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े पैमाने पर तेज गति से हो रहे बदलाव से जॉब तेजी से कम होंगे, राष्ट्रीय आय में वर्करों की आय घटेगी और असमानता में बढ़ोतरी होगी। कोष ने सरकारों से इस बदलाव के कारण वर्करों पर पड़ने वाले बोझ से निपटने के लिए सामाजिक सिस्टम तैयार करने की अपील की है।

टोयोटा चेयरमैन के लिए समर्थन में गिरावट आई

जापानी कार कंपनी टोयोटा के चेयरमैन पद पर टोयोडा अकिओ की पुनर्नियुक्ति का 72% शेयरहोल्डरों ने समर्थन किया है। यह पिछले साल के 85% से कम है। दो बड़े प्रॉक्सी सलाहकारों ने टोयोडा के खिलाफ वोट करने की सिफारिश की थी। उन पर कुछ वाहनों के सही सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पर ध्यान न देने का आरोप है। यह जापान के कॉरपोरेट जगत में विद्रोह की दुर्लभ मिसाल है।

प्रतिस्पर्धा की रैंकिंग में सिंगापुर टॉप पर लौटा

बिजनेस स्कूल आईएमडी की प्रतिस्पर्धा की सालाना रैंकिंग में 67 देशों के बीच सिंगापुर की टॉप पर वापसी हो गई है। सिंगापुर पिछली बार 2020 में टॉप पर था। स्विटजरलैंड दूसरे और पिछले साल का चैम्पियन डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहे। अमेरिका तीन स्थान नीचे गिरकर बारहवें नंबर पर आ गया है। चीन सात पायदान चढ़कर 14 वें स्थान पर है। वेनेजुएला अंतिम स्थान पर रहा।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

2040 तक दुनिया की पूरी बिजली सोलर एनर्जी से आएगी; इस साल 41 लाख करोड़ रुपए का निवेश

टेक्नोलॉजी

हर तीन साल में सोलर क्षमता दोगुनी हो रही, दुनिया में कहीं भी बिजली की कमी नहीं रहेगी

एटीएंडटी बैल लैब ने सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने की नई टेक्नोलॉजी 70 साल पहले पेश की थी। फोन कंपनी को उम्मीद थी कि यह हर जगह उपकरण चलाने के लिए बैटरियों की जगह ले लेगी। उस समय टेक्नोलॉजी की घोषणा करने वाली प्रेस कांफ्रेंस में दिखाया गया कि किस तरह सूरज का प्रकाश टॉय फैरिस व्हील को घुमा सकता है। आज सोलर पावर से बिजली के उत्पादन में तेजी आई है। इस साल सोलर पैनल दुनिया की 6% बिजली मुहैया कराएंगे। हर तीन साल में सोलर की स्थापित क्षमता दोगुनी और दस साल में दस गुना बढ़ रही है। दस साल पहले सोलर पावर मौजूदा क्षमता का दसवां हिस्सा थी तब तक विशेषज्ञ उसे कम आंकते थे।

धरती पर 2035 तक सोलर पैनल बिजली का सबसे बड़ा स्रोत होंगे। 2040 तक वे न केवल बिजली बल्कि पूरी एनर्जी के सबसे बड़े स्रोत हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इस साल सोलर पावर पर 41.77 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोलर पैनलों से पैदा होने वाली बिजली की लागत आज उपलब्ध सबसे सस्ती बिजली से आधी से भी कम होगी। इससे जलवायु परिवर्तन की गति धीमी पड़ेगी।

ऊर्जा के अन्य स्रोतों के मुकाबले सोलर बिजली सस्ती होती जाएगी। वैसे, कुछ अन्य मुश्किलें तो हैं। सोलर पावर को स्टोर करना पड़ेगा। हैवी इंडस्ट्री, एविएशन और माल ढुलाई में दिक्कत आएगी। सौभाग्य से इन समस्याओं को बैटरियों और इलेक्ट्रोलिसिस से तैयार ईंधन से सुलझाया जा सकता है। एक अन्य चिंताजनक तथ्य है कि विश्व के ज्यादातर सोलर पैनल चीन में बनते हैं। उसकी सोलर इंडस्ट्री को सरकार से भारी मदद मिलती है। वह वर्तमान मांग से अधिक पैनल बना रहा है। चीन ने सोलर पावर की बहुत बड़ी क्षमता का निर्माण कर लिया है। उसकी कुछ कंपनियों के बंद होने और निवेश कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी सोलर पावर के मूल्यों को उस तरह प्रभावित नहीं कर सकेगी जैसे ओपेक देश तेल मूल्यों को करते हैं।

सस्ती ऊर्जा से दुनिया बदल जाएगी। इस सप्ताह दुनिया के उत्तरी गोलार्द्ध (नार्दर्न हेमिस्फीयर-एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका के देश) में ग्रीष्म संक्रांति (समर सोलास्टिस) है। इस वक्त सूर्य आकाश में अपने उच्चतम स्तर पर होगा। कुछ दशकों बाद वह पूरी दुनिया को रोशन करेगा जहां कोई भी बिजली के बिना नहीं रहेगा।

इस साल विश्व में 70 अरब सोलर पैनल बनेंगे

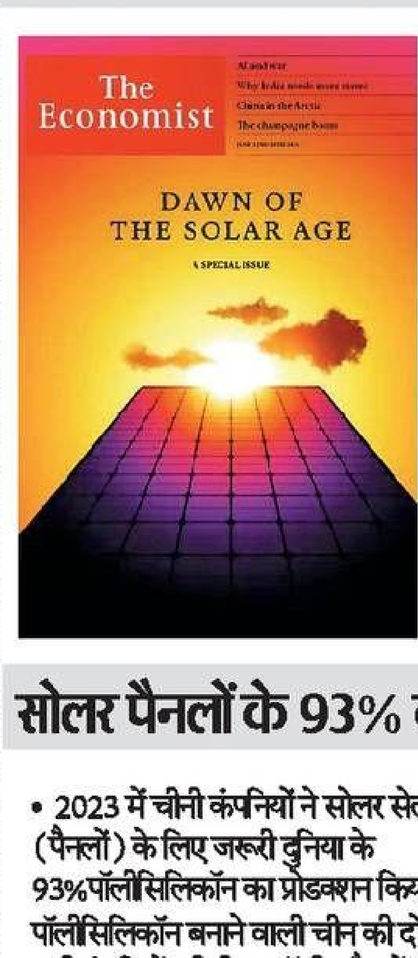

- इस साल विश्व में लगभग 70 अरब सोलर सेल्स (पैनल) बनेंगे। इनमें से अधिकतर का प्रोडक्शन चीन में होगा। 2023 में सोलर पैनलों से 1600 टेरावॉट बिजली पैदा हुई (एक टेरावॉट या एक खरब वॉट)।
- क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ माइकेल लाईब्रीच बताते हैं, 2004 में दुनिया को एक गीगावॉट (एक गीगावॉट बराबर एक अरब वॉट या एक टेरावॉट का दसवां हिस्सा)सोलर पावर क्षमता बनाने में एक वर्ष, 2010 में एक माह, 2016 में एक सप्ताह लगता था। 2023 में एक दिन लगा।
- 2026 तक सोलर पावर से दुनिया के सभी परमाणु रिएक्टरों से ज्यादा बिजली बनने लगेगी। यह 2027 तक विंड टरबाइंस, 2028 तक पनबिजली, 2030 तक गैस से चलने वाले प्लांट और 2032 तक कोयला प्लांटों से अधिक बिजली बनाने लगेगा।

सोलर पैनलों के 93% कच्चे माल का प्रोडक्शन चीन में

- 2023 में चीनी कंपनियों ने सोलर सेल्स (पैनलों) के लिए जरूरी दुनिया के 93%पॉलीसिलिकॉन का प्रोडक्शन किया था। पॉलीसिलिकॉन बनाने वाली चीन की दो सबसे बड़ी कंपनियों-जीसीएल पॉली और टोंगवेई की उत्पादन क्षमता तीन लाख 70 हजार टन थी।
- भारत सहित कई देश सोलर पॉवर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात और राजस्थान में सोलर प्लांट लगा रही है। कंपनी पूरा सोलर किट चीन या पूर्व एशियाई कंपनियों से खरीदती है और लगभग 90% पैनल अमेरिका एक्सपोर्ट करती है।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

नई रिसर्च

अमेरिका में गुलामों के कारोबार में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी थी

लंबे समय से इतिहासकार कहते रहे हैं कि गुलामी का व्यापार केवल पुरुषों का काम था। पिछले माह प्रकाशित रिसर्च ने इस धारणा को तोड़ दिया है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्रियों ने न्यू ओरलिएंस के गुलाम मार्केट के डेटा का विश्लेषण कर इस कारोबार में महिलाओं की हिस्सेदारी का पता लगाया है। उन्होंने पाया कि लगभग 30% सौदों में महिलाएं खरीदार या विक्रेता थीं। इनमें 38% महिलाएं भी बेची गईं। जनगणना के रिकॉर्ड से नामों का मिलान करने पर सामने आया कि न केवल अविवाहित या विधवा महिलाएं बल्कि शादीशुदा महिलाएं भी गुलामों के कारोबार में शामिल थीं।

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इतिहासकार स्टीफेनी जोन्स रॉजर्स की रिसर्च से गुलामों के कारोबार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका का खुलासा होता है। मिसेज स्टीफेनी ने विदेशियों के यात्रा विवरणों के आधार पर गुलामों के बाजार में शानदार सिल्क के परिधान और चमकते कीमती आभूषण पहनकर बोली लगाने वाली महिलाओं का जिक्र किया है। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में महिलाओं के लिए गुलामों का कारोबार उनकी आर्थिक आजादी से जुड़ा था। वे गुलामों को पीटती भी थीं।

रिसर्च के अनुसार कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए शादी के बाद अपनी संपत्ति और पैसा छोड़ने के कानून थे। लेकिन गुलामों पर यह कानून लागू नहीं होते थे। दुल्हन अपने गुलामों को अपने नए पति के यहां ले जा सकती थी। अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए पिता उन्हें जन्मदिन और सगाई के मौके पर तोहफे में गुलाम भेंट करते थे। महिलाएं आर्थिक तौर पर आजादी पाने के लिए गुलामों का इस्तेमाल करती थीं। चार्ल्सटन और न्यू ओरलिएंस जैसे शहरों में उन्हें केक, कपड़े बेचने जैसे काम में लगाया जाता था। महिलाएं इससे हुआ मुनाफा चुपचाप अपने पास रख लेती थीं। कुछ महिलाओं ने तो गुलामों के वेश्यालय चला रखे थे। इस पैसे से और ज्यादा गुलाम खरीदे जाते थे। 1860 में अमेरिकी कांग्रेस ने कनफिसकेशन कानून पास किया। इसके तहत सरकार को गुलाम बरामद करने का अधिकार मिल गया था।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com

चीन में अमीरी का दिखावा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई

अभियान

इंटरनेट पर आलीशान चीजों का प्रदर्शन करने वालों पर पाबंदी

चीन के तत्कालीन शीर्ष नेता माओ जेदांग ने अमीरों को प्रताड़ित किया था। लेकिन,उनके उत्तराधिकारी डेंग स्याओपिंग ने बाजारवादी सुधार लागू कर कुछ लोगों को धनवान बनने की छूट दी थी। अब चीन में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं सरकार ने धन-संपत्ति के आलीशान दिखावे के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। सरकार के निशाने पर ऑनलाइन इंफ्लूएंसर ज्यादा हैं। कुछ समय पहले तक युवा पुरुष और महिलाएं अपने लाखों फॉलोअर्स के सामने लग्जरी गुड्स का प्रदर्शन करते थे। पिछले कुछ महीनों में चीन के इंटरनेट रेगुलेटर ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए हैं।

सरकारी कार्रवाई की चपेट में आने वाले सबसे मशहूर लोगों में वांग होंगक्वानसिंग नामक पुरुष हैं। उन्हें चीन की 'किम कर्दाशियां' कहा जाता है। उन्होंने किसी समय कहा था, वे 11 करोड़ रुपए मूल्य के कपड़े, ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान पहने बिना अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलते हैं। मई में सरकारी मीडिया ने बताया कि दर्जनों अन्य इंफ्लूएंसर्स के समान उन्हें भी चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

यह पहला मौका नहीं है जब इंफ्लूएंसर्स को सरकार की टेढ़ी नजर का शिकार होना पड़ा है। 2021 में जब चीन के प्रमुख नेता शी जिनपिंग ने सबके लिए समृद्धि अभियान छेड़ा था तब भी वे निशाने पर थे। बड़ी कंपनियों और संपन्न लोगों से समाज के लिए अधिक धन देने की अपेक्षा की गई थी। चीन के नामी अरबपति जैक मा के खिलाफ कार्रवाई अन्य अरबपतियों के लिए चेतावनी थी।

अमीरों की संख्या में 47 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी

सरकार की कार्रवाई से अमीरों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लंदन की प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रेंक के अनुसार चीन में अब से 2028 तक अमीरों की संख्या में 47% बढ़ोतरी होगी। बड़े मल्टीनेशनल बैंकों का कहना है, वे चीनी क्लाइंट के लिए अपनी वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर लग्जरी ब्रांड अपने बिना बिके स्टॉक के मूल्य कम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण चीनी कंज्यूमर किफायत बरतने लगे हैं।

© 2024 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

कैबिनेट का फैसला

एमएसपी में वृद्धि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी सरकार ने अपने पहले प्रमुख निर्णयों में किसानों को खुश करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य-'एमएसपी' में वृद्धि की घोषणा की है। केन्द्रीय कैबिनेट ने खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार इस निर्णय से सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित व लाभकारी मूल्य मिले ताकि वे खेती में निवेश की बढ़ती कीमत तथा मुद्रास्फीति का सामना कर सकें। हालांकि, अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सभी किसान इसका स्वागत करेंगे या नहीं, पर इससे वास्तव में किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, खरीफ की आम फसल धान की एमएसपी में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसमें आम किस्म के लिए नई कीमत 2,180 रुपये तथा अच्छी किस्म के लिए 2,220 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई है। इसी प्रकार मक्के की एमएसपी में 75 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा कर इसे 2,130 रुपये किया गया है। यह वृद्धि एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसके अंतर्गत चावल और मक्के जैसे अनाजों, मूंग व तूर जैसी दालों तथा सोयाबीन व मूंगफली जैसे तिलहनों को शामिल किया गया है। सरकार इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को एमएसपी बढ़ाने के माध्यम से प्रेरित कर रही है। उसका दावा है कि इससे कृषि निवेशों पर लगभग 50 प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित होगा।

कुछ समय पहले हुए किसान विरोध प्रदर्शनों ने कृषि क्षेत्र के गहरे व्यवस्थागत मुद्दों की ओर संकेत किया था जो केवल मूल्य समर्थन से आगे जाते हैं। कृषि में बढ़ते खर्च, अनुपयुक्त खरीद ढांचे, बढ़ते कर्ज तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। अनेक किसान नाकाफी खरीद व्यवस्थाओं तथा भुगतान में विलम्ब के कारण एमएसपी वृद्धि के लाभों का आंकलन कर रहे हैं। इसके साथ ही बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे निवेशों पर खर्च बढ़ गया है जिसके कारण एमएसपी वृद्धि का शुद्ध लाभ कम हुआ है। फसलें खराब होने तथा बाजार में अनुमान के विपरीत उतार-चढ़ाव के कारण लगातार बढ़ते कर्ज की समस्या ने किसानों की वित्तीय अस्थिरता को और बढ़ा दी है। हालांकि, एमएपी वृद्धि एक सकारात्मक कदम है, पर अकेले यही कृषि क्षेत्र की बहुआयामी समस्याओं के समाधान के लिए काफी नहीं है। किसानों की आजीविका में टिकाऊ बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए समग्र सुधार जरूरी हैं। इसके लिए सरकार को एक समग्र दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए जिसमें कृषि ढांचे को अद्यतन बनाना, कर्ज तक पहुंच बढ़ाना तथा फसलें खराब होने पर बीमा कवरेज दिलाना शामिल हैं। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने तथा बाजार तक पहुंच बढ़ाने से भी किसानों की कीमतों के उतार-चढ़ाव से पैदा जोखिम कम होगी तथा कुछ प्रमुख फसलों पर उनकी निर्भरता भी घटेगी। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए खरीद व्यवस्थाओं को मजबूत करने तथा उचित कीमतें एमएसपी को उपयुक्त प्रभावी बना सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट द्वारा 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि हालांकि नाकाफी है, पर यह एक स्वागत योग्य कदम है जिससे कृषि क्षेत्र की गंभीर चुनौतियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता स्पष्ट होती है। उचित मूल्य व्यवस्थाओं के साथ ही व्यवस्थित सुधार क्रियान्वित करना भी जरूरी है। इससे भारत के किसानों तथा कृषि क्षेत्र की समग्र वृद्धि सुनिश्चित होगी।

महिलाओं पर बेगारी का बोझ

वैश्विक रूप से महिलायें काफी समय बिना भुगतान वाले देखभाल का काम करती हैं। इससे श्रम बाजार में उनकी सहभागिता सीमित होती है तथा आर्थिक स्थायित्व प्रभावित होता है।

अर्चना दत्ता
(लेखिका, दूरदर्शन की पूर्व महानिदेशक हैं)

साठ के दशकारंभ में जब कनाडा की लघु कथा लेखिका एलिस मुनरो को थोड़ी लोकप्रियता मिली तब एक अखबार ने उनके बारे में विवरण प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया था, 'लघु कथायें लिखने के लिए समय निकालने वाली गृहिणी।' इसे एलिस की लोकप्रियता और बढ़ी और उनको 2013 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्लाडिया गोल्डिन ने अपने शोध में बताया था कि महिलाओं की छुट्टी हमेशा उनकी पसंद के अनुसार नहीं होती है, लेकिन अक्सर इसका कारण 'लंबे समय से व्याप्त सामाजिक प्रवृत्ति' के कारण होती है।

इससे महिलाओं के आसपास 'घरेलूपन की अवधारणा' विकसित होती है और बिना भुगतान देखभाल करने या बेगारी करने की उसकी भूमिका को आदर्श के रूप में स्थापित किया जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज भी सभी क्षेत्रों में महिलायें अपने काम का 76.2 प्रतिशत बिना भुगतान वाले देखभाल के काम या बेगार पर खर्च करती हैं जो पुरुषों से तीन गुना अधिक है। सभी क्षेत्रों में प्रशांत और एशिया की स्थिति सबसे खराब है, जहां पुरुष सबसे कम बेगार करते हैं जो औसतन 1 घंटा चार मिनट है। 2018 में कामगार आयुवर्ग की 606 मिलियन महिलाओं ने निराशा प्रकट की थी कि वे श्रम बाजार में इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि उन पर बिना भुगतान वाले देखभाल के काम का भारी बोझ है। इसके उलट इस प्रकार बेगार करने वाले पुरुषों की संख्या केवल 41 मिलियन है। मौद्रिक मूल्य के अनुसार, महिलाओं का बिना भुगतान वाला काम कुछ देशों की जीडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक हो सकता है। समाज वैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चों तथा वृद्धों की देखभाल और बच्चों की संख्या विवाह की तुलना में श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता को अधिक प्रभावित करते हैं।25-54 वर्ष आयु वाली महिलाओं को श्रमशक्ति सहभागिता दर-एलएफपीआर में व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है जिसके कारण 90.6 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में उनकी सहभागिता केवल 61.4 प्रतिशत है। कम से कम 6 वर्ष से छोटे एक बच्चे वाले एकल महिला परिवारों में आर्थिक मजबूरियां महिलाओं की एलएफपीआर को बढ़ा कर 65.8 प्रतिशत कर देती हैं। लेकिन यदि छोटे बच्चे के साथ माता का कोई जोड़ीदार या 'रोटी कमाने वाला पुरुष' हो तो यह दर घट कर 48.7 प्रतिशत रह जाती है। हालांकि, 'रोटी कमाने वाली महिलाओं' पर घर में ज्यादा बोझ होता है, भले ही वे पतियों के साथ बाहर कमाई करती हों।

इस प्रकार की 'मातृत्व की सजा' अमेरिका में भी खूब प्रचलित है। 2023 में पीएनएएस के एक अध्ययन के अनुसार, 'माताओं को गैर-माताओं तथा बिना बच्चे वाले पुरुषों की तुलना में 3.35 प्रतिशत कम काम मिलता है। इसी प्रकार पुरुषों की तुलना में उनके बीच में कॅरियर से अवकाश लेने की प्रवृत्ति 114 प्रतिशत अधिक है। यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए तो महिलायें छुट्टी आसानी से ले लेती हैं क्योंकि उनको कम भुगतान मिलता है। इस कारण उनका छुट्टी लेना आर्थिक रूप से ज्यादा लाभकारी माना जाता है।' ब्रिटिश ट्रेड यूनियन असोसियेशन-टीयूसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'पुरुषों को संरक्षक के रूप में कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता है, बल्कि पूरे समय काम करने वाले पिता के रूप में उनको बच्चे होने पर वेतन में बोनस मिलता है। इस कारण वे 22 प्रतिशत अधिक कमाते हैं।' मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय एमहर्स्ट में समाजविज्ञान की प्रोफेसर माइकेल बुडिग के अनुसार, 'यह विसंगति इसलिए नहीं होती कि मातायें कम उत्पादक कर्मी बन जाती हैं या पिता ज्यादा कठोर परिश्रम करने वाले संरक्षक होते हैं। बल्कि इसका कारण सेवायोजकों की उनसे उम्मीदें हैं जो स्पष्ट रूप से जेंडर और काम के प्रति उनके पूर्वाग्रह स्पष्ट करती हैं।' उनकी शोध से पता चलता है कि बच्चे होने पर पुरुषों की आमदनी औसतन 6 प्रतिशत बढ़ जाती है, यदि वे उनके साथ रहते हैं। लेकिन हर बच्चे पर महिलाओं की आमदनी में 4 प्रतिशत कमी आती है।

भारत में बच्चे के जन्म से श्रमबाजार में महिलाओं का प्रवेश प्रभावित होता है, लेकिन यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग है। कर्नाटक और राजस्थान राज्यों से 'लाइफ हिस्ट्री कैलेंडर'-एलएचसी डेटा के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं में मातृत्व के साथ श्रम बाजार में महिलाओं के प्रवेश पर नुकसान होना जरूरी नहीं है क्योंकि यहां रोजगार की प्रकृति अनौपचारिक व लचीली होती है जो शहरी या ज्यादा औपचारिक परिवेश में बच्चों के पालन-पोषण के प्रति ज्यादा सुविधाजनक है। 2004-2012 के बीच एनएसएस के रोजगार-बेरोजगार शेड्यूल-ईयूएस डेटा से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मातृत्व से लगभग कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि शहरी महिलाओं को कुल वेतन में 18 प्रतिशत का नुकसान होता है।

उच्च शिक्षित महिलाओं या नियमित व वेतनभोगी वर्ग की महिलाओं को कम शिक्षित या अनियमित रोजगार वाली महिलाओं की तुलना में मातृत्व की स्थिति में वेतन का ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि, पहली बार पिता बनने वाले ग्रामीण व शहरी पुरुषों को बच्चे होने पर वेतन में लगभग कोई नुकसान नहीं होता है। श्रम बाजारों में जेंडर समानता की राह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा बच्चों की देखभाल सुविधाओं की कमी है। 18 ओईसीडी देशों में बाल देखभाल नीतियों के एक मैक्रो-इकोनोमिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कामगार माताओं को बनाए रखने के लिए रोजगार संरक्षण तथा लंबी सवेतन छुट्टियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2016 में सात उच्च आय वाले ओईसीडी देशों के एक विश्लेषणात्मक अध्ययन से पता चलता है कि देखभाल उद्योग में जीडीपी के 2 प्रतिशत निवेश से अमेरिका में 13 मिलियन, जापान में 3.5 मिलियन, जर्मनी में 2 मिलियन, ब्रिटेन में 1.5 मिलियन, इटली में 1 मिलियन, आस्ट्रेलिया में 600,000 और डेनमार्क में 120,000 नए रोजगारों का सृजन कर सकता है। इससे महिलाओं के रोजगार में 3.3 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत की वृद्धि होती है, जबकि पुरुषों के रोजगार में केवल 1.4 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत वृद्धि ही होती है। ब्राजील, कोस्टारिका, चीन, भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका में ऐसे ही अध्ययनों से पता चला है कि स्वास्थ्य एवं देखभाल क्षेत्र में इतने ही निवेश से चीन में लगभग 24 मिलियन, भारत में 11 मिलियन, इंडोनेशिया में 2.8 मिलियन, ब्राजील में 4.2 मिलियन, दक्षिण अफ्रीका में 400,000 तथा कोस्टारिका में 63,000 नए रोजगारों का सृजन होगा।

आईएलओ की हालिया वैश्विक 'केयर एट वर्क' रिपोर्ट के अनुसार, 2035 तक रोजगार में जेंडर अंतर 7 प्रतिशत तथा आमदनी में अंतर 1.8 प्रतिशत घटाने के लिए हर साल 204 मिलियन डालर से अधिक टिकाऊ निवेश किया जाना चाहिए जो हर देश की जीडीपी का औसतन 5.8 प्रतिशत है। यह निवेश समग्र बाल-देखभाल तथा दीर्घकालीन देखभाल सेवाओं में किया जाना चाहिए। नारीवादी अर्थशास्त्रियों तथा 'पर्पल इकोनोमी' के पैरोकारों ने देखभाल को 'मानव बेहतरी का अपरिहार्य आयाम' बताते हुए 'देखभाल एवं जेंडर समानता वाली समतापूर्ण आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था' का आह्वान किया है।

समय आ गया है कि देखभाल की जिम्मेदारियों का राज्य और परिवारों तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच साझा किया जाए। समय आ गया है कि पूरी दुनिया सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों-एसडीजी 2030 की प्रतिबद्धताओं को पूरी करने तथा महिलाओं को आर्थिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियां बनाए तथा इनको क्रियान्वित करने के लिए समुचित संसाधन आबंटित करे। वैश्विक रूप से महिलायें काफी समय बिना भुगतान वाले देखभाल का काम करती हैं। इससे श्रम बाजार में उनकी सहभागिता सीमित होती है तथा आर्थिक स्थायित्व प्रभावित होता है। बच्चों की देखभाल में राज्य के समुचित निवेश से महिला श्रम सहभागिता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

जी-7 सम्मेलन और दक्षिण जगत

"जी-7 की बैठक से एक स्पष्ट संदेश यह मिला कि वैश्विक मामलों पर कई लोगों की राय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था बनाई जा रही है।"

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

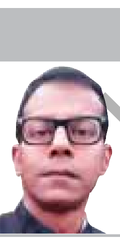

हाल ही में इटली के सुरम्य अपुलिया में आयोजित जी7 बैठक में दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों के बीच हाल के भू-राजनीतिक बदलावों और बदलते समीकरणों पर कई संकेत मिले। जी हाँ, मीम-योग्य, घूरने, नमस्कार और पैराशूट लैंडिंग की तस्वीरें जिन्होंने सोशल मीडिया को जीवंत रखा और विश्व नेताओं की बैठकों और रात्रिभोजों के एक अन्यथा उबाऊ दौर में ऊर्जा भर दी, साझा हितों के विषयों पर चर्चा करते हुए, रेखांकित बिंदुओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया गया।

सबसे पहले, बैठक का स्पष्ट फोकस, जैसा कि संयुक्त विज्ञप्ति में उजागर किया गया था, यूक्रेन था ताकि चीन और रूस के साथ गुप्त रूप से काम करने वाले अन्य दलों को कुछ सख्त संदेश भेजे जा सकें। एक स्पष्ट संदेश में और सीधे चीन का नाम लेते हुए, संयुक्त वक्तव्य में कहा गया, हम चीन और तीसरे देशों में उन अभिनेताओं के खिलाफ कदम उठाना जारी रखेंगे जो रूस की युद्ध मशीन का भौतिक रूप से समर्थन करते हैं, जिसमें वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं, हम दोहराते हैं कि वित्तीय संस्थाओं सहित ऐसी संस्थाएं जो रूस को उसके रक्षा औद्योगिक आधार के लिए वस्तुओं या उपकरणों के अधिग्रहण में सहायता करती हैं, वे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को कमजोर करने वाली कार्रवाइयों का समर्थन कर रही हैं।

तदनुसार, हम दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी कानूनी प्रणालियों के अनुरूप प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करेंगे और इस गतिविधि में शामिल चीनी संस्थाओं सहित तीसरे देशों में लक्षित व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए हमारी वित्तीय प्रणालियों तक पहुँच को प्रतिबंधित करेंगे। चीन को संदेश था, आग से खेलते मत रहो, क्योंकि एक दिन यह तुम्हें जला सकती है। यह उल्लेखनीय हो सकता है कि अमेरिका ने चीन को उच्च तकनीक वाले उपकरणों के हस्तांतरण को रोकने के लिए कई निर्यात नियंत्रण उपाय किए हैं, जिनकी दोहरे उद्देश्य वाली उपयोगिताएं हैं, यानी उनका उपयोग सटीक हथियार बनाने के साथ-साथ साइबर निगरानी उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। चीन एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था थी, (रूस-यूक्रेन युद्ध में इतनी प्रत्यक्ष पार्टी नहीं), जो जी 7 शिखर सम्मेलन से अनुपस्थित थी। हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के खिलाफ कई यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ-संबंधी मुद्दों को कम करने के लिए कई यूरोपीय देशों का दौरा किया। यूरोप के कुछ देश चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाने के अमेरिकी नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वहीं कई अन्य देश चीन की ओर झुके हुए हैं। इस बीच, जी-7 शिखर सम्मेलन ने वैश्विक मामलों में वैश्विक दक्षिण देशों को शामिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की एक तरह से अप्रत्यक्ष प्रशंसा की, अफ्रीकी देशों के महत्व को दोहराया और क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों का वादा किया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया, हम अंतरराष्ट्रीय निकायों में अधिक से अधिक आवाज उठाने के अफ्रीकी देशों के आह्वान का समर्थन करते हैं और स्थायी सदस्य के रूप में जी-20 में एयू की भागीदारी और नवंबर में आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड में उप-सहारा अफ्रीका के लिए तीसरे अध्यक्ष के निर्माण का स्वागत करते हैं। हम अफ्रीका के साथ जी-20 समझौते के लिए अपने समर्थन को दोहराते हैं, जो निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने, संरचनात्मक सुधारों और स्थानीय उद्यमिता समर्थन को बढ़ावा देने और ऊर्जा क्षेत्र सहित सहयोग को बढ़ाने के लिए एक उपकरण है। विशेष आमंत्रित के रूप में अपुलिया में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संक्षिप्त आउटरीच सत्र में वैश्विक दक्षिण देशों की प्रमुखता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, वैश्विक दक्षिण के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे हैं। भारत ने वैश्विक दक्षिण के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी समझा है। हमने इन प्रयासों में अफ्रीका को उच्च प्राथमिकता दी है।

हमें गर्व है कि भारत की अध्यक्षता में जी-20 ने अफ्रीकी संघ को अपना स्थायी सदस्य बनाया। भारत सभी अफ्रीकी देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास, स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देता रहा है और आगे भी देता रहेगा।

इटली में जी-7 की बैठक से एक स्पष्ट संदेश यह मिला कि वैश्विक मामलों पर कई लोगों की राय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था बनाई जा रही है, जबकि मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं को घरेलू स्तर पर चुनौती दी जा रही है।

आप की बात

नालंदा की गरिमा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह आह्वान हमें गौरवान्वित करता है कि भारत को ज्ञान और शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय इतिहास बन चुका था। प्रधानमंत्री द्वारा नवनिर्मित विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन के साथ ही नालंदा पुनर्स्थापित हो रहा है। नरेन्द्र मोदी का यह कथन भी महत्वपूर्ण है कि आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती है। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने पांचवीं सदी में बनवाया था जिसे चीनी पर्यटक एवं यात्री ह्वेनसांग ने विश्व के समक्ष शानदार ढंग से रखने का कार्य किया था। एक समय इस महान विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र अध्ययनरत थे और करीब 1,500 शिक्षक भारत के महान दर्शन, योग, सभ्यता, संस्कृति एवं बौद्ध दर्शन पर ज्ञानवर्धन का करते थे। एक आततायी हमलावर ने इसे इस कारण नष्ट कर दिया था क्योंकि उसे नालंदा द्वारा प्रचारित-प्रसारित बौद्ध व हिंदू दर्शन से घृणा थी और इसे वह अपने धर्म के लिए घातक मानता था। इसके उलट बौद्ध व हिंदू दर्शन सारी दुनिया के ज्ञान-विज्ञान को अपने भीतर समाहित करते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि नालंदा पुन: भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से अदा करेगा।

– **वीरेंद्र कुमार जाटव**, दिल्ली

परीक्षाओं की शुचिता

नीट के बाद अब यूजीसी में भी पेपर लीक होने की गड़बड़ी सामने आना अफ्सोसजनक है। इन परीक्षाओं के लिए छात्र लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग और पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई की भरपूर फीस भरते है और देर रात तक जाग-जाग कर 16-16 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। और भ्रष्टाचार के दानवों ने उनके कठोर परिश्रम को निगल लिया है तो उनमें गंभीर निराशा पैदा होती है। सुप्रीमकोर्ट में मामला जाने के बाद नीट में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं। विडंबना है कि राजनीतिक दलों ने इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेंकना शुरू कर दी है। संभवत: जिन बड़े नेताओं के तार इस अपराध से जुड़े हुए हैं वह भी चिल्ला-चिल्ला कर सरकार और शिक्षा विभाग की आलोचना कर रहे है। लगता है कि तथाकथित बड़े नामी गिरामी कोचिंग क्लासेस वाले पेपर फिक्सिंग करवा रहे हैं। लगता है कि अखबारों में लाखों रुपए के विज्ञापन देने और करोड़ों रुपए को लिए कोचिंग क्लासेस वाले कुछ शिक्षा माफिया ने कई गिरोह खड़े कर लिए हैं। यह पूरी सड़ी-गली व्यवस्था समाप्त करने का समय आ गया है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सबसे कड़ी परीक्षा होगी।

– **सुभाष बुडावन वाला**, रतलाम

भारतीय शिल्पकला

प्राचीन काल के मंदिरों के प्रांगणों में और उनकी दीवारों में जटिल और सूक्ष्म शिल्पकला की मूर्तियां, डिजाइन आदि बनी होती है जो आज के युग मे आश्चर्य के साथ सौंदर्य का बोध कराती हैं। खजुराहो, कोणार्क, कैलाश मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, आदि कई मंदिर, गुफाएं व महल चट्टानों को तराश कर मूर्तियों अथवा भित्तिचित्रों से अलंकृत हैं। कालांतर मे तो विशेषकर दक्षिण में मूर्तियों का इतना बाहुल्य हो गया कि स्वयं मंदिर तो उनका निमित्त अथवा आधार मात्र प्रतीत होने लगे हैं। वाकई शिल्पकला का जटिल और सूक्ष्म शैल्पिक अलंकरण लोगों को आकर्षण में बाँध देता है। पिछले वर्षों में बने अनेक मंदिरों में भारतीय शिल्पकला को उतना महत्व नहीं मिला। इस दृष्टिकोण से अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर, वाराणसी में विश्वनाथ कारीडोर, इंदौर में महाकाल तथा पिछले दशक में बने अनेक मंदिरों को विस्तार देने के साथ ही उनमें प्राचीन भारतीय शिल्पकला को भी महत्व दिया गया है। विदेशों में बने और बन रहे मंदिरों में भी भारतीय शिल्पकला के साथ आधुनिक इंजीनियरिंग व वास्तुकला से प्राप्त ज्ञान को समाहित किया जा रहा है। यह भारतीय संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण कदम है।

– **संजय वर्मा**, मनावर

जमीनी समस्यायें

हर साल खुले मेनहोल, सड़कों पर निर्माणाधीन कार्यों से उपजे गड्ढे, ऊबड़-खाबड़ रास्तों आदि में बरसात में पानी भर जाने से अनेक दुर्घटनाएं हो जाती हैं। एक तो सड़कों के गड्ढों में पानी, ऊपर से बिजली की कमी व बिना संकेत के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे समय रहते न भरने का अर्थ अनहोनियों को प्रशासन द्वारा न्यौता देने के समान ही है। यह हमारे इंदौर की ही समस्या ही नहीं है, बल्कि हर गाँव, कस्बे, नगर या महानगर व पूरे देश की समस्या है। ऐसी सभी समस्यायें स्थानीय प्रशासन की कार्य-शिथिलता के कारण पैदा होती हैं। अत: देश के सभी स्थानीय प्रशासन सड़कों के खुदे गड्ढों को समय रहते भरें, जहाँ जरूरी हो वहां संकेतक लगाएं तथा उनके आसपास बिजली की व्यवस्था करें ताकि रात-बिरात राहगीर धोखा न खाएं। अगर हर गाँव, शहर और महानगर की लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे तो अवश्य बिना किसी अनहोनी के लोगों के बरसात के दिन अच्छे से गुजर सकेंगे। यदि जमीनी स्तर पर ऐसे संकटों से गुजरना पड़े तो देश, अपने जीवन तथा भावी पीढ़ियों के भविष्य के प्रति विश्वास डगमगाता है।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 109

एनवीडिया का उभार और एआई

एनवीडिया का गेम चिप डिजाइनर कंपनी से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनना केवल संयोग मात्र नहीं है। इसका सीधा संबंध ऐसे सेमीकंडक्टर डिजाइन करने में उसकी विशेषज्ञता से है जो गहन संख्याओं की गणना करने में अच्छे हैं। इसकी टाइमलाइन बिल्कुल सीधी है। चैटजीपीटी को नवंबर 2022 में सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था। इसके बाद आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास में तेजी आई। वर्ष 2023 में एनवीडिया का राजस्व दोगुना से अधिक बढ़कर 60.9 अरब डॉलर हो गया क्योंकि कंपनी की चिप की मांग दुनिया भर में बढ़ गई। एनवीडिया का शुद्ध लाभ भी छह गुना बढ़कर 29.7 अरब डॉलर हो गया। मई 2023 में पहली बार कंपनी का बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ डॉलर का स्तर पार कर गया और अगले 13 महीनों में यह तीन गुना से अधिक हो गया। एनवीडिया इसलिए असामान्य है कि यह एक चिप निर्माता कंपनी है जो खुद चिप नहीं बनाती। यह विशेष प्रकार के सेमीकंडक्टर डिजाइन करती है, जिन्हें अनुबंध करने वालों की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कंपनी अपनी चिप का निर्माण इंटेल जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनी से भी कराने को तैयार है।

शुरुआत में एनवीडिया का ध्यान गेमिंग बाजार पर केंद्रित था और वह गेमिंग बाजार में करीब 80 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे अधिक दबदबा रखती है। गेमिंग के कारण को-प्रोसेसर (इन्हें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या जीपीयू भी कहा जाता है) की मांग बढ़ी ताकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) को हल्के कामों के लिए खाली छोड़ दिया जाए और जटिल गणनाओं का काम जीपीयू करें। एआई को जीपीयू की ऐसी ही लेकिन कहीं अधिक गहन प्रक्रियाओं की जरूरत होती है और एनवीडिया की विशेषज्ञता ने उसे एआई की दुनिया में अग्रणी बनने में मदद की है। चिप डिजाइन में विशेषज्ञता के अलावा कंपनी एक अलग तरह की कारोबारी संस्कृति का पालन करती है। लाखों करोड़ डॉलर की कंपनी के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। उसके 30,000 से भी कर्मचारी हैं। लाख करोड़ डॉलर वाली अन्य कंपनियों की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के 2,20,000 कर्मचारी हैं जबकि ऐपल के 1,60,000 और गूगल के 1,80,000 कर्मचारी हैं।

कंपनी का नाम 'नेक्स्ट वर्जन' और 'इनविडिया' से बना है जो ईर्ष्या के लिए लैटिन भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द है। वर्षों तक कंपनी के प्रेसिडेंट और मुख्य कार्य अधिकारी जेनसेन हॉन्ग की ओर से मिलने वाले आंतरिक संदेशों की शुरुआत एक चेतावनी से होती थी: 'हमारी कंपनी तीस दिनों में कारोबार से बाहर होने के कगार पर है।' सन 1997 में ऐसा हुआ भी था जब एनवीडिया बंद होने के कगार पर थी। संदेश में जो हताशा का भाव है वही एनवीडिया को चला रहा है। अब कंपनी शोध और विकास के लिए कई साझेदारियों में शामिल है जिनमें भारत में टाटा और रिलायंस समूह के साथ साझेदारी भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी कई आईआईटी के साथ भी काम कर रही है।

अमेरिका ने एनवीडिया की चुनिंदा चिप के चीन को होने वाले निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि उनका सैन्य इस्तेमाल हो सकता है। कंपनी की कुछ उत्कृष्ट जीपीयू की कीमत एक लाख डॉलर से भी अधिक है। उनकी इतनी कमी है कि उनको सशस्त्र बलों की निगरानी में भेजा जाता है और अगर कोई उन्हें खरीदकर दोबारा बेचे तो उसे बहुत बेहतर दाम मिलते हैं। लिनक्स के डेवलपर और गेमर समुदाय ने भी ड्राइवर्स की ओपन सोर्सिंग नहीं करने के कारण कंपनी की आलोचना की है। कंपनी की चिप इन्हीं कोड से संचालित होती हैं। ऐसे में डेवलपर और गेम डिजाइनर के लिए एनवीडिया के प्रदर्शन को अनुकूलित करना मुश्किल होता है। बहरहाल आखिरकार एनवीडिया इस समुदाय तथा अन्य समकक्ष कंपनियों के दबाव में झुकी और उसने ओपनसोर्सिंग आरंभ की। ऐसा इसलिए कि इंटेल और एएमडी ऐसा कर रही थीं। एनवीडिया एकाधिकार की स्थिति में है, यही वजह है कि इसे इतनी तवज्जो मिल रही है। यह एआई आपूर्ति श्रृंखला का अहम घटक है और इसके प्रदर्शन में मामूली कमी पूरे उद्योग में उथलपुथल ला सकती है। जब तक उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां अहम क्षमता नहीं विकसित कर लेतीं, यह चिंता का विषय बना रहेगा।

आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याओं का समाधान?

बदल रही परिस्थिति में नैबफिड को सफल होना चाहिए। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एक नया संपत्ति वर्ग हैं जो अच्छा रिटर्न देती हैं। बता रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

देश में 2021 में स्थापित विकास वित्त संस्थान, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक (नैबफिड) के चेयरमैन केवी कामत का केबिन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की द कैपिटल बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर मौजूद है और यहां से आईसीआईसीआई बैंक मुख्यालय थोड़ी ही दूरी पर है जिसका नेतृत्व उन्होंने 2009 तक किया था। इसके बाद छह साल यानी करीब 2015 तक वह बैंक के अध्यक्ष रहे, जिसका विलय इसकी मूल कंपनी आईसीआईसीआई लिमिटेड के साथ हो गया था। उन्हें शायद उन दिनों की याद आती होगी जब एक प्रोजेक्ट फाइनैंस संस्थान के पास अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए बैंक के साथ विलय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

लेकिन नैबफिड के अध्यक्ष के रूप में अब उन्हें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी का इंतजाम करने के लिए एक बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व इसके प्रबंध निदेशक (एमडी) राजकिरण राय करते हैं।

नैबफिड ने वित्त वर्ष 2024 में 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य तक की मंजूरी दी। मार्च तक ऋण वितरण 36,000 करोड़ रुपये था और मई के अंत तक यह 45,000 करोड़ रुपये को पार कर गया। इसमें से लगभग 50 प्रतिशत 15-25 वर्षों का दीर्घकालिक ऋण हैं। राय को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी मिल जाएगी और ऋण वितरण 93,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक राय ने अगस्त 2022 में यह कार्यभार संभाला था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण में नैबफिड की स्थापना की घोषणा के आठ महीने बाद अक्टूबर 2021 में कामत इस संस्थान से अध्यक्ष के रूप में जुड़े। दिसंबर 2022 में जम्मू कश्मीर में एक सुरंग परियोजना के लिए फंड का पहला वितरण किया गया था, जिसे काजीगुंड एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड संचालित कर रही थी। अक्षय ऊर्जा वाली बिजली और पारंपरिक बिजली उत्पादन परियोजनाएं इसके पोर्टफोलियो में आधे से अधिक हैं और इसके बाद सड़कें (एक चौथाई से थोड़ा अधिक) और रेलवे हैं। इसने अब तक दूरसंचार, सिटी गैस वितरण, बिजली ट्रांसमिशन तथा वितरण में भी हाथ आजमाया है।

नैबफिड को 1 लाख करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ स्थापित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ऋण और इक्विटी निवेश के माध्यम से बुनियादी ढांचे की फंडिंग और दीर्घकालिक बॉन्ड तथा डेरिवेटिव बाजार तैयार करना है।

भारत के वित्तीय बाजार ढांचे में बॉन्ड बाजार हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है। वर्ष 2006 के केंद्रीय बजट में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार तैयार करने के वास्ते अहम मुद्दों का हल करने के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी लेकिन पूंजी बढ़ाने में बहुत कम प्रगति हुई है। वर्ष 2016 से, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़ी कंपनियों को अपने दीर्घकालिक ऋण का कुछ हिस्सा कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार से जुटाने पर जोर दिया है।

नैबफिड की चुकता पूंजी 20,000 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान भी है। पिछले साल इसने मुख्य रूप से घरेलू बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों से 10 और 15 साल के दो चरणों के माध्यम से 19,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। नए वितरण के लिए नैबफिड ने कई बैंकों से 20,000 करोड़ रुपये के ऋण का इंतजाम किया है। हरित जलवायु कोष सहित सौर, पवन ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक फंड के लिए कुछ बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ बातचीत भी चल रही है। यह चालू वर्ष की अंतिम तिमाही में बाहरी वाणिज्यिक उधारी जुटाने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है।

भारत में बुनियादी ढांचे की फंडिंग कभी आसान नहीं रही है। आजादी मिलने के बाद दीर्घावधि की परियोजनाओं, विशेषतौर पर बुनियादी ढांचे की फंडिंग के लिए ऋणदाताओं के एक विशेष वर्ग को बढ़ावा दिया गया जिसे विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) कहा गया। ये तब तक अच्छी तरह चलते रहे जब तक उन्हें आरबीआई के मुनाफे से तैयार हुई, कम लागत वाले नैशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट (दीर्घावधि के परिचालन के लिए) फंड की सुविधा मिली थी। उन्होंने सरकारी गारंटी वाले बॉन्ड के जरिये भी किफायती पूंजी जुटाई। पहली बार डीएफआई, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके बाद 1955 में आईसीआईसीआई और 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई। 1990 के दशक में सस्ती पूंजी का स्रोत बंद हो जाने के बाद से उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं और इसके चलते उनकी संपत्ति और देनदारियों में भारी असंतुलन पैदा हो गया।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनैंस कंपनी की स्थापना 1997 में मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास और परियोजना से जुड़ी पूंजी जुटाने के लिए की गई थी। हालांकि, यह भी सफल नहीं हो सका। इस क्षेत्र में किए गए एक अन्य प्रयोग में भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) भी शामिल है। इसका लक्ष्य 'भारत में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के संवर्धन एवं विकास के लिए नए वित्तीय उपकरण' मुहैया कराना है। वर्ष 2006 में स्थापित हुए, आईआईएफसीएल की 31 मार्च, 2023 तक बकाया ऋण राशि 42,271 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2024 में, इसने 42,309 करोड़ रुपये की मंजूरी दी और 33,356 करोड़ रुपये का वितरण किया।

लगभग 100 कर्मचारी 23,000 वर्ग फुट के नैबफिड कार्यालय में काम करते हैं, जो भारत के विकास गाथा के लिए अहम बुनियादी ढांचे की फंडिंग में एक नया अध्याय तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। शीर्ष-स्तर के कर्मचारी अनुबंध पर हैं जबकि प्रवेश स्तर पर, नैबफिड अपने पेरोल पर सीए, एमबीए और स्नातकोत्तर इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है ताकि एक टीम तैयार की जा सके। फंडिंग के साथ-साथ, यह लेन-देन से जुड़ी परामर्श सेवाओं के लिए एक परियोजना मूल्यांकन टीम भी तैयार कर रहा है जो आगामी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का तकनीकी अध्ययन करेगा। इस संबंध में उसने पहले ही अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विचार यह है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन तैयार करने में मदद मिले। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन के पूरक के रूप में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए एक डेटा भंडार भी बनाना है।

भले ही इस क्षेत्र में पहले के प्रयास विफल रहे हों लेकिन नैबफिड को सफल होना चाहिए क्योंकि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है। निवेशकों के नजरिये से देखा जाए तो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एक नया परिसंपत्ति वर्ग हैं जो बेहतर रिटर्न देने की गुंजाइश रखता है। मैं नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वे परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं और वे भुनाए जाने के लिए तैयार हैं, वे भी विदेशी पूंजी और निजी इक्विटी के अलावा खुदरा निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती हैं। अक्टूबर 2022 में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नैशनल हाईवेज इन्फ्रा ट्रस्ट (एनएचएआई इनविट) गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) की सूचीबद्धता के माध्यम से इसके रिटेल में प्रवेश को औपचारिक रूप से दर्शाने के लिए बंबई स्टॉक एक्सचेंज में इसकी शुरुआत की। एनसीडी का एक-चौथाई हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित था। इनविट के दूसरे चरण में इसने हर वर्ष 8.05 प्रतिशत प्रतिफल की पेशकश की और इसकी ओपनिंग के सात घंटों के भीतर लगभग सात गुना अभिदान मिला।

इनविट, या इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक म्युचुअल फंड की तरह है, जो निजी और संस्थागत निवेशकों की पूंजी को सीधे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने और आमदनी के एक हिस्से को रिटर्न के रूप में हासिल करने में मददगार होता है। निवेशकों का एक नया वर्ग इन्फ्रा को परिसंपत्ति वर्ग के रूप में मानने के लिए तैयार है क्योंकि सभी घटक चाहे वह सरकार, वित्तीय संस्थान और कॉरपोरेट जगत हो, उन्होंने पिछली गलतियों से सीखा है। परियोजना की फंडिंग के क्षेत्र में पिछले दशक की शुरुआत में काफी कुछ गड़बड़ था जिसमें पर्यावरणीय मंजूरी का न मिलना, अदालतों द्वारा परियोजनाओं पर रोक लगाना, कंपनियों का टाल-मटोल करना और बैंकों की खराब संपत्ति का बढ़ना शामिल है। बैंकों के फंसे कर्जों में सर्वाधिक योगदान देने वालों में दूरसंचार, बिजली, ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) और इस्पात जैसे चार संकटग्रस्त क्षेत्र शामिल हैं। नियामक ने दिसंबर 2015 और मार्च 2017 के बीच छह तिमाहियों में एक परिसंपत्ति की गुणवत्ता समीक्षा के जरिये बैंकों को अपनी बैलेंसशीट बेहतर बनाने के लिए मजबूर किया। नतीजतन, बैंकिंग प्रणाली अब जोखिम से उबरने के लिए तैयार है क्योंकि 26 सूचीबद्ध बैंकों की शुद्ध गैर-निष्पादित संपत्ति 1 प्रतिशत से कम है और उद्योग ने वित्त वर्ष 2024 में अब तक का सबसे अधिक 3.2 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। वर्ष 2016 में बनी दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता ने तंत्र से राजनीतिक संबंधों का लाभ हासिल करने वाले पूंजीपतियों को बाहर किया है और सरकार लौह अयस्क तथा कोयला खदानों के आवंटन और परियोजना से जुड़ी बाधाएं दूर करने के लिए सक्रिय हो गई हैं। अब किसी भी परियोजना में निवेश से पहले भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी मिल जाती है।

फंडिंग का ढांचा भी बदल रहा है। बीमा, पेंशन और भविष्य निधि का बड़ा कोष क्रमशः लगभग 75 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये हो सकता है और यह दीर्घकालिक निवेश की तलाश में है। इसके अतिरिक्त, बाजार से धन जुटाया जा सकता है। बैंकिंग प्रणाली अब फंडिंग का एकमात्र स्रोत नहीं रह जाएगी। नैबफिड, बॉन्ड बाजार और दीर्घकालिक विदेशी और घरेलू फंड बुनियादी ढांचे के लिए मिश्रित फंडिंग के विकल्प तैयार करेगा, जिससे बैंकिंग प्रणाली के लिए जोखिम कम होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2021 के अपने बजट में नैबफिड के गठन की घोषणा करते हुए कहा था, 'इस डीएफआई के लिए तीन वर्षों में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपये का ऋण पोर्टफोलियो रखने की महत्त्वाकांक्षा है।' यह लक्ष्य से काफी पीछे है लेकिन यह एक संस्था के लिए ऐसी महत्त्वाकांक्षा भी है जो हकीकत नहीं बन सकता है, खासतौर पर एक ऐसे संस्थान के लिए जो खुद को भारत के बुनियादी ढांचे की समस्याओं के पूर्ण समाधान के रूप में पेश कर रहा था।

क्या यह सफल होगा? यह कहना जल्दबाजी होगी। इस बीच, आरबीआई ने मई में अधूरी पड़ी परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण ढांचे का मसौदा जारी किया है। यह मसौदा नाबार्ड सहित सभी बुनियादी ढांचा ऋणदाताओं के लिए संभावित रूप से चुनौती बन सकता है।

समान नागरिक संहिता और आदिवासी

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मुद्दा विवादों से अछूता नहीं रहा है। इन्हीं विवादों के बीच एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि भारत में आदिवासी समुदाय इस बात से कितने भयभीत हैं कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) उनसे उनकी पहचान छीन लेगी और एक विशिष्ट समुदाय के रूप में उन पर सवालिया निशान लगा देगी? अगर 2024 के लोक सभा चुनाव के नतीजों पर विचार करें तो इस प्रश्न का उत्तर देना और जटिल हो जाता है।

ठीक एक वर्ष पहले विधि आयोग ने धर्म, रीति-रिवाज और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह जाति, संप्रदाय, यौन रुझान एवं लिंगभेद से इतर एक साझा कानून लाने के प्रस्ताव पर सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं मांगी थीं। व्यक्तिगत कानून और विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े कानून एक समान संहिता में लाए जाने का प्रस्ताव था। जून 2019 तक इस विषय पर सरकार को लगभग 19 लाख सुझाव मिले थे। अब लोक सभा चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता लोगों को व्हाट्सऐप पर संदेश भेजकर उन्हें यूसीसी के लिए 'हां' के पक्ष में राय देने के लिए कह रहे हैं।

भाजपा के वर्ष 2024 के चुनावी घोषणापत्र में यूसीसी के आने से पहले से ही आदिवासी समूह के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह और सरकार के शीर्ष अधिकारियों से मिलना शुरू कर दिया था। इन समूहों के नेता आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखे जाने की मांग कर रहे थे। भाजपा सांसद, एक गैर-आदिवासी नेता एवं विधि पर स्थायी समिति के अध्यक्ष दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने एक बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह व्यक्तिगत तौर पर महसूस करते हैं कि पूर्वोत्तर के आदिवासियों को यूसीसी की जद से बाहर रखा जाना चाहिए। मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों जैसे कोर्नाड संगमा (मेघालय के मुख्यमंत्री एवं राजग के घटक दल के नेता) की मांग के साथ सहमति जताई थी। संगमा का मानना है कि यूसीसी से भारत की ताकत माने जाने वाली इसकी विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नगालैंड और मिजोरम विधानसभाओं में पारित प्रस्तावों में कहा गया है कि उन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम, नगालैंड में आदिवासी समुदायों की आबादी क्रमशः 94.4 प्रतिशत, 86.5 प्रतिशत और 86.1 प्रतिशत है। मिजो समुदाय के लोग अनुच्छेद 371 (जी) के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं।

परंतु, भारत में सदैव किंतु-परंतु तो लगा ही रहता है। झारखंड के भाजपा नेता सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि यूसीसी के लिए आदिवासियों के मन में बैठे डर का नुकसान लोक सभा चुनाव में हुआ है। भाजपा राज्य की 14 में 8 सीटों पर जरूर विजयी रही मगर, इसके उम्मीदवारों की जीत का अंतर वर्ष 2019 के लोक सभा चुनाव की तुलना में कम रह गया। पार्टी को एक तरह से दोहरा झटका लगा। पहली बात तो उसका मत प्रतिशत 2019 के 51.6 प्रतिशत से घट कर 44.58 प्रतिशत रह गया और दूसरी बात यह कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर यह एक भी सीट नहीं जीत पाई।

झारखंड में भाजपा को हुए नुकसान के दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इनमें एक है भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और दूसरा है यूसीसी का मंडराता खतरा। आदिवासी समूह 'सरना' की सुरक्षा के मुद्दे पर सक्रिय रहे हैं। सरना एक पुरानी प्रथा है जिसमें आदिवासी वन, पहाड़, मवेशी, जीव-जंतु आदि की पूजा करते हैं। आदिवासी समन्वय समिति महिलाओं के अधिकारों, विरासत एवं दत्तक ग्रहण आदि मुद्दों पर आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करने में आगे रही है। आदिवासियों के बीच ईसाई धर्म की भी पैठ धीरे-धीरे बढ़ रही है जिससे मामला और पेचीदा हो जाता है।

हालांकि, इतना कुछ होने के बाद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हालात बिल्कुल अलग दिखे। मध्य प्रदेश में आदिवासियों सहित सभी लोगों ने भाजपा को दिल खोलकर वोट दिए। पार्टी को राज्य की 29 लोकसभा सीटों में सभी पर जीत हासिल हुई। लोक सभा चुनाव से पहले कुछ महीने पहले हुए राज्य विधान सभा चुनाव में भी भाजपा कुल 230 सीटों में 163 झटकने में कामयाब रही। भाजपा को विधान सभा में इससे पहले कभी इतना प्रचंड बहुमत नहीं मिला था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में मिलाकर कुल 76 विधान सभा सीटें आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित हैं। वर्ष 2018 में भाजपा को इनमें 19 सीटों पर जीत मिली थी और 2013 में यह संख्या बढ़कर 44 हो गई। इनमें अधिकांश सीटें पहले कांग्रेस के पास थीं।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के उम्दा प्रदर्शन से एक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। वह प्रश्न यह है कि अगर झारखंड में आदिवासी यूसीसी के कारण अपनी पहचान के संकट से इतने भयभीत हैं तो यही भय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को वोट देने वाले आदिवासी मतदाताओं में क्यों नहीं दिखा? या फिर आदिवासी बहुल ओडिशा में क्यों बाजी भाजपा के हाथ लगी जहां उसने राज्य की 21 लोक सभा सीटों में 20 पर परचम लहरा दिया और राज्य में पहली बार सरकार भी बना ली?

आपका पक्ष

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने से घटेगा ईंधन का आयात

सरकार की तरफ से परंपरागत ऊर्जा की जगह हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) को बढ़ावा देने के प्रयासों के नतीजे अब दिखने लगे हैं। अगर सबकुछ ठीक रहा तो अनुमान है कि वर्ष 2030 तक पेट्रोल-डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के आयात में गिरावट से एक लाख करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है। इसके अलावा इस अवधि तक कार्बन उत्सर्जन में सालाना पांच करोड़ टन की कमी भी आएगी। वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 50 लाख टन तक हो जाएगी। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी के साथ इसके आयात को घटाने के उद्देश्य से पिछले साल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत पेट्रोल-डीजल का आयात करता है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल (फेम) स्कीम लेकर आई थी, जिसकी मदद से दो पहिया वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए दिसंबर तक देश भर में 10,000 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हो चुकी है। देश में मेट्रो का जाल 450 किलोमीटर तक पहुंच गया है। वर्ष 2014 में मेट्रो रेल सेवा पांच शहरों में थी जो वर्ष 2023 तक बढ़कर 21 शहरों में हो गई। पिछले नौ वर्षों में सोलर और अन्य ग्रीन एनर्जी की उत्पादन क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर की उत्पादन क्षमता में वर्ष 2014 के मुकाबले 25 गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 में सोलर की उत्पादन क्षमता सिर्फ 2,600 मेगावॉट थी,जो नवंबर 2023 में 76,000 मेगावॉट हो गई थी। गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन की क्षमता पिछले नौ वर्षों में बढ़कर 1.87 लाख मेगावॉट तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार यह भी मानती है कि ग्रीन एनर्जी पर पूरी तरह से शिफ्ट होना बहुत बड़ी चुनौती है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए दिसंबर 2023 तक देश भर में 10,000 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हो चुकी है

प्लास्टिक और पॉलिथीन इधर-उधर न फेंकें

हिमाचल प्रदेश समेत पर्वतीय प्रदेशों में जो पर्यटक बाहरी राज्यों से आते हैं, उन्हें स्वच्छता का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पानी और अन्य पेय पदार्थों की बोतलों को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूसरे पर्यटन स्थलों पर भी देखी जा सकती है। पॉलिथीन की थैलियां इधर-उधर फेंकी जाती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में पॉलिथीन प्रयोग पर प्रतिबंध है। लेकिन पर्यटकों और श्रद्धालुओं का पॉलिथीन लाकर फेंकना उचित नहीं है। स्वच्छता का लक्ष्य और स्वच्छ भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक कि प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह से बंद नहीं होता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा बोतलों का होता है। अगर लोग फल-सब्जियों के छिलकों या इनके अन्य अवशेषों और बचे शाकाहारी भोजन को गौशाला में, प्लास्टिक, अखबारों या कागज की रद्दी को कबाड़ी को देना आरंभ कर दें तो देश स्वच्छ हो सकता है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'एक्स' पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'श्रीनगर में योग के बाद सेल्फी! यहां डल झील में अद्वितीय जीवंतता।' उन्होंने कहा कि योग जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर शेर-ए-कश्मीर इंटरनैशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित किया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संवाद
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 22 जून 2024

अब मिले राज्य का दर्जा
जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पहले उठी मांग

लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद जम्मू-कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही वहां के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षा को संबोधित किया। उन्होंने न केवल वहां जल्द चुनाव कराए जाने का संकेत दिया बल्कि यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने में अब ज्यादा देर नहीं है। बेशक ये दोनों मुद्दे जम्मू-कश्मीर के लोगों के दिल के करीब हैं, लेकिन इन पर ऐसी घोषणाओं से आगे बढ़कर काफी कुछ करने की जरूरत है।

पीएम मोदी का दो दिवसीय दौरा

स्पष्टता की कमी | पीएम मोदी ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले ही दिन इन दोनों मसलों का जिक्र किया जो इस बात का संकेत है कि सरकार की प्राथमिकता सूची में ये दोनों मुद्दे काफी ऊपर हैं। फिर भी ये घोषणाएं वहां तत्काल खास उत्साह नहीं जगा पाईं तो उसकी एक वजह यह भी है कि इनमें स्पष्टता की थोड़ी कमी पाई गई। प्रधानमंत्री की बातों से यह साफ नहीं हुआ कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दिए जाने की योजना है।

चुनाव की हैसियत | संभवतः यही कारण रहा कि पीएम मोदी के बयान के बाद वहां से यह मांग उठी कि सरकार को चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। विधानसभा चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर की समयसीमा तय कर चुका है। लेकिन चुनाव राज्य की विधानसभा के लिए होगा या केंद्रशासित क्षेत्र के लिए यह तय नहीं है। और प्रधानमंत्री का बयान भी उस पर कोई रोशनी नहीं डालता है।

कानून-व्यवस्था की चुनौती | इसमें दो राय नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगी है। लेकिन फिर भी ये घटनाएं पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं। खासकर पीएम मोदी की यात्रा से कुछ पहले हुई घटनाएं बताती हैं कि आतंकी तत्व अपनी मौजूदगी का अहसास कराने की कोशिश से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में चुनावों के दौरान उनकी तरफ से बाधा डालने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

370 के बाद | पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को हासिल विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद किए गए कार्यों का उल्लेख किया और बताया कि कैसे उसके बाद विकास का फल राज्य के लोगों तक ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में पहुंच रहा है। लेकिन इस बारे में राज्य के लोगों की क्या राय है यह चुनावों से जाहिर होगा।

समयसीमा आगे न बढ़े | लोकसभा चुनावों में वोटिंग का दशकों पुराना रेकॉर्ड टूटना जरूर एक उपलब्धि है जो बताती है कि आतंकी तत्वों की लाख कोशिशों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया के जरिए मुख्यधारा से जुड़ने की आम लोगों की इच्छा कम नहीं हुई है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी सूरत में चुनाव की सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समयसीमा आगे न बढ़ने दी जाए।

दो दूनी चार
कुछ नया चाहिए

रमेश तिवारी

बजट में हर साल कई बदलाव होते हैं। लेकिन जनता की चाहत कभी नहीं बदलती। इनकम टैक्स की दर कम हो, इसे कैलकुलेट करना आसान हो, कुल मिलाकर उसकी यही चाहत होती है। कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश करेंगी। नई सरकार का यह पहला बजट होगा। आम चुनाव पांच साल दूर हैं, लेकिन टैक्स छूट की संभावनाओं पर लगातार चर्चा हो रही है।

सिस्टम को आसान बनाने और टैक्स कम करने के मकसद से ही 2020 में न्यू टैक्स रिजीम लाया गया, लेकिन इसमें लगभग सारे डिडक्शन खत्म कर दिए गए। डिडक्शन मतलब टैक्स बचाने के लिए कुछ रकम इन्वेस्ट करना होगा, इस आदत को मिटाने की कोशिश की गई। शुरुआत में तो ये लोगों की पसंद नहीं बन पाया। बाद में टैक्स में कमी करके न्यू टैक्स रिजीम में बड़े सुधार किए गए, जिससे लोग जुड़े भी। लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। समझा जाता है कि 60 फीसदी टैक्सपेयर्स ने न्यू टैक्स रिजीम को चुन लिया है। इस संख्या को और बढ़ाने की गुंजाइश है। जिनके पास बड़ा होम लोन है, वो अब भी ओल्ड रिजीम को फायदेमंद देख रहे हैं। न्यू रिजीम में 15 लाख की कमाई पर ही 30 पर्सेंट टैक्स शुरू हो जाता है, जिसे 20 लाख किए जाने की जरूरत समझी जा रही है।

ओल्ड रिजीम में टैक्स बचाने के लिए अभी तक लोग एफडी, पीएफ, इंश्योरेंस जैसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते थे। सेक्शन 80 सी के नाम से पॉपुलर इस इंतजाम में डेढ़ लाख रुपये तक इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन 2014 से ये लिमिट नहीं बदली है। वैसे भी एफडी और पीएफ का आकर्षण कम होता दिख रहा है। शेयर बाजार और रियल एस्टेट युवा पीढ़ी की पसंद बन रहे हैं। इन असेट्स के मुनाफे पर कैपिटल गेंस टैक्स की जो व्यवस्था है, वो जटिल है। वहां अलग-अलग असेट क्लास में होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स बदल जाता है। इसकी जटिलता को खत्म करने से भी सिस्टम आसान बनेगा।

कई बरसों से टैक्स की दरें कम होती गई हैं। इससे टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ी है। करीब एक दशक में ये संख्या डबल के करीब बढ़ी है। लेकिन बड़ी आबादी आज भी इसके दायरे में नहीं है। एक बात और, पर्सनल इनकम टैक्स का असर जितने लोगों पर पड़ता है, उससे ज्यादा असर जीएसटी का पड़ता है। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। इससे ईंधन सस्ता तो हो सकता है, लेकिन राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शनिवार को होनी है। बजट से पहले केंद्र सरकार इस मीटिंग में राज्यों की चिंता दूर करने की कोशिश कर सकती है।

अगर इस वक्त का आर्थिक माहौल देखें तो दो तस्वीरें नजर आएंगी। एक तरफ देश आंकड़ों में तेज रफ्तार से तरक्की कर रहा है। दूसरी तरफ घरेलू खपत में कमी दर्ज की गई है। प्राइवेट सेक्टर निवेश से बच रहा है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि डिमांड में कमी हो सकती है। निचले स्तर पर टैक्स स्ट्रक्चर ठीक किया जाए तो घरेलू खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। नतीजा ये होगा कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

ऑफ दि ट्रैक
बारहसिंगा जैसा डायनासोर
दिलीप लाल

डायनासोर के बारे में जब भी कोई नई खोज सामने आती है, तो वह वैज्ञानिकों के लिए एक सुखांत कहानी के तौर पर दर्ज होती है। इसमें कहानी का अंत जंगलों में नहीं, संग्राहलयों में होता है। डायनासोर से जुड़े किसी नए विवरण का प्रमाण मिलता है, तो उसे सावधानी से संरक्षित किया जाता है। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस युग के अंत में एक बड़ा क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिसके परिणामस्वरूप डायनासोरों का व्यापक विनाश हुआ। इस घटना के कारण अधिकांश बड़े डायनासोर विलुप्त हो गए। पक्षियों को डायनासोरों के ही परिवर्तित रूप में भी देखा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी थेरोपोड डायनासोरों के एक समूह से विकसित हुए हैं। खास बात यह कि वैज्ञानिकों ने डायनासोरों की एक नई प्रजाति खोजने का दावा किया है। उत्तरी अमेरिका में मिले इस जीवाश्म की स्टडी के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रजाति के डायनासोर खासे विशाल होते थे। करीब 22 फुट लंबे इस डायनासोर का वजन 5 हजार किलोग्राम तक होता था। यह डायनासोर 7.8 करोड़ साल पहले मोंटाना के दलदल में घूमता था। इस डायनासोर की पहचान कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की और इसे Lokiceratops rangiformis नाम दिया। झालरनुमा घुमावदार ब्लेड जैसी बेतरतीब सींगों के कारण इसकी तुलना बारहसिंगा से की जाती है।

एजुकेशन सिस्टम भी बच्चों के लिए फोन को ज़रूरी बना रहा
बच्चों को कब देना चाहिए फोन

मुकुल श्रीवास्तव

AI Image

स्मार्टफोन की बच्चों को कितनी जरूरत है। यह एक अहम सवाल है। अफसोस कि भारत में इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फर्ज करिए, अगर आपकी 10 साल की बेटी को मंगल ग्रह की पहली मानव बस्ती में शामिल होने के लिए चुना जाए, और वह जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, तभी आपको पता चले कि इस मिशन के अरबपति आर्किटेक्ट ने उस लाल ग्रह के जहरीले वातावरण को नजरअंदाज किया है, जिसमें बच्चों के दिल, दिमाग और आंखों में गंभीर विकृतियां आ जाएंगी, तो क्या सबकुछ जानने के बाद भी आप अपनी बेटी को उस मिशन पर जाने देंगे? यह कोशिश नहीं करेंगे कि वह लाल ग्रह पर जाने के उस मिशन से मुंह मोड़ ले?

ब्लैक मिरर | जोनाथन हैड्ट ने अपनी किताब 'The Anxious Generation' की शुरुआत इसी उदाहरण से की है, जिसे ब्लैक मिरर कहा गया है। इस उदाहरण में मंगल ग्रह को सोशल मीडिया की खतरनाक दुनिया का प्रतीक माना गया है। कॉमन सेंस मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आज 10 साल की उम्र वाले 42% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। 12 साल की उम्र में यह 71% तक पहुंच जाता है। 14 साल के उम्र समूह में तो 91% बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है।

युवाओं में डिप्रेशन | इस डिजिटल दुनिया ने हमारे युवाओं को चिंता और डिप्रेशन जैसी विकृतियों से भर दिया है। मोबाइल फोन एक लत की तरह है, लगातार बच्चों का ध्यान भटकाता है और उन्हें उस दुनिया में ले जाता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। भारत में एक बड़ा बदलाव 2000 के दशक से शुरू हुआ, जब अभिभावकों ने बच्चों को अनजान खतरों से बचाने के लिए भय आधारित पैरेंटिंग करनी शुरू की। इसकेनी ऐसी पैरेंटिंग जिसमें बच्चों पर ज्यादा नजर रखी जाती थी, यह ध्यान रखा जाता था कि वह घर की सुरक्षित दुनिया से बाहर ज्यादा समय न बिताए। इसका परिणाम यह रहा कि बच्चों के खेलने का समय कम हुआ और उन पर माता-पिता का नियंत्रण बढ़ गया। दूसरी बात यह कि शहरों में खेल के मैदान खत्म होते गए। नतीजा कुल मिलाकर यह रहा कि बच्चे मोबाइल स्क्रीन में डूबते चले गए।

कैसे हो रहा नुकसान
- भावनात्मक स्थिरता प्रभावित
- चिंता, डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे
- शिक्षकों में भी बढ़ता है तनाव

डिफेंस मोड में बच्चे-अभिभावक | आज के बच्चे और उनके माता-पिता एक तरह के डिफेंस मोड में फंसे हुए हैं। इससे बच्चे चुनौतियों का सामना करने, जोखिम उठाने और नई चीजें एक्सप्लोर करने से वंचित रह जाते हैं, जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है।

गलत नजरिया | असल में बच्चों को माता-पिता से वैसी ही परिस्थितियां मिलनी चाहिए जैसी एक माली अपने पौधों को स्वाभाविक रूप से बढ़ने और विकसित होने के लिए उपलब्ध कराता है। मगर अभिभावक हैं कि बच्चों को एक बढ़ई की तरह बड़ा कर रहे हैं जो अपने सांचों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में आकार देता है।

डिजिटल दुनिया | असली दुनिया में हम अपने बच्चों को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। स्मार्टफोन और अत्यधिक सुरक्षात्मक पालन-पोषण के इस मिश्रण ने बचपन की संरचना को बदल दिया है और मेंटल हेल्थ ईशूज को जन्म दे रहा है।

भावनात्मक स्थिरता पर प्रभाव | संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति एजेंसी यूनेस्को के मुताबिक इस बात के प्रमाण मिले हैं कि मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी से जुड़ा है और स्क्रीन के अधिक समय का बच्चों की भावनात्मक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यूनेस्को ने अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट 2023 में लिखा है कि डिजिटल तकनीक ने शिक्षा में गुणवत्ता जोड़ी है, यह प्रदर्शित करने के लिए बहुत कम मजबूत शोध हुए हैं। इस बाबत दिए गए ज्यादातर साक्ष्य निजी शिक्षा कंपनियों द्वारा वित्त पोषित थे, जो डिजिटल शिक्षण उत्पाद बेचने की कोशिश कर रही थीं।

चीन ने बांधी सीमा | इस रिपोर्ट में चीन का हवाला दिया गया है, जिसने शिक्षा में डिजिटल उपकरणों के उपयोग की सीमाएं निर्धारित कर दी हैं। वहां उन्हें कुल शिक्षण समय के 30% तक सीमित कर दिया गया है और छात्रों से नियमित तौर पर स्क्रीन ब्रेक लेने की अपेक्षा की जाती है।

सेकंड हैंड स्मोक | फोन लोगों में सीखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया कि स्कूल में फोन का इस्तेमाल एकाग्रता को कम करता है। खास बात यह कि फोन का इस्तेमाल सिर्फ उपयोगकर्ता को ही नहीं प्रभावित करता। फोन फ्री स्कूल आंदोलन की संस्थापक साबिने पोलाक ने इसके लिए 'सेकंड हैंड स्मोक' टर्म इजाद किया है। जिस तरह किसी व्यक्ति के द्वारा छोड़ा गया सिगरेट का धुआं पास खड़े व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह भले किसी छात्र के पास फोन न हो, वह क्लास में दूसरों द्वारा फोन के इस्तेमाल से प्रभावित होता है। यह उपकरण शिक्षकों में भी तनाव बढ़ाता है।

मोबाइल मैनर | भारत में अभी तक इस दिशा में कोई ठोस पहल न होना चिंता का विषय है। मगर अभिभावक अपने स्तर पर भी प्रयास कर सकते हैं। बेहतर होगा वे अपने बच्चों को स्मार्टफोन देने में देरी करें और स्कूल इस फैसले में उनका समर्थन करें। अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए माता-पिता फ्लिप फोन, स्मार्ट वॉच, ट्रैकिंग डिवाइसेस जैसे उपकरणों की मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि अब बच्चों को जीवन जीने के तौर-तरीके सिखाने के साथ-साथ मोबाइल मैनर भी सिखाए जाएं।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में जर्नलिज्म के प्रफेसर हैं)

कैसे लौटी Huawei

चीनी कंपनी Huawei पर सरकार के लिए जासूसी के आरोप लगे। US ने प्रतिबंध लगा दिए। भारत में भी कंपनी का काम सिमट गया। मुनाफा 70% तक गिर गया। हुवावे ने कैसे वापसी की, जानते हैं :

AI image

नए बिजनेस तलाशे
Huawei मुख्य रूप से टेलिकॉम नेटवर्क उपकरण बनाती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इसने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। स्मार्टफोन के अलावा कंपनी टेलिविजन, घड़ियां और EV को कंट्रोल करने वाले सिस्टम भी बना रही है।

रिसर्च पर फोकस
Microsoft ने चीन में कारोबार समेट लिया है। Huawei ने माइक्रोसॉफ्ट के तमाम इंजीनियरों को हायर कर लिया। कंपनी का फोकस है इनोवेशन पर। रिसर्च एंड डिवेलपमेंट में 1.14 लाख कर्मचारी लगाए गए हैं।

अपना टेक सपोर्ट
बैन से सबसे ज्यादा असर पड़ा टेक सपोर्ट पर। कंपनी अपनी intellectual property (IP) डिवेलप कर रही है। अमेरिकी बैन के बाद से 13 हजार विदेशी पार्ट्स की जगह चीनी सामानों ने ली है। पिछले साल Huawei ने Mate60 Pro+ फोन लॉन्च किया, जिसमें 70% कंपोनेंट्स चीनी थे। चीन में स्मार्टफोन्स की कुल बिक्री में हुवावे के इस फोन का शेयर 15.5% रहा।

हितों में निवेश
Huawei ने Hubble नाम से इन्वेस्टमेंट यूनिट बनाई है। इसका काम है उन फर्म्स में हिस्सेदारी खरीदना, जो उसे पार्ट्स और सिस्टम सप्लाई करती हैं। इसने दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी TSMC और ASML में निवेश किया है। 5G, ग्रीन एनर्जी और पावर सेक्टर में पैसे लगाए हैं।

देसी ऑपरेटिंग सिस्टम
Huawei ने एक नया प्रोग्राम डिवेलप किया, Metaerp। इसी तरह Android का एक्सेस बंद होने के बाद कंपनी ने अपने गैजेट्स के लिए खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम Harmony बनाया। उसके सारे कंस्यूमर प्रॉडक्ट्स इस सिस्टम पर चल सकते हैं।

प्रस्तुति : **शैलेंद्र पांडेय**

हवा में बनारस घराने की महिमा गूंजती है

सप्ताह का इंटरव्यू
पंडित छन्नूलाल मिश्र

शास्त्रीय संगीत के साधक, उपासक और आराधक पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र 87 वर्ष के हो चुके हैं। शास्त्रीय संगीत शब्द सुनते ही उनमें फिर बच्चों जैसी चंचलता, निश्छलता और कोमलता उछलकूद करने लगती है। उनसे बात करना गुरु से हमेशा कुछ नया पाने जैसा होता है। उनसे बात की ***सलिल पाण्डेय*** *ने। पेश हैं बातचीत के अहम अंश :*

Shital Verma

■ **गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी में गाने और गर्मी भगाने के कौन-कौन से राग या गीत परंपराएं हैं?**

देखिए गर्मी को निष्प्रभावी तो पानी से किया जा सकता है। इसलिए कजली (कजरी) गीत गाए जाते थे। साधना उत्तम हो तो 'बरसन लागी बदरिया हो रामा' कजली गीत गाए जाने पर बादलों में हलचल मचने लगती है। ग्रीष्म ऋतु की तपिश से छुटकारे के लिए वर्षा ऋतु में कजली गीत गाते ही आकाश में सूरज की सत्ता बेदखल होने लगती है और बादलों का साम्राज्य छाने लगता है। वर्षा ऋतु के गीत कजली को वार्षी छंद कहा जाता है। कजली गीत योगेश्वर श्रीकृष्ण की बहन योगमाया के कंस के हाथों से छूटकर धरती पर आने के मौके पर गाए जाने से भी संबंधित है। विंध्य पर्वत पर योगमाया का अवतरण हुआ। इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जब मातृ-शक्ति आसपास होती है तो शीतलता और सुकून का अहसास ज्यादा होता है।

■ **बनारस में पीएम मोदी के आने के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। अब इस बदले हुए बनारस को कैसे देखते हैं, कैसा पाते हैं?**

उनके आते ही बनारस सच में बन गया और रसदार हो गया। रूप-रंग संवर गया। संकरापन खत्म हुआ। काशी विशाल और विराट हुई। सड़कें खूबसूरत और चौड़ी हुईं। रफ्तार तेज हुई।

■ **आस्था की काशी कहीं पर्यटन और पिकनिक की काशी तो नहीं हो गई?**

'मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्नाः। इसे 'जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन जैसी' भी कह सकते हैं। यह बाबा विश्वनाथ की तीन लोकों से न्यारी काशी है। महादेव जबान की नहीं, मन की आवाज सुनते हैं।

■ **आप 5 साल की उम्र से ही संगीत सेवा कर रहे हैं। इतने लंबे सफर में क्या छूटा, क्या पाया?**

संगीत में भगवान बसते हैं। खुद लीलाधारी भगवान विष्णु कहते हैं, 'नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायंति तत्र तिष्ठामि नारद!' इसका अर्थ है, 'हे देवर्षि ! मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूं और न ही योगी-जनों के हृदय में निवास करता हूं। मैं तो उन भक्तों के पास रहता हूं जहां भक्तगण मेरे नामों का गायन करते हैं। यहां भगवान ने 'भजंति' और 'ध्यायंति' का उल्लेख नहीं किया बल्कि 'गायंति' का जिक्र किया है। तो मैं कह सकता हूं कि जितनी मैंने साधना की, उससे कहीं अधिक इतना हाथ लगा है कि बांटते और लुटाते भी खत्म नहीं हो रहा है। संगीत किसी को दुखी नहीं करता तो मुझे ही क्यों दुखी करेगा?

■ **आपका जगप्रसिद्ध होली गीत है- 'खेलें मसाने में होली दिगंबर।' पिछले दिनों कुछ लोग वाकई मणिकर्णिका के मसान में होली खेलने पहुंच गए थे। इसे कैसे देखते हैं?**

बड़ी आध्यात्मिक महत्ता की बात है। मसान में होली केवल काल के देवता महाकाल स्वरूप महादेव ही खेल सकते हैं। मृत्यु प्रलय है। प्रलय के द्रष्टा महादेव हैं। 'नाचत गावत डमरू बजावत' की क्षमता किसी और देवता में नहीं है तो सामान्य इंसान की बात ही क्या है? यशोदा के लल्ला कन्हैया होली में गोपिकाओं संग होली खेलते हैं, परंतु महादेव 'मृत्यु की राह में स्थित मणिकर्णिका' में निरंतर होली खेलते हैं। मृत्यु शाश्वत सत्य है। इसलिए अपने भूत-प्रेतों तक को अनियंत्रित होने से रोकने के लिए महादेव 'मसान-पीठ' पर जा विराजे। जहां तक मणिकर्णिका पर जाकर होली खेलने की बात है तो मसान में सामान्य लोगों को गाना या नृत्य नहीं करना चाहिए। महादेव के नृत्य का स्वरूप भी अलग-अलग है। जब मां पार्वती को नृत्य का अवसर महादेव देते हैं तो वह 'लास्य नृत्य' कहलाता है। यही लास्य नृत्य नारी के कोमल भाव का रूप है, जबकि महादेव के तांडव नृत्य को 'नृत' कहा जाता है। यह पुरुष सूचक नृत्य है। शिव तांडव के श्लोकों में नारी जैसा लास्य

> “ मसान में होली केवल काल के देवता महाकाल स्वरूप महादेव ही खेल सकते हैं। मृत्यु प्रलय है। प्रलय के द्रष्टा महादेव हैं। 'नाचत गावत डमरू बजावत' की क्षमता किसी और देवता में नहीं है तो सामान्य इंसान की बात ही क्या है? अपने भूत-प्रेतों तक को अनियंत्रित होने से रोकने के लिए महादेव 'मसान-पीठ' पर जा विराजे

तथा पुरुष जैसा नृत दोनों समाहित है। जन्म-मृत्यु दो स्थितियों से हर कोई गुजरता है। जन्म के समय 'सोहर गीत' गाया जाता है जबकि मृत्यु पर निर्गुण। इसलिए श्मशान पर सिर्फ निर्गुण ही गाया जाना चाहिए।

■ **आजकल सिखाने वाले सब कुछ सिखाने से बचते हैं। लोग भी कहते हैं कि सब कुछ मत सिखाना, कुछ खुद के लिए भी बचाकर रखना। क्या वाकई में कुछ बच पाता है?**

अखिल ब्रह्मांड की अनंतता और समुद्र के जल जैसा गहरा संगीत का भी सागर है। 'दोऊ हाथ उलीचिए' भाव संगीत के गुरु को भी रखना चाहिए। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य की गुरुता यानी वजन को बढ़ा दे।

■ **आपने आजादी के बाद संगीत का पूरा वक्त देखा है। कम से कम 70 साल तो हो ही गए आपको संगीत की दुनिया में होश संभाले। इतने लंबे समय में क्या बदला, क्या छूटा, क्या बना रह गया?**

शास्त्रीय विधि से गाए जाने वाला गीत जन-मन-रंजन का माहौल बनाता है। सिर्फ राग अलापने को शास्त्रीय संगीत नहीं कह सकते। इधर राग अलापने की प्रवृत्ति बढ़ी है। शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का सम्यक ज्ञान आवश्यक है। फिल्मों के गीतों ने शास्त्रीय संगीत के उत्थान में उल्लेखनीय भूमिका अदा नहीं की है। कभी-कभी कुछ गीत प्रभाव छोड़ते हैं। 'मधुवन में राधिका नाचे रे' गीत लोकप्रिय हुआ है। शास्त्रीय संगीत के लिए प्रारंभिक स्तर पर 6 राग और 30 रागिनियों को समझने की जरूरत होती है।

■ **संगीत के क्षेत्र में बनारस घराने की स्थिति और योगदान पर क्या कहेंगे?**

घरानों में सिरमौर है बनारस घराना। इसके गुरु तुंबरु ऋषि थे। इन्होंने नारद को संगीत में दीक्षित-प्रशिक्षित किया था। 'केशव कहि न जाई का कहियो' पद से इसकी विशेषता समझी जा सकती है। अशरीरी ब्रह्म के मुख से यह भाव प्रकट हुआ। इसका अर्थ यही है कि वायु तरंगों में बनारस घराने की महिमा गूंजती रहती है।

जाना किधर है मगहर बताता है

खुद अपनी आंख से
आशुतोष द्विवेदी

उत्तर प्रदेश में है संत कबीर नगर, और इसी नगर का कस्बा है मगहर। मगहर बुद्ध काल से ही इसलिए बदनाम था कि यहां विस्तृत-विशाल जंगल, ऊसर और आमी नदी के कारण रेतीला क्षेत्र था। एक ऐसा इलाका, जहां अक्सर लोग रास्ता भटक जाते और फिर लुटेरों, रहजनों द्वारा हर लिए जाते। इसी से बना मग+हर= मगहर, यानी जहां मार्ग का हरण हो जाए, जहां लोग रास्ता भूल जाएं। लेकिन स्थायी कुछ नहीं है तो मगहर का यह अर्थ भला कैसे बना रह पाता। बाद में इसमें कुछ बदलाव हुआ। कहावतें और मान्यताएं यहां तक पहुंच गई कि मगहर में जो देह त्यागता है, उसे स्वर्ग नहीं, बल्कि नर्क ही मिलता है।

पहली बार जब मगहर में प्रवेश किया तो काफी तलाश करने के बावजूद इस कस्बे में ऐसी कोई बात नहीं दिखी, जो इसे काशी या देश की किसी और जगह से अलग करती हो। यह एक आम-सा कस्बा है। काशी या अयोध्या की तरह ही यहां भी वैसे ही पक्षी, पेड़, रास्ते, खेत, लोग, व्यवहार, बतकही। बचपन में मां शाम को हम भाइयों को लेकर बैठतीं और तरह-तरह के संतों की कहानियां सुनाती थीं। मां काशी की भी कहानियां सुनातीं थीं, जब पिताजी का वहां ट्रांसफर हुआ था। इन कहानियों में अक्सर कबीर चौरा और लहरतारा का नाम आता। असल में मां और पिताजी लहरतारा में ही रहते थे। मां लहरतारा से रोज कबीर चौरा होते हुए गंगा स्नान के लिए जाती थीं। एक दिन लहरतारा और कबीर चौरा के संबंध में मां ने संत कबीर की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह से कबीर तालाब के किनारे पाए गए थे। फिर एक जुलाहे ने उनको देखा तो अपने घर ले आया। जुलाहे ने ही उनका पालन-पोषण किया। वहीं उन्होंने दोहे कहने शुरू किए। कबीर कपड़ा बुनते जाते, और साथ-साथ दोहे भी बुनते। ऐसे दोहे, जिन्होंने समूची मानवता को एक नई राह दिखाई, नया मार्ग दिया। कहानी सुनाने के बाद वह बोलीं कि इस भ्रम में मत रहो कि किसी स्थान विशेष पर देह त्यागने से स्वर्ग और नरक मिलता है। यही सोचकर कबीर भी मगहर चले गए थे कि मरने की जगह कुछ तय नहीं करती।

संत कबीर के इस जीवन वृत्त और वृत्ति से मैं स्वयं को सबसे अधिक प्रभावित पाता था। तभी से काशी से अधिक मगहर और वहां उनकी समाधि और कब्र पर दो समुदायों का व्यवहार देखने की बड़ी इच्छा थी। मगहर देखने का सपना रह-रहकर आंखों में डोल उठता था। और आखिरकार उस दिन मैं मगहर में था।

मगहर में बहती रही होगी कभी आमी नदी, जब मैं पहुंचा तो लगभग सूख चुकी थी। इसी आमी नदी के किनारे बनी संत कबीर की समाधि और कब्र। दोनों ही एक परिसर में हैं। उसकी सीढ़ियां चढ़ते समय विचार आया कि पहले किस में जाऊं? शायद सभी को आता होगा। दोनों से कुछ मीटर दूर बीच में खड़े होकर सोचता रहा। फिर ध्यान आया, यही तो मग+हर है। यहां आकर ऐसे सवाल बेमानी हो जाते हैं कि किधर जाएं। हरि की ओर जाने के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कबीर बाबा बता गए थे। और यह मग यानी मार्ग मानवता के लिए ही है।

(लेखक संत कबीर अकादमी, यूपी के प्रबंध सलाहकार हैं)

चलते-चलते...

वॉशिंगटन में रहने वाली हिस्लॉप ने 105 साल की उम्र में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने 1940 में ही स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्स में एडमिशन लिया था। लेकिन बॉयफ्रेंड जॉर्ज को द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा देने के लिए बुला लिए जाने के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। 89 साल लगे, पर आखिरकार उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई का मलाल दूर कर लिया।

रीडर्स मेल

▸ रवैया बदले पाक
21 जून का लेख 'क्या पड़ोसियों से रिश्ते सुधार पाएंगे मोदी' पढ़ा। वैश्विक मंच पर भारत की साख में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले लगभग दो दशकों से देश-दुनिया के विकसित मुल्कों ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लोहा माना है। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालते ही मोदी का G7 शिखर सम्मलेन में भाग लेना भी भारत के बढ़ते कद का ही परिचायक है। बहरहाल, इस समय हमें सतर्क होकर चलना चाहिए क्योंकि एक विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने के साथ-साथ हमें अपने पड़ोसी मुल्कों जैसे चीन और पाकिस्तान से तल्ख होते रिश्तों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बार कह चुके हैं कि अलगाववाद और आतंकवाद का रास्ता छोड़कर ही शांति और विकास की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। खासकर पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह सीख ज्यादा अहमियत रखती है। उसे समझना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति आखिरकार उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

▸ नया गठजोड़
यह पत्र 20 जून के संपादकीय 'तानाशाहों का गठजोड़' से संबंधित है। 24 साल बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन की उत्तर कोरिया यात्रा ने न सिर्फ चौंकाया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय हलकों में चिंता भी बढ़ाई है। अब तक उत्तर कोरिया के तानाशाह किमजोंग उन को सिर्फ चीन से संरक्षण मिल रहा था। ऐसे में अब रूसी राष्ट्रपति पूतिन की उनसे बढ़ती करीबी भविष्य के खतरे का संकेत दे रही है। 'बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा' वाले हालात बन रहे हैं। रूस-यूक्रेन और इस्राइल-हमास युद्ध के चलते दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है। उत्तर कोरिया, रूस, चीन के राष्ट्राध्यक्ष खुले तौर पर तानाशाह हैं। इन तीनों का गठजोड़ दुनिया के लिए वाकई घातक सिद्ध हो सकता है। निश्चित रूप से इस उभरते गठजोड़ पर नजर रखने की जरूरत है।

सुभाष बुडावन वाला, ईमेल से

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 22 जून • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

अपने शब्द उठाओ, आवाज नहीं
-मौलाना रूमी

तार्किक हो कोटा

पटना हाई कोर्ट ने 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत किए गए राज्य सरकार के आरक्षण को रद्द कर दिया है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार को तगड़ा झटका माना जा रहा है। यह दलितों, पिछड़े वर्गों व आदिवासियों को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा था। बिहार की तत्कालीन महागठबंधन सरकार द्वारा बीते साल नवम्बर में जाति गणना के आधार पर इन वर्गों के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने का कानून बनाया गया था। अदालत ने विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद इस बढ़ी आरक्षण सीमा को संविधान के अनुच्छेद 14, 16 व 20 का उल्लंघन बताया। जैसा कि शीर्ष अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि कोई भी राज्य सरकार 50 प्रतिशत की तय सीमा से अधिक कोटा नहीं लागू कर सकती है, जबकि

बिहार में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 फीसद मिलाकर यह आरक्षण 75 प्रतिशत पहुंच गया था। अदालत का मानना है कि बिहार में कुल जनसंख्या के केवल 1.57 प्रतिशत लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी पर्याप्त बताया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। दरअसल, जैसा नजर आता है कि आरक्षण अब राजनीतिक पार्टियों के लिए जनता को फुसलाने का साधन मात्र रह गया है। उनका ध्येय समाज में व्याप्त गैर-बराबरी को मिटाना नहीं रहा। वे मतदाताओं को बड़ी तादाद में प्रभावित करने के उद्देश्य से व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। तमाम अगड़ी जातियां मानती हैं कि आरक्षण के चलते नौकरियों क लाले पड़ रहे हैं। वे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रभावित होने का रोना भी रोती रहती हैं, परंतु यह भी गलत नहीं है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न जातियों/समुदायों को जबरदस्त अन्याय सहना पड़ा है। उनके लिए कोटा तय कर, उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक तौर पर बराबरी पर लाने के प्रयासों पर अड़चनें लाने उचित नहीं है। यूं तो अन्य राज्यों में भी सत्ताधारी दल लाभ के लोभ में कोटा बढ़ाते रहने को उतावले हो सकते हैं। इसलिए बिना देरी किए, इस पर लगाम लगाना लाजमी है। कमजोर वर्ग की सहूलियत के लिए, उन्हें सहायता देने व जीवन स्तर बेहतर बनाने के अन्य तरीकों पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।

कश्मीर में चुनाव की बयार

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में थे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका कश्मीर का यह पहला दौरा है। आतंकी हमलों के बीच मोदी का कश्मीर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया। पिछले दिनों यहां लगातार चार आतंकी हमले हुए जिन्होंने सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में हिचकिचाएंगे नहीं। लोक सभा का चुनाव यहां शांतिपूर्ण हुआ और लोगों ने उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया। जाहिर है इसके कारण मतदान प्रतिशत में भारी इजाफा हुआ। अलगाववादियों और आतंकवादियों को यह पसंद नहीं आया और

उन्होंने एक के बाद एक हमले किए जिनमें तीर्थयात्री भी शामिल थे। वास्तव में आतंकी विश्व जनमत को संदेश देना चाहते थे कि कश्मीर में सबकुछ सामान्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार प्रदेश में लोक सभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जिस उत्साह से घरों से बाहर निकले उससे प्रधानमंत्री मोदी भी उत्साहित हुए। उन्होंने कहा कि सबको बांटने वाले अनुच्छेद 370 की दीवार अब गिर चुकी है। वास्तव में 5 अगस्त, 2019 का ऐतिहासिक दिन कश्मीर और समूचे भारतवासियों के लिए बंदिशों से आजादी का दिन था। अब यहां पर्यटक बेखौफ होकर आ रहे हैं। युवा वर्ग अपने करियर के बारे में जागरूक हो गया है। अनुकूल वातावरण को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे और इस केंद्रशासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कश्मीर के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नजरिये 'इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत' को याद करते हुए कहा कि इसे हम हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द होंगे और लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। लेकिन केंद्र सरकार को सतर्क रहना होगा क्योंकि आतंकवादी चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का हरसंभव प्रयास करेंगे।

कटाक्ष/ कबीरदास

पर इस्तीफा, कभी नहीं!

ये तो विरोधियों की घनघोर टाइप की ज्यादती है। पहले इसकी रट लगा रखी थी कि नीट परीक्षा में गड़बड़-घोटाले के लिए नैतिक जिम्मेदारी लो। शिक्षा मंत्री ले, एनटीए के निदेाक ले, कोई तो नैतिक जिम्मेदारी लो। और अब जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिक जिम्मेदारी मान ली है, तो भाई लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी और लगे मंत्री जी का इस्तीफा मांगने। जिम्मेदारी लेने की बात से सीधे इस्तीफा देने की मांग पर आ गए; ऐसी धोखाधड़ी इस अपोजीशन की!

वह तो अच्छा हुआ कि मोदी जी ने अपने राज के शुरू में ही साफ कर दिया था कि कुछ भी हो जाए, उनकी सरकार में किसी का इस्तीफा नहीं होगा। माने छुट्टी भी, नई भर्ती भी, सब कुछ होगा तो सही; पर वही होगा जो मोदी रचि राखा होगा। पर दूसरों के कहने से ही नई भर्ती, इस्तीफा, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इतना साफ-साफ कह देने के बाद भी मोदी जी कोई इस्तीफों की मांग से साफ बच गए हों। गुजरे दस साल में इस्तीफे की मांग का शोर उठा, बार-बार उठा। पर इस्तीफा मांगने वाले जानते थे कि कुछ भी हो, इस्तीफा नहीं मिलेगा। पब्लिक सब देख-समझ रही थी कि कोई कुछ भी कर ले, इस्तीफा नहीं होगा। सो इस्तीफा नहीं हुआ। और जब बाकी किसी का वैसा वाला इस्तीफा भी नहीं हुआ, कि पब्लिक मांगे और ना-ना करते-करते मंत्री आखिर में इस्तीफा दे डाले, फिर किसी के मोदी जी का इस्तीफा मांगने का तो सवाल ही कहां उठना था। छप्पन इंच की छाती इंतजार ही करती रह गई, पर उसे इस्तीफे की मांग को खारिज करने का, मौका ही नहीं मिला।

सब अच्छा-भला चल रहा था, न कोई इस्तीफा, न इस्तीफे की मांग का ज्यादा कोई शोर। पर तभी पब्लिक पगला गई। चार सौ पार वालों को, तीन सौ से भी नीचे खिसका दिया। मोदी जी के सिंहासन की टांगें तोड़कर, नीतीश और नायडू की बैसाखियां फिट कर दीं। ऊपर से पहले दिन से इस्तीफे की मांग पर मांग। नीट और नेट के लिए प्रधानजी का इस्तीफा; कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना के लिए वैष्णव जी का इस्तीफा; जम्मू-कमीर में आतंकवादी वारदातों के लिए शाह साहब का इस्तीफा। यूं ही चला तो इस बार डिमांड कहीं मोदी जी के इस्तीफे तक न पहुंच जाए। सो और जोर से बोलो, इस्तीफा कभी नहीं!

बड़ी चुनौती है नौकरी

मोदी सरकार

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

यकीनन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नई एनडीए गठबंधन सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती नौकरियों और रोजगार अवसरों में वृद्धि करने की है। हाल ही में दुनिया में आर्थिक और रोजगार से संबंधित शोध अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध फ्रांस के कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्सि एसए के द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिस तेजी से युवा रोजगार के लिए तैयार होकर श्रम शक्ति (वर्क फोर्स) में शामिल हो रहे हैं, उसको देखते हुए भारत को 2030 तक प्रति वर्ष 1.65 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत होगी। इसमें से करीब 1.04 करोड़ नौकरियां संगठित सेक्टर में पैदा करनी होंगी। जबकि पिछले दशक में सालाना कुल 1.24 करोड़ नौकरियां ही पैदा हो सकी थीं।

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी को बरकरार रखने के लिए सर्विसेज से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सभी सेक्टर्स को नई रफ्तार से बढ़ावा देना होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी में से 83 फीसद बेरोजगार युवा थे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, भारत की कुल श्रम शक्ति की भागीदारी दर मात्र 58 प्रतिशत है, जो भारत के एशियाई समकक्ष देशों की तुलना में बहुत कम है। निसंदेह नई गठबंधन सरकार को बेरोजगारी संबंधी चिंताजनक नए आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा। हाल ही पिछले दस वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग रेलवे भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जो भर्तियां की हैं, वे रिक्त पदों की तुलना में कम बहुत है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) के द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी से मार्च 2024) में बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गई है, जो इसके पहले की तिमाही में 6.5 प्रतिशत थी। शहरी बेरोजगारी पिछली चार तिमाही के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 15 साल से अधिक उम्र में बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2023 की तिमाही के 6.8 प्रतिशत के बाद सर्वाधिक है। सर्वेक्षण के अनुसार युवा बेरोजगारी स्तर बढ़ा है और यह बीती तिमाही के 16.5 प्रतिशत से बढ़कर चौथी तिमाही में 17 प्रतिशत हो गया। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस आयु वर्ग के लोग पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इससे शहरी रोजगार के बाजार में गिरावट का पता चलता है। अब नई सरकार के द्वारा देश में असंगठित सेक्टर लघु एवं मध्यम उद्योगों और गिग वर्कर्स की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाना होगा। इन सेक्टरों में करोड़ों

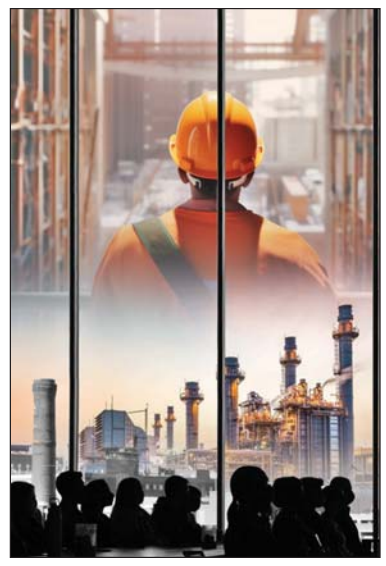

लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन भविष्य एकदम सुरक्षित नहीं है। जून 2022 में प्रस्तुत नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 77 लाख लोग इस समय गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अनुमान है कि 2029-30 तक इनकी संख्या 2.35 करोड़ हो जाएगी।

गिग वर्कर्स के लिए बड़ी समस्या नौकरी जाने का खतरा और प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलना है। देश में रोजगार के मद्देनजर महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है। नैसकॉम के मुताबिक भारत के प्रौद्योगिकी कार्यबल में केवल 36 फीसद महिलाएं हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों में महिलाओं की भागीदारी केवल 14 फीसद है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्र में महिलाओं का रोजगार कम है और भारत के बड़े अवसरों के लिए महिलाओं की कम भागीदारी चुनौतीपूर्ण है। निश्चित रूप से नई गठबंधन सरकार को देश की नई पीढ़ी को जॉब सीकर यानी नौकरी की चाह रखने वाले से ज्यादा नए दौर के जॉब गिवर यानी नौकरी देने वाले बनाने की तेज रणनीति के साथ भी आगे बढ़ना होगा।

पिछले 10 वर्षों में जिस तरह नई पीढ़ी के द्वारा स्वरोजगार के मौके मुट्ठी में लिए जा रहे हैं। उनकी रफ्तार बढ़ाई जानी होगी। हाल ही में शोध संस्थान स्कॉच की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में 51.40 करोड़ रोजगार मिले हैं। इस शोध अध्ययन में रोजगार व स्वरोजगार से संबंधित 12 केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएमईजीपी, पीएमए-जी, पीएलआई, पीएमएवाई-यू, और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत 10 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नई स्किल्स से नई पीढ़ी को सुसज्जित करके उनके लिए रोजगार के मौके बढ़ाए हैं।

अब तीसरे कार्यकाल में देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों की (जीसीसी) स्थापनाओं की रफ्तार तेजी से बढ़ाकर नए तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके सृजित करने की डगर पर आगे बढ़ा जाना होगा। चूंकि कई विकसित और विकासशील देशों में तेजी से बूढ़ी होती आबादी के कारण उद्योग-कारोबार व सर्विस सेक्टर के विभिन्न कामों के लिए युवा हाथों की कमी हो गई तथा श्रम लागत बढ़ने से ये देश कार्यबल संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत को इस मौके को भुनाते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा। सरकार ने 2023 तक भारतीय श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न देशों के साथ 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई गठबंधन सरकार को ऐसे समझौतों को अब और बढ़ाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा।

हम उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार के द्वारा उनके विकास के एजेंडे में शामिल अधिक रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। हम उम्मीद करें कि नई सरकार नई सरकारी नौकरियों के सृजन पर पूर्णरूपेण ध्यान देते हुए लघु-मध्यम उद्योग और असंगठित क्षेत्र में रोजगार की जरूरतों पर ध्यान देगी। साथ ही उम्मीद करें कि मोदी सरकार के श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी 142 करोड़ से अधिक आबादी के साथ दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले भारत में दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी को नए उच्च गुणवत्ता वाले कौशल से सुसज्जित करके उनके चेहरों पर रोजगार की मुस्कुराहट देने के साथ देश की आर्थिक तस्वीर संवारने की संभावनाओं को साकार करने के लिए नई कारगर रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेंगे।

तीसरे कार्यकाल में देश में वैश्विक क्षमता केंद्रों की (जीसीसी) स्थापनाओं की रफ्तार तेजी से बढ़ाकर नए तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके सृजित करने की डगर पर आगे बढ़ा जाना होगा। चूंकि कई विकसित और विकासशील देशों में तेजी से बूढ़ी होती आबादी के कारण उद्योग-कारोबार व सर्विस सेक्टर के विभिन्न कामों के लिए युवा हाथों की कमी हो गई तथा श्रम लागत बढ़ने से ये देश कार्यबल संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत को इस मौके को भुनाते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा

- अमेरिका, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान समेत 9 परमाणु संपन्न देश अपने एटमी हथियारों का आधुनिकीकरण जारी रखे हुए हैं। इनमें से कई ने 2023 में नये परमाणु सक्षम हथियार सिस्टम तैनात किए हैं
- स्वीडिश थिंक टैंक सिपरी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के परमाणु हथियार जनवरी, 2023 में 410 से बढ़कर जनवरी, 2024 में 500 हो गए वहीं भारत के पास 172 एटमी हथियार हैं
- अमेरिका-रूस के पास दुनिया के 90 प्रतिशत एटमी हथियार हैं

(मीडिया इनपुट्स)

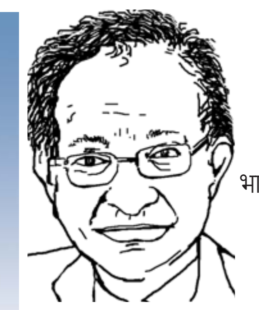

लोग मुझसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछते हैं और मैं इसके गुणा-भाग बता देता हूं। मुझे तो असली चिंता भारतीय राजनीति को लेकर है, इस बात को लेकर है कि राजनीतिक हित के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में इस सबके लिए जगह नहीं है। सच बात तो यह है कि हिन्दुत्व न केवल भारत बल्कि हिन्दूवाद को भी चोटिल कर रहा है।

कौशिक बसु, अर्थशास्त्री
@kaushikcbasu

मंत्री जी कृपया ध्यान दें

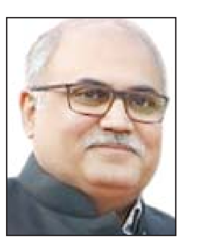

भारतीय रेल | रजनीश कपूर

शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी ना कभी रेल यात्रा न की हो। रेलवे स्टेशन पर सुनाई देने वाली घोषणा की शुरुआत 'यात्रीगण कृपया ध्यान दें' से ही होती है। इसका उद्देश्य सभी मौजूद यात्रियों का ध्यान आकर्षित करना होता है। यह तो हुई एक साधारण बात। परंतु बीते कुछ वर्षों में हो रहे रेल हादसों के बाद से अब इस घोषणा का सीधा संबंध भारतीय रेल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े मंत्रियों और अफसरों से है। बढ़ते हुए रेल हादसों के चलते अब भी अगर संबंधित मंत्री और अधिकारी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे?

देश की जीवन रेखा माने जाने वाली भारतीय रेल हर खास-ओ-आम आदमी के लिए देश के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करने का सस्ता और भरोसेमंद साधन है। हर यात्री को इस बात का भरोसा होता था कि देर-सेवर वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएगा। ज्यों-ज्यों देश की आबादी बढ़ी सरकार ने रेल यात्रा में उचित सुधार भी किए। आज भारत में रेलवे की कुल लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। भारतीय रेल रोजाना करीब 2 करोड़ 31 लाख यात्रियों और 33 लाख टन माल को ढोती है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। 12.27 लाख कर्मचारियों के साथ, भारतीय रेलवे दुनिया की आठवीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। भारतीय रेल के कार्यचालन केविभिन्न पहलुओं की देखभाल करने के लिए इसने 11 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी स्थापित किए। भारत जैसे देश के लिए इतने बड़े स्तर पर यात्रा का साधन मुहैया कराने वाली भारतीय रेल पर देश को गर्व है, परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बीते कुछ वर्षों में रेल मंत्रालय द्वारा कई ट्रेनों में जो बदलाव किए गए हैं। वह एक ओर जहां यात्रियों द्वारा बधाई प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे सिस्टम में फैली अव्यवस्था को लेकर भारी विरोध भी झेल रहे हैं। यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से रेल मंत्रालय ने अनेकों आधुनिक गाड़ियां भी चलाईं। जैसे-जैसे रेल यात्रा में सुविधा बढ़ी वैसे-वैसे किराये में भी वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि जिस कदर रेल के किरायों में वृद्धि हुई है उसमें यात्रा केवल वही लोग कर पा रहे हैं जो उस बढ़े हुए किराए का वहन कर

सकते हैं। आम जनता जो कि साधारण श्रेणी में यात्रा करती है उसके लिए कोई भी नई सुविधा नहीं दी गई है। आबादी के बढ़ने पर आम जनता के लिए आम श्रेणी की गाड़ियों में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आँकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में 2.70 करोड़ यात्री टिकट होने के बावजूद रेल में यात्रा नहीं कर पाए, क्योंकि उनका टिकट कन्फर्म नहीं हो पाया। इसी का नतीजा हुआ कि आए दिन हमें यह देखने को मिलता है कि ट्रेन में सफर करने वाले लोग ट्रेन की क्षमता से ज्यादा पाए जाते हैं। इससे आरक्षित टिकट प्राप्त कर यात्रा करने वालों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्या रेल मंत्रालय के अधिकारियों इस बात की जानकारी नहीं थी कि देश में बढ़ती हुई आबादी के चलते आवागमन में भी वृद्धि होगी? क्या जिन यात्रियों की टिकट कन्फर्म नहीं हुई और उन्हें उनके किराए की राशि वापिस की गई, इसकी संख्या में होती वृद्धि पर किसी का ध्यान नहीं गया? क्या जिन साधारण श्रेणी के डिब्बों को उच्च श्रेणी में तब्दील किया जाना उचित था? क्या उच्च श्रेणी की आधुनिक ट्रेनों को चलाने के लिए साधारण श्रेणी की ट्रेनों को रद्द करना उचित था? यदि समय रहते सही निर्णय लिया गया होता तो रेल में भीड़ के चिंताजनक दृश्य सामने नहीं आते।

एक ओर जहां किसी नई और आधुनिक रेल के उद्घाटन के समय जिस कदर मंत्री और अफसर श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं, वह रेल में हो रही लापरवाहियों का ज़िम्मा लेने से बचते नजर आते हैं। आंकड़ों के अनुसार 2014 से 31 मार्च 2023 तक 1117 रेल हादसे हो चुके हैं। इनमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों की तादाद में लोग घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ, परंतु इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया गया। यहां एक तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में 20 हजार करोड़ रुपये आने थे, जिसमें 15 हजार करोड़ केंद्र सरकार द्वारा दिये जाते और 5 हजार करोड़ रेल मंत्रालय देता, परंतु चार साल बाद मात्र 4225 करोड़ ही आए और इन्हें भी गैर जरूरी मदों पर खर्च किया गया रेलवे सुरक्षा पर नहीं। सोचने वाली बात यह है कि अधिकतर दुर्घटनाओं में मानवीय त्रुटि बताई जाती है। रेल मंत्री द्वारा संसद में दिए गए उत्तर के मुताबिक रेलवे में 3.12 लाख रिक्त पद पड़े हैं। गौरतलब है कि ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट के 70093 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 21 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। इसी के चलते मौजूदा लोकोपायलटों को लंबे समय तक ड्यूटी पर रहना पड़ता है। थकान और नींद के चलते ऐसे हादसे होना स्वाभाविक है, परंतु क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी के चलते सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए था?

आध्यात्मिक एकता | संत राजिन्दर

प्रत्येक दिन दुनिया में अलग-अलग जगहों पर कई कारणों से अनेक सभाएं और सम्मेलन होते हैं। यह सम्मेलन विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, लोक-

कल्याण, उद्योग या कई अन्य मुद्दों पर होते हैं। इन सभी सम्मेलनों में जिसमें लिए लोग इकट्ठे होते हैं, आध्यात्मिक एकता एक सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है, इसमें पूरी मानवता शामिल हो सकती है। आध्यात्मिक एकता एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए परमात्मा ने इंसान को बनाया और उसमें प्राण डालकर उसे जीवन दिया है। आध्यात्मिक एकता एक ऐसा लक्ष्य है, जिसके लिए आत्माओं (इंसान) को इस संसार में भेजा गया है। आध्यात्मिक एकता ही वह लक्ष्य है जो परमात्मा हम सबसे चाहते हैं। सभी धर्मों ने आत्मा के अस्तित्व जोकि परमात्मा का अंश है और हमें जान दे रही है, उसे स्वीकारा है। कई धर्म शास्त्रों में परमात्मा को प्रेम, चेतनता और परमानंद का महासागर बताया गया है। कहा जाता है कि शुरू में परमात्मा एक थे, फिर उन्हें एक से अनेक होने का विचार आया। इस एक विचार से परमात्मा अपने अंशों को जिन्हें हम आत्मा कहते हैं, इस संसार में भेज दिया। यदि हममें से हरेक अपने आपको आध्यात्मिक नजरिये से देखें तो हम पाएंगे कि हम आत्मिक तौर पर परमात्मा के महान, अनंत और असीम समुद्र में एक-दूसरे जुड़े हुए हैं। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, हम अपने शरीर और मन से ही पहचाने जाते हैं। हम खुद को उस नाम से जानते हैं, जो हमारे माता-पिता ने हमें दिया है। हम उस धर्म से पहचाने जाते हैं, जिसमें हमारे माता-पिता विश्वास करते हैं। हम खुद को उसी देश का समझते हैं, जहां शारीरिक रूप से हम रहते हैं। जितना अधिक हम इन बाहरी नामों से जाने जाते हैं, उतना ही अधिक हम यह भूल जाते हैं कि हम परमात्मा का अंश हैं। यदि हम प्रत्येक धर्म का गहराई से अध्ययन करेंगे और संतों-महात्माओं की शिक्षाओं को समझेंगे तो हम पाएंगे कि सभी धर्म प्रेम, शांति और एकता का ही सबक सिखाते हैं। प्रत्येक संत-महात्मा मानवता का मार्गदर्शन करते आए हैं, जिससे हम अपनी आध्यात्मिक एकता को जान सकें। यदि वास्तव में हम अपने धर्म के मानने वाले बनना चाहते हैं तो हमें उनके गूढ़ रहस्य और संतों-महात्माओं की शिक्षाओं को समझकर उस पर चलना होगा।

रीडर्स मेल

कम करनी होगी गर्मी

देश के अधिकांश हिस्सों में लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में तापमान पचास डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग शिमला, दार्जिलिंग और धर्मशाला जा रहे हैं, लेकिन अब उन क्षेत्रों में भी तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस वर्ष भीषण गर्मी और लू की चपेट में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है एवं अनेक लोग अस्वस्थ हैं। लू की वजह से श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसे देखते हुए गर्मी से राहत देने के लिए जगह-जगह पर शीतल पेय जल की व्यवस्था होनी चाहिए। भीषण गर्मी के लिए घटती हरियाली, बढ़ता शहरीकरण, घरों में बढ़ता कांच का इस्तेमाल एवं दैनिक जीवन में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन का बढ़ता उपयोग है।

हिमांशु शेखर, गया

सतर्क रहना होगा भारत को

वैश्विक रंगमंच पर भारत की साख में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले लगभग दो दशकों से देश-दुनिया के विकसित मुल्कों ने भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लोहा माना है। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालते ही मोदी का जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेना भारत के बढ़ते कद का ही परिचायक है। इस समय हमें बेहद सतर्क होकर चलना चाहिए क्योंकि विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने के साथ-साथ हमें अपने पड़ोसी मुल्कों जैसे चीन और पाकिस्तान से तल्ख होते रिश्तों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दुनिया के कुछेक देश भारत की एकता और संप्रभुता को चोट पहुंचाकर भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते है। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी तमाम तरह की चुनौतियों से बखूबी निपटना आता है। अपने शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, नेपाल व बांग्लादेश के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करके प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि भारत को शत्रु से निपटना आता है। भविष्य में भी इसी तरह की संतुलित नीतियां बनाकर विकसित भारत की दिशा में बढ़ना चाहिए।

हितेंद्र डेढा, दिल्ली

खत्म करना होगा जातिवाद

सामाजिक स्तरीकरण मुख्यतः जाति पर आधारित है। किसी जाति समूह की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, जिसके आधार पर लोगों को अन्य जाति समूहों के सापेक्ष स्थान दिया जाता है। यह दर्शाता है कि विभिन्न जातियों को उनके व्यवसायों की शुद्धता और अशुद्धता के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। यह बात सच है कि प्राचीन असमानताएं और पूर्वाग्रह धीरे-धीरे बदलते हैं। सदियों से निचली जातियों का शोषण करने वाली उच्च जातियां आज भी उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव करती हैं। अपनी जाति को दूसरी जातियों से श्रेष्ठ समझने की भावना इसका मुख्य कारण है। मानवाधिकारों की सुरक्षा, एससी-एसटी के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम जैसे कानूनों और समझौतों को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। दलित पूंजीवाद, खाप जैसे न्यायेत्तर निकायों पर लगाम लगाकर शिक्षा और भूमि और पूंजी के स्वामित्व के माध्यम से दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण करने की दिशा में कदम उठाने से ही फायदा होगा।

डॉ. सत्यवान सौरभ, भिवानी, हरियाणा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 309

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। **समूह संपादक - डॉ. विजय राय**। **स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय
संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

नीट-नेट उलझन में फंसे युवा

नीट परीक्षा देने वाले 24 लाख छात्र और उनके परिवार तो दुविधा में फंसे हुए हैं लेकिन अचानक यूजीसी की नेट परीक्षा रद्द किए जाने से परीक्षा देने वाले 9 लाख छात्र भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पेपर लीक हो जाने के मुद्दे को लेकर आक्रोशित युवा देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस समय देश के युवा नेट और नीट में ही उलझ कर रह गए। लाखों छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए पर छात्रों का भरोसा उठ चुका है। नेट परीक्षा रद्द किए जाने के एक दिन बाद शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए दोषियों को दंडित करने की बात कही है और जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति भी बनाने की घोषणा की है। यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्न पत्र डार्क नेट पर लीक हुए थे, जिसके बाद मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। जहां तक नीट परीक्षा का सवाल है शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अनियमितताओं की कुछ घटनाओं के लिए उन लाखों छात्रों को नुक्सान नहीं होना चाहिए जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर यह परीक्षा पास की है। अब पेपर लीक कांड की जांच होगी। जांच रिपोर्ट मंत्रालय को दी जाएगी। फिर किसी न किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा। इसमें कितना समय लगेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

नीट परीक्षा रद्द करने या नहीं करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही आएगा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। नीति निर्माताओं को यह सोचना होगा कि देश की प्रतिभाओं को सहेज कर रखा जाए। इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते हर साल लाखों छात्र पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं और वहीं जाकर बस जाते हैं। भारत से प्रतिभाओं का पलायन लगातार हो रहा है, जो किसी भी तरह देश के हित में नहीं है। शिक्षा मंत्रालय को इस बात का अहसास होना चाहिए कि परीक्षा रद्द होने पर छात्रों की हालत क्या होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से कोई समझने वाला नहीं है। अमीर परिवारों के बच्चे तो महंगे कोचिंग सैंटरों में पढ़ लेते हैं। उन्हें जीवन की हर सुख-सुविधाएं उपलब्ध होती हैं लेकिन उन परिवारों के बच्चों की क्या हालत होगी जो अपनी मेहनत की कमाई से सपने पूरे करने के लिए अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाते हैं। जिन परिवारों की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है उनकी हालत क्या होती है, इसे कोई समझ नहीं रहा। किसी भी छात्र के लिए परीक्षा की दोबारा तैयारी करना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। आईआईटी या नीट परीक्षा क्वालीफाई न कर पाने पर अनेक छात्र अपनी जिन्दगी को बेकार मान लेते हैं और फिर उनकी जिन्दगी में भटकाव आ जाता है। कुछ तो आत्महत्या तक करने की हद तक पहुंच जाते हैं।

> **नीट परीक्षा रद्द करने या नहीं करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही आएगा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। नीति निर्माताओं को यह सोचना होगा कि देश की प्रतिभाओं को सहेज कर रखा जाए। इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते हर साल लाखों छात्र पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं और वहीं जाकर बस जाते हैं। भारत से प्रतिभाओं का पलायन लगातार हो रहा है, जो किसी भी तरह देश के हित में नहीं है। शिक्षा मंत्रालय को इस बात का अहसास होना चाहिए कि परीक्षा रद्द होने पर छात्रों की हालत क्या होती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से कोई समझने वाला नहीं है।**

देश के विभिन्न राज्य नीट और नेट परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए एक ही संस्था को जिम्मेदारी दिए जाने का विरोध करते रहे हैं। कोचिंग सैंटरों के माफिया के खेल और अंग्रेजी के वर्चस्व को लेकर भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्य आरोप लगाते रहे हैं कि इस परीक्षा में अन्य भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है। तमिलनाडु सरकार पहले भी आरोप लगाती रही है कि मैडिकल कॉलेजों में तमिल भाषी छात्रों को कम जगह मिल रही है। इन परीक्षाओं में हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के छात्रों के साथ अन्याय होने की खबरें पहले भी आती रही हैं लेकिन इन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैडिकल परीक्षा की पुरानी प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर एनटीए की स्थापना की गई थी लेकिन यह संस्था भी माफिया का शिकार हो गई। हजारों छात्र दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज की जा चुकी हैं। पेपर लीक मामले के तार कई माफिया गिरोहों से जुड़ रहे हैं। राजनीतिक दल इस सारे मामले को सियासी बनाने पर तुले हुए हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि उठे सवालों का हल कौन तलाशेगा। इनमें अहम प्रश्नचिह्न था कई विद्यार्थियों का अस्वाभाविक रूप से पूर्णांक हासिल करना। इनमें कई हरियाणा के एक ही सेंटर से परीक्षा देने वाले थे। इसके अलावा यह भी सामने आया कि प्रश्न पत्र की दिक्कतों की वजह से कुछ बच्चों को 'ग्रेस मार्क्स' यानी कृपांक दिए गए। इससे पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे। बिहार और गोधरा में पर्चा लीक होने की खबरें भी आईं। उसके बाद केंद्र सरकार ने कृपांक रद्द कर दिए और इस माह के अंत में उन बच्चों की पुनः परीक्षा कराने को कहा है। शिक्षण में प्रवेश स्तर के रोजगार और पीएचडी में दाखिले के लिए यूजीसी-नेट की ताजा परीक्षा को शिक्षा मंत्रालय ने उस समय रद्द कर दिया जब गृह मंत्रालय की ओर से खबर आई कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है। दिलचस्प है कि पेपर लीक होने की दोनों घटनाएं उस समय हुई हैं जब बमुश्किल कुछ माह पहले संसद ने इस देशव्यापी समस्या से निपटने के लिए कानून पारित किया। एनटीए की कमियां इस समस्या का एक पहलू है। परंतु मौजूदा विवाद बड़े सवालों की ओर भी संकेत करता है जो शिक्षा व्यवस्था के ढांचे से संबद्ध है। उनमें से ताजा सवाल यह है कि क्या देशव्यापी स्तर पर फैली परीक्षाओं का केंद्रीकरण व्यावहारिक विकल्प है? फिलहाल लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है। देखना यह है कि सरकार इस मामले से कैसे निपटती है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर...

गीता पाढा

नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश का मान है,
हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर की पहचान है,
माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सराहनीय काम है,
जो उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति संस्थानों के जीर्णोद्धार पर दिया ध्यान है...!!

अलग व्यक्तित्व में उभर रहे राहुल गांधी !

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

कई सालों में पहली बार राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन भारत में मनाया और नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाकर अपने पार्टी सहयोगियों को चौंका दिया। आमतौर पर वह जन्मदिन पर विदेश में गायब हो जाते हैं, यूरोप में अपने करीबी दोस्तों के साथ ठंडी जगहों पर इसे मनाना पसंद करते हैं। लेकिन चुनावी जीत और देशभर में दो सफल भारत जोड़ो यात्राओं के बाद मिले नए आत्मविश्वास से उत्साहित राहुल गांधी एक अलग ही रूप में उभर रहे हैं।

वह इस वास्तविकता को स्वीकार कर रहे हैं कि एक राजनीतिक नेता एक सार्वजनिक व्यक्तित्व होता है, जिसके पास निजी पल बहुत कम होते हैं। इसलिए इस साल अपने जन्मदिन पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने एक केक काटा, कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने उन्हें एक टुकड़ा खिलाया। एक अजीबोगरीब पल तब आया जब राहुल गांधी को एहसास हुआ कि केक काटने से पहले वह मोमबत्ती बुझाना भूल गए थे। बहन प्रियंका गांधी को एक चम्मच केक देने के बाद उन्हें यह बात याद आई लेकिन वह जलती हुई मोमबत्ती से परेशान नहीं हुए। उन्होंने बस नीचे झुककर मोमबत्ती बुझाई और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए लोगों से जन्मदिन की शुभकामनाएं स्वीकार कीं।

अपने बदलाव के तहत राहुल गांधी भी ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक मुख्यधारा के मीडिया घरानों को साक्षात्कार नहीं दिया है लेकिन उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में अक्सर प्रेस को संबोधित करना शुरू कर दिया है और सवालों के जवाब भी आसानी से दे रहे हैं। राहुल गांधी का राजनीतिक विकास हो रहा है। और उन्हें अब पप्पू तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता।

राम मोहन नायडू ने भाजपा को बनाया अपना मुरीद

टीडीपी के नए नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही एक कागज़ पर 21 बार ओम श्रीराम लिखकर सबको चौंका दिया। जाहिर है, उन्होंने यह अपनी मां की सलाह पर किया। वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं और जब उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनने की खुशखबरी देने के लिए उन्हें फ़ोन किया, तो उन्होंने काम शुरू करने से पहले कुछ काम करने को कहा। एक था अपने नए कार्यालय में विशिष्ट अनुष्ठानों के साथ एक पारंपरिक समारोह आयोजित करना।

दूसरा था दोपहर 1:11 बजे के शुभ समय पर एक कागज पर 21 बार ओम श्रीराम लिखना। जहां उनकी मां अपने कर्त्तव्यनिष्ठ बेटे से प्रसन्न हुई होंगी, वहीं नायडू ने अपने कार्यों से भाजपा में अपने नए सहयोगियों को भी अपना मुरीद बना लिया।

क्या 'तीन लाल' परिवार से हुड्डा को रोक पाएगी भाजपा

हरियाणा की पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति के भाजपा में शामिल होने से अब भाजपा में उन तीन लालों के परिवार के सदस्य शामिल हो गए हैं, जिन्होंने तीन दशक पहले राज्य की स्थापना के बाद से हरियाणा की राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखा है। किरण चौधरी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, जिन्हें राज्य के विकास का जनक कहा जाता है। श्रुति बेशक बंसीलाल की पोती हैं।

लोकसभा चुनाव से तीन महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला भी भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा के टिकट पर हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन कांग्रेस से हार गए। उससे दो साल पहले एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते भव्य ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। वह वर्तमान में हिसार के आदमपुर से विधायक हैं। हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में भाजपा ने राज्य में कांग्रेस के हाथों पांच सीटें गंवा दी थीं। जाहिर है, उसे उम्मीद है कि हरियाणा के तीन प्रमुख लाल परिवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से उसे इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुनौती का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

भारतीय करोड़पतियों का नया ठिकाना बन रहा अमीरात

यह विडंबना है कि मोदी सरकार द्वारा भारत को हिंदुओं के लिए दूध और शहद की भूमि में बदलने के प्रयास के बावजूद, समुदाय के करोड़पति मध्य पूर्व में संयुक्त अरब अमीरात में प्रवास करना पसंद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेश प्रवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पोर्टर द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के अनुसार, 4300 भारतीय करोड़पतियों के स्थायी निवास के लिए घर छोड़ने की उम्मीद है, जिनमें से ज्यादातर संयुक्त अरब अमीरात में हैं। इस पलायन ने भारत को करोड़पतियों के प्रवास के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। पहले स्थान पर चीन और उसके बाद ब्रिटेन का स्थान है।

सांत्वना यह है कि इस वर्ष के लिए अनुमानित आंकड़ा पिछले वर्ष के वास्तविक प्रवास से कम है। 2023 में, 5100 करोड़पतियों के भारत छोड़कर विदेश जाने की खबर है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में प्रवास के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं : कर लाभ, सुरक्षा और वित्तीय विचार, सेवानिवृत्ति की संभावनाएं, व्यवसाय के अवसर और बेहतर जीवनशैली। करोड़पतियों के प्रवास से घरेलू विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है क्योंकि प्रवासी अपनी अधिकांश संपत्ति अपने नए देश में स्थानांतरित कर देते हैं।

प्रियंका की उम्मीदवारी ने असमंजस में डाला

राहिल नोरा चोपड़ा

वायनाड लोकसभा उपचुनाव में एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी ने केरल में कांग्रेस पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर दिया है। इस फैसले ने जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भाजपा को उनके खिलाफ मजबूत और प्रभावशाली उम्मीदवारों को मैदान में उतारने को लेकर असमंजस की स्थिति में डाल दिया है।

सीपीआई और बीजेपी, दोनों ने संकेत दिया है कि वे अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। हालांकि, एनी राजा, जिन्होंने पहले राहुल गांधी के खिलाफ इस सीट से चुनाव लड़ा था, ने कहा कि उनकी उम्मीदवारी पर निर्णय पार्टी के पास रहेगा। सीपीआई के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पार्टी को एक स्थानीय नेता को मैदान में उतारना चाहिए, जो क्षेत्र और लोगों से अच्छी तरह परिचित होने के कारण बेहतर समर्थन हासिल कर सके।

दूसरी ओर, बीजेपी ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वायनाड उपचुनाव के लिए कोझिकोड से सुरेंद्रन को मैदान में उतारा जाए या किसी वरिष्ठ नेता को। 2024 में बीजेपी ने अपना वोट शेयर 62,000 से ज्यादा वोटों से बढ़ाया है। राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट बरकरार रखने का निर्णय लेने के बाद इस सीट पर उपचुनाव जरूरी हो गया था, जिसे उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में वायनाड के साथ जीता था।

अब गिरिराज बोले देवेश की भाषा

जनता दल-यूनाइटेड के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खुले तौर पर यह कहने के बाद कि वह मुस्लिम या यादव समुदायों की ओर से मदद के किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया था, अब केंद्रीय मंत्री और बेगुसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने ठाकुर का समर्थन करते हुए कहा कि मुसलमानों ने उन्हें भी वोट नहीं दिया।

गिरिराज ने आरोप लगाया कि सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए उच्च स्तर पर साजिश रची गई है। गिरिराज की इस टिप्पणी को लेकर बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने उनकी जोरदार आलोचना की। अहमद ने कहा, उन लोगों के बारे में बात करने का क्या मतलब है, जो संविधान की भावना के खिलाफ हैं? वे ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जो हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है।

अजित शिंदे के लिए बड़ी चुनौती

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के इस दावे के बाद कि एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के नेता रोहित पवार ने दावा किया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राकांपा के 18 से 19 विधायक राज्य विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र के बाद उनके पक्ष में आ जाएंगे। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आठ सीटें जीती थीं, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा केवल एक सीट हासिल कर सकी थी। पार्टी वर्तमान में भाजपा के साथ गठबंधन में है और सत्तारूढ़ एनडीए का हिस्सा है।

नतीजों ने यह चर्चा भी तेज कर दी है कि कुछ नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टियों में वापसी की योजना बना रहे हैं। विधानमंडल का मानसून सत्र 27 जून को शुरू होगा और 12 जुलाई को समाप्त होगा। राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने से पहले यह आखिरी सत्र होगा। दूसरी ओर, तीन महा विकास अघाड़ी पार्टियों ने पहले ही आगामी चुनाव एक साथ लड़ने के अपने इरादे की घोषणा कर दी है।

आठ राज्यों में प्रदर्शन की समीक्षा करेगी कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के दौरान आठ राज्यों में अपने कमजोर प्रदर्शन की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग (तथ्य-खोज) पैनल बनाए हैं। 8 जून को आयोजित सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी ने चर्चा के बाद निर्णय लिया कि वह उन राज्यों में परिणामों की गहन जांच करेगी, जहां पार्टी का प्रदर्शन औसत से नीचे था।

खराब प्रदर्शन के बाद समीक्षा किए जाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस सभी 29 सीटें हार गई, छत्तीसगढ़ जहां पार्टी ने 11 सीटों में से सिर्फ एक सीट जीती, ओडिशा जहां उसने फिर से 21 सीटों में से केवल एक सीट जीती, कर्नाटक जहां उसने 28 में से 9 सीटें जीती, तेलंगाना जहां उसने 17 में से आठ सीटें जीतीं व दिल्ली, जहां पार्टी को सात सीटों में से कोई सीट नहीं मिली, के अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, जहां उसे एक भी सीट नहीं मिली।

मध्य प्रदेश के लिए समिति की अध्यक्षता महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण करेंगे। समिति में सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका और गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पैनल में कर्नाटक के पूर्व सीएम वीरप्पा मोइली और राजस्थान के विधायक हरीश चौधरी शामिल होंगे। ओडिशा के लिए इसमें सांसद अजय माकन और सांसद तारिक अनवर होंगे। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए इसमें वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और रजनी पाटिल होंगे। कर्नाटक के लिए इसमें पूर्व सांसद मधुसूदन मिस्त्री, सांसद गौरव गोगोई और वरिष्ठ नेता हिबी ईडन होंगे। तेलंगाना के लिए, इसमें पूर्व राज्यसभा उपाध्यक्ष पी जे कुरियन, वरिष्ठ नेता रकीबुल हुसैन और परगट सिंह होंगे।

सोसाइटी की लिफ्ट में सवा घंटे तक फंसी रहीं मां-बेटी

नोएडा, (पंजाब केसरी) : ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हाइनिस सोसाइटी में गुरुवार रात मां-बेटी सवा घंटे तक लिफ्ट में फंसी रहीं। आरोप है कि उन्होंने अलार्म भी दबाया, लेकिन मदद नहीं मिली। गर्मी से दोनों की हालत खराब हो गई। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने मेंटेनेंस टीम को सूचित किया, लेकिन टीम लिफ्ट का गेट नहीं खोल पाई। इसके बाद पास की सोसाइटी से टेक्नीशियन को बुलाकर लिफ्ट का गेट खोलकर दोनों को बाहर निकाला गया। पंचशील हाइनिस सोसाइटी के टावर-2 के फ्लैट नंबर 1202 में मणि कांत गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार देर रात को उनकी पत्नी सीमा गुप्ता और बेटी स्नेहा गुप्ता किसी काम से नीचे जाने के लिए 12वीं मंजिल से लिफ्ट में सवार हुई। दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचीं तो लिफ्ट का गेट नहीं खुला। दोनों करीब सवा घंटे तक लिफ्ट में फंसी रहीं। आरोप है कि दोनों ने कई बार अलार्म बजाया है, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अंदर से चिल्लाना और लिफ्ट का दरवाजा बजाना शुरू किया। इसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने आवाज सुनकर मेंटेनेंस प्रबंधन को इस बात की सूचना दी।

यूपी रेरा का ग्रेटर नोएडा में बड़ा एक्शन

- **बिल्डर का दफ्तर सील, बिल्डर पर 1.50 करोड़ रुपये का बकाया था**

नोएडा, (पंजाब केसरी) : यूपी रेरा के बकाया को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस क्रम में सदर तहसील की टीम ने एक प्रमुख बिल्डर के कार्यालय को सील कर दिया। जयदेव बिल्डर पर 1.50 करोड़ रुपये का बकाया था। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। स्थानीय निवासियों और निवेशकों ने इस कदम का स्वागत किया है, उम्मीद जताते हुए कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में अनुशासन बढ़ेगा।

यूपी रेरा ने पिछले वर्ष 3277 बिल्डरों के खिलाफ 1302 करोड़ रुपये की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी की थी। दिसंबर तक केवल 98.59 करोड़ रुपये की वसूली हो पाई थी। चुनाव आचार संहिता के कारण कार्रवाई रुकी थी, अब फिर से शुरू हो गई है। पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में दादरी तहसील में सबसे अधिक बकायेदार बिल्डर है। यह कार्रवाई उन व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिन्हें जिला प्रशासन यूपी रेरा के बकाया की वसूली के लिए कर रहा है। सदर तहसील की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयदेव बिल्डर के कार्यालय को सील कर दिया। यह कार्रवाई यूपी रेरा के 1.50 करोड़ रुपये के बकाया को न चुकाने के कारण की गई। प्रशासन ने बताया कि बिल्डर को कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। पिछले वर्ष यूपी रेरा ने 3277 बिल्डरों के खिलाफ कुल 1302 करोड़ रुपये की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी की थी। हालांकि, दिसंबर तक प्रशासन केवल 173 आरसी से 98.59 करोड़ रुपये ही वसूल कर पाया था।

9 इंस्पेक्टर समेत 13 के तबादले

कई थानों के प्रभारी बदले

नोएडा, (पंजाब केसरी) : गौतमबुद्ध नगर पुलिस में एक बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जिले में लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार तबादला एक्सप्रेस चलाई है। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नए दायित्व सौंपे गए हैं। यह कदम पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षक अमित कुमार भडाना को साइबर हेल्प डेस्क थाना फेस-2 से थाना फेस-1 का प्रभार दिया गया है। निरीक्षक ध्रुवभूषण दुबे को थाना फेस-1 से थाना सेक्टर 24 का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निरीक्षक भूपेन्द्र सिंह को रबूपुरा स्थित साइबर हेल्प डेस्क से थाना सेक्टर 126 का प्रभार सौंपा गया है। निरीक्षक विजय कुमार गौतम को पुलिस लाइन से थाना साइबर का नया प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक मनोज कुमार सिंह को पुलिस लाइन से थाना सूरजपुर का प्रभार दिया गया है। निरीक्षक पुष्पराज सिंह को थाना सूरजपुर से थाना सेक्टर 142 का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है।

कोयला खदान नीलामी का 10वां दौर शुरू

हैदराबाद, (पंजाब केसरी): केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को यहां वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 10वें दौर की शुरुआत की। नीलामी के 10वें दौर में 67 कोयला खानों को शामिल किया गया है। कोयला मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस कदम से घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ेगा और देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कोयला आयात घटाने और इसका उत्पादन बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पिछले नौ दौर की नीलामी में 107 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।

कांग्रेस विधायक की पत्नी घर में फंदे से लटकी मिली

जांच शुरू

हैदराबाद, (पंजाब केसरी): तेलंगाना में कांग्रेस विधायक एम सत्यम की पत्नी अपने आवास पर मृत मिली। पुलिस के अनुसार, माना जा रहा है कि यह आत्महत्या का मामला है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार रात परिवार के कुछ सदस्यों को रूपा देवी अपने घर पर फंदे से लटकी हुईं मिली। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने (रूपा ने) स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण यह कदम उठाया है। एम सत्यम, तेलंगाना के करीमनगर जिले के चोप्पादंडी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तेलंगाना सरकार में मंत्री पोन्नम प्रभाकर समेत अन्य लोगों ने विधायक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

चार राज्यों की मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य शुरू

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाता सूची अद्यतन करने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने इन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए पात्रता की तिथि एक जुलाई, 2024 तय की गई है। हाल में हुए लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को एक जनवरी से अद्यतन किया गया है। तीनों राज्यों में मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 नवंबर, 26 नवंबर और 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होने जा रहा है। आयोग ने कहा कि इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद नए सदन के गठन के लिए जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कराए जाने हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा, ''हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की भारी भागीदारी को देखते हुए, आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों को एक जुलाई, 2024 की पात्रता तिथि के तहत अद्यतन करने का भी निर्देश दिया है।''

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

फिर भटकता कनाडा

कनाडा में बढ़ते भारत विरोधी अलगाववाद की जितनी निंदा की जाए, कम होगी। भारत सरकार ने उचित ही कनाडा सरकार से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। फिर एक बार खून-खराबे को लालायित चंद खालिस्तानी चरमपंथियों ने तथाकथित नागरिक अदालत आयोजित की है और वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया है, तो कतई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता। भारत ने कनाडाई उच्चायोग को बाकायदे एक राजनयिक नोट जारी करते हुए अलगाववादी तत्वों की ताजा हरकतों पर अपनी गंभीर आपत्ति जताई है। कनाडा में भारत विरोध को जिस तरह से भड़काने की लगातार साजिशें हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं उस देश की मुख्यधारा की राजनीति का हल्कापन जिम्मेदार है, तभी तो घोषित आतंकी निज्जर को वहां की संसद में मौन श्रद्धांजलि दी गई है। यह वही निज्जर है, जिस पर भारत में हत्या का आरोप था, जो मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल था। उसकी मौत पर कनाडा में आंसू बहाने वालों की जमात निरंतर उग्र होती जा रही है, तो भारत सरकार को कुछ ज्यादा ही सचेत रहना चाहिए।

अब यह बात कतई छिपी नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार अलगाववादियों को खूनी खिलवाड़ का मौका दे रही है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अलगाववाद के प्रति नरमी खुद कनाडा के समाज पर भारी पड़ेगी। अलगाववाद का समर्थक पाकिस्तान आज किस मुकाम पर है, यह हर कोई देख रहा है। बेशक, दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दा कनाडा सरकार द्वारा अपनी धरती पर सक्रिय हिंसक तत्वों को छूट देने का है। दरअसल, कनाडा अपने ही इतिहास को भूल गया है। साल 1985 में 25 जून को मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को कनाडाई सिख आतंकियों ने बम विस्फोट से उड़ा दिया था। जमीन से 31,000 फीट ऊपर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 268 कनाडाई, 27 ब्रिटिश व 24 भारतीय मारे गए थे। यह बमबारी आज भी विमानन आतंकवाद के सबसे दर्दनाक दुष्कृत्यों में से एक है। फिर 23 जून दहलीज पर है, पीड़ित परिजन अपनों की शहादत को हर साल की तरह इस बार भी याद करना चाहते हैं, लेकिन अलगाववादियों को यह चुभ रहा है। विडंबना देखिए, निज्जर को तो संसद में श्रद्धांजलि दी गई, मगर आतंकी हमले के शिकार बेगुनाहों को बाहर कहीं श्रद्धांजलि देने पर आपत्ति हो रही है? ऐसे में, भारत सरकार ने आधिकारिक निंदा का सहारा लेकर दोटूक संदेश दिया है, जो कनाडा के कर्णधारों तक जरूर पहुंचना चाहिए।

भारत सरकार ने अलगाववाद की आधिकारिक निंदा का सहारा लेकर दोटूक संदेश दिया है, जो कनाडा के कर्णधारों तक जरूर पहुंचना चाहिए।

यह भी गौर करने की बात है कि कनाडा में ही अच्छी नसीहत देने वाले कम नहीं हैं। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने साफ शब्दों में कहा है कि आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार विचारधारा अब भी उनके देश में कुछ लोगों के बीच जीवित है। कनाडाई संसद में बोलते हुए आर्य ने उचित ही कहा कि खालिस्तान समर्थकों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाना यह दर्शाता है कि स्याह ताकतें फिर सक्रिय हो गई हैं। वहां हिंदुओं और उनके आयोजनों को निशाना बनाया जाने लगा है। कनाडा 1980 के दशक में ऐसी ही आग से गुजर चुका है, वहां की सरकार ने जब आतंकवाद का दर्द झेलने के बाद कड़ी कार्रवाई की थी, तब अलगाववादी आग काबू में आई थी, आज फिर वैसी ही जरूरत आन पड़ी है।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 22 जून, 1949

पेरिस-वार्ता का हासिल

करीब एक महीने से पेरिस में संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा सोवियत रूस के विदेश मंत्रियों के बीच जो वार्ता चल रही थी, वह समाप्त हो गई। इस बीच कई खुली और कई गुप्त बैठकें हुईं और उनके संबंध में जो समाचार तथा अनुमान पत्रों में प्रकाशित होते थे, उनसे यही आभास होता था कि चार बड़े परराष्ट्र-मंत्रियों के कई दिनों का परिश्रम 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' के रूप में परिणत होगा। यदि यह सम्मेलन पूर्ण विफल हो गया होता तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर बड़ी गंभीर और निराशाजनक प्रतिक्रिया होती। हर्ष है कि विश्व-शांति इस संभावित आघात से बच गई। पेरिस-सम्मेलन जहां असफलता की गहरी खाई में डूबने से बच गया, वहां वह सफलता के शैल-शृंग पर भी नहीं पहुंच सका। वास्तविकता यह है कि परिस्थितियों ने 'चार बड़ों' को किसी हद तक विवेक, संयम तथा सद्भावना को ग्रहण करने के लिए बाध्य किया है और उसी का परिणाम यह कामचलाऊ समझौता निकला है। सम्मेलन द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में ''रहो और रहने दो'' शब्द सार्थक हैं। जब समग्र जर्मनी की राजनीतिक तथा आर्थिक एकता की पुनर्स्थापना के बारे में समझौते का कोई मार्ग न निकल सका तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं रह गया कि चारों राष्ट्र अपने अधिकृत क्षेत्रों में पूर्ववत अपनी व्यवस्था कायम रखें किन्तु इस प्रकार रहते हुए वे दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। यदि इसको सचाई तथा सद्भावना के साथ कार्यान्वित किया जाये तो भावी स्थायी समझौते के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है। चारों राष्ट्रों ने निर्णय किया है कि न्यूयार्क में बर्लिन के घेरे को हटाने के बारे में जो फैसला हुआ था, वह कायम रहेगा; साथ ही बर्लिन के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के मध्य जनता का आवागमन तथा माल का यातायात जारी रहेगा।

बर्लिन के अतिरिक्त आस्ट्रिया के प्रश्न पर जो समझौता हुआ है वह भी आशाजनक है। यद्यपि आस्ट्रिया की संधि का मसविदा अभी तैयार नहीं हुआ किन्तु वर्तमान गतिविधि को देखते हुए यही उम्मीद करनी चाहिये कि आगामी १ सितम्बर तक चारों राष्ट्रों के उप-विदेश मंत्री सर्वसम्मत मसविदा प्रस्तुत कर सकेंगे।

कहीं लोग बादल के लिए तरस रहे हैं, तो कहीं पानी के लिए धरने की नौबत आ रही है, तो कहीं बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। ऐसी ही स्थिति साल 1986 में भी बनी थी और लोकसभा में बहस हुई थी, तब जो सवाल उठे थे, वे आज भी बरकरार हैं।

आमने-सामने

आपदा के समय राज्यों को पूरी सहायता मिले

यहां स्कैन करें

मधु दंडवते | तत्कालीन सांसद व वरिष्ठ नेता

- बाढ़ और सूखा अब रोजमर्रा की समस्या बन गए हैं।
- आपदाओं से निपटने के लिए पूरा धन जुटाने में राज्य सरकारें नाकाम हैं।
- अधिकारी वास्तविक स्थिति का पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, अब तक वाद-विवाद में बाढ़ पर बहुत ध्यान दिया गया है। निःसंदेह यह एक अच्छी बात है, परंतु बाढ़ पर चर्चा करते समय सूखे को भुला दिया गया है और इसलिए मैं देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति की ओर कुछ अधिक ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मैं पश्चिम तटीय कोंकण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां पिछले 100 वर्षों से अकाल या सूखा नहीं पड़ा। बाढ़ आई थी, पर इस बार हमने देखा कि असामान्य रूप से सूखे तथा अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी...।

देश में सूखा तथा बाढ़ लगभग एक चिरकालिक समस्या बन गई है और इसलिए इनकी रोकथाम तथा बचाव के तरीकों पर हमें कुछ और चर्चा करने की जरूरत है, जिससे हम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपना सकें। ...यद्यपि बाढ़ एवं सूखा मुख्य रूप से राज्यों का विषय है, क्योंकि ये रोजमर्रा की समस्या बन गए हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे समरूप मार्गनिर्देश तैयार करें तथा राज्यों को भेजें, ताकि इनके प्रति एक समान दृष्टिकोण अपनाया जा सके तथा उस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर साधन एकत्र कर सके।

जहां तक वित्तीय साधनों का संबंध है, यदि आप विभिन्न राज्य सरकारों के पास सूखे तथा बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए उपलब्ध धनराशि को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि राज्यों के लिए संसाधन जुटाना उनकी क्षमता से बाहर है। इसलिए केंद्रीय सहायता सुलभ होनी चाहिए...। वर्तमान स्थिति क्या है? मानदंड तथा पुराने प्रतिमान केवल कल्पना शक्ति पर ही आधारित हैं; अधिकारियों को यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या किसी क्षेत्र विशेष में सूखे की स्थिति है? अधिकारियों को पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है और वे कल्पना शक्ति के सहारे ही यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है और फिर वे कहते हैं कि इस बार फसल रुपये में 50 पैसे या 60 पैसे या 40 पैसे है। इसका गलत प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत में कई क्षेत्रों में इस पुराने मानदंड कि एक क्षेत्र विशेष में सूखे की स्थिति क्या है, के बजाय यह बेहतर होगा कि आप उस क्षेत्र विशेष में हुई औसत वर्षा को लें और यदि वर्षा काफी कम हुई हो, तो गांव के अधिकारी द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट की चिंता किए बिना हमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों के बारे में मैं जानता हूं, हमारे वित्त मंत्री महोदय कृषि मंत्री महोदय को बताएंगे कि बैंक वालों के कारण परेशानियां पैदा होंगी। ...मैं सोचता हूं कि वित्त मंत्री महोदय तथा कृषि मंत्री महोदय के बीच एक वार्ता होनी चाहिए तथा पुराने मानदंडों को बिल्कुल बदल दिया जाना चाहिए। ...

कुछ बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। उनमें से एक कुएं की खुदाई करना है। इस बारे में एक बड़ा दिलचस्प अनुभव है तथा यह अनुभव राजस्थान में हुआ है। ...सामान्यतया पानी 150 या 200 फुट नीचे होता है। आप पाएंगे कि सूखे की स्थिति में अगर आप 700 फुट तक भी खुदाई करेंगे, तो ट्यूबवेल में कोई पानी नहीं आएगा और सारी राशि तथा समस्त व्यय व्यर्थ चला जाएगा।...

सभी राज्यों को पर्याप्त केंद्रीय सहायता दी जानी चाहिए। यहां मेरा एक ठोस सुझाव है कि सूखे की स्थिति में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, उड़ीसा, बिहार अथवा महाराष्ट्र के क्षेत्र। ...जब कभी संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता दी जाती है, तो यह पता चलता है कि सामान्यतया न केवल पिछड़े इलाकों की अवहेलना की जाती है, अपितु सूखे की स्थिति में तो उन्हें सहायता से पूरी तरह वंचित रखा जाता है। ...एक निश्चित राशि इन उपेक्षित पिछड़े क्षेत्रों के लिए निर्धारित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इन पिछड़े इलाकों की सूखे के दौरान भी उपेक्षा न हो।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

पैसों का पूरा इस्तेमाल तो करें राज्य सरकारें

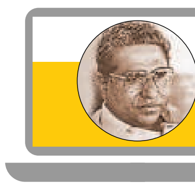

यहां स्कैन करें

योगेंद्र मकवाना | तत्कालीन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री

- हमने प्राकृतिक आपदाओं में पूरी राहत देने के पर्याप्त प्रावधान किए।
- आंध्र प्रदेश को हमने धन दिया, पर खर्च केवल 36 प्रतिशत हुआ।
- बहुत मेहनत करते हैं अधिकारी, उनके साथ न्याय होना चाहिए।

चर्चा में जिन 41 सदस्यों ने हिस्सा लिया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। कई सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। ...1950 तक अभाव से राहत या प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, दूसरे वित्त आयोग द्वारा इस मुद्दे पर काफी अच्छी तरह से चर्चा हुई और राज्य सरकारों द्वारा और लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा कई सुझाव दिए गए थे कि आपदाओं से निपटने के लिए कुछ निधियां होनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं बिना सूचना के आती हैं और उनके लिए धन नहीं मिलता है। इसलिए कुछ प्रावधान होने चाहिए।...

दूसरे वित्त आयोग के दौरान सीमांत धन के नाम से इस प्रावधान को शुरू किया गया था...। अब इस राशि को दोगुने से अधिक कर दिया है।... छठे वित्त आयोग तक अग्रिम सहायता योजना देने की व्यवस्था थी, अनुदानों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, जो अब सातवें वित्त आयोग ने बाढ़ों, तूफानों, ओलावृष्टि और भूकंप के लिए इसे शुरू किया है। अनुदानों का प्रावधान सातवें वित्त आयोग ने शुरू किया था। तब तक यह केवल अग्रिम सहायता योजना थी और इन विपत्तियों से निपटने के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी थीं और वे इनके लिए व्यय अपनी निधियों से पूरा करती थीं। ...राज्य सरकारें लोगों को राहत देने के लिए जो कार्य शुरू करती हैं, उन सभी के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता करना मुश्किल है। ....गत वर्ष सारे देश में अभूतपूर्व बाढ़ आई थी तथा फिर सूखा पड़ा था। चौदह राज्यों तथा दो केंद्रशासित प्रदेशों में सूखे से नुकसान हुआ था और सभी 22 राज्यों एवं चार केंद्रशासित प्रदेशों में बाढ़, ओलावृष्टि, तूफानों आदि तथा यहां तक कि आग से भी नुकसान हुआ था। आग पर पहले राज्यों को राहत नहीं दी जाती थी, पर हाल ही में आठवें वित्त आयोग ने इसे शामिल किया है।...

राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाले धनराशि की मांग बढ़ रही है। यह हमारा अनुभव है और हमें प्राप्त हुए ज्ञापनों से तथा राज्यों में जो नुकसान हुआ है, उससे पता चलता है कि कुछ मांगें बढ़ाकर भी बताई गई हैं...।

मिसाल के लिए, वर्ष 1985-86 में आंध्र प्रदेश की एआरडब्ल्यूएसएस, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 1,587.45 लाख रुपये की राशि दी गई थी, पर इस्तेमाल कितनी राशि का किया गया है? केवल 582 लाख रुपये, अर्थात 36 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल किया गया था। अब किसको दोष दें? क्या भारत सरकार दोषी है? अथवा क्या यह राज्य सरकार है, जिसने दी गई राशि का इस्तेमाल नहीं किया है?...

मैंने प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर से हेलिकाप्टर में उड़ान भरी है, पर ये अधिकारीगण, जो वहां जाते हैं, वास्तव में कार्य कर रहे हैं। वे प्रातः जाकर देर शाम तक लौटते हैं और कभी-कभी उन्हें अपना दोपहर का भोजन भी छोड़ना पड़ता है। हमें उनके प्रति भी न्याय करना चाहिए। ...

बाढ़, चक्रवात और सूखा इत्यादि के लिए दी जाने वाली राहत के समय अपनाए जाने वाले मानदंडों को बदलने के लिए सिर्फ प्रोफेसर मधु दंडवते ने ही नहीं कहा है, बल्कि लगभग प्रत्येक सदस्य ने कहा है। वे चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु अनुदान के रूप में दी जाए, किंतु यह संभव नहीं है। ये मानदंड वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तब राज्य सरकारों को वित्त आयोग से मिलने, उसको अपना ज्ञापन देने और अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है।...

हमारा देश एक देश नहीं, उप-महाद्वीप है और उप-महाद्वीप में अनेक प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्रों में वर्षा अधिक है और कुछ क्षेत्रों में सूखा है, इसलिए यह एक स्थायी समस्या है और यह सिर्फ दीर्घकालिक उपायों से सुलझाई जा सकती है, जो सरकार ने किए हैं, और जिनका मैंने उल्लेख किया है, पर धन का अभाव होने के कारण समय पर प्रत्येक काम करना संभव नहीं है।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन से)

आधी रात तक जागते बच्चे और उनका ब्लड प्रेशर

यहां स्कैन करें

क्षमा शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार

कल एक खबर पढ़ते हुए कई साल पहले की घटना दिमाग में कौंध गई। बुखार के कारण मैं एक डॉक्टर के पास पहुंची थी। सामने एक छह-सात साल की बच्ची बैठी थी। उसकी नकसीर बह रही थी। मां बार-बार रूमाल से पोंछ रही थी। बच्ची डॉक्टर के सामने गई, तो कुछ देर वह सोचते रहे। फिर मां से पूछा, तो पता चला कि कल से रह-रहकर ऐसा हो रहा है। डॉक्टर ने बच्ची का 'ब्लड प्रेशर' मापा। ऊपर का बीपी ढाई सौ से ऊपर और नीचे का एक सौ दस था। डॉक्टर हतप्रभ थे। देखने वालों के लिए भी यह आश्चर्य की बात थी कि इतनी छोटी बच्ची को ब्लड प्रेशर, जबकि इसे तो उम्रदराज लोगों का रोग माना जाता है। न जाने उस बच्ची का क्या हुआ होगा! मगर जिस खबर का ऊपर जिक्र किया, वह भी बच्चों में बढ़ते ब्लड प्रेशर से संबंधित थी।

कई अध्ययनों और शोध के मुताबिक, भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों में से सात प्रतिशत बच्चे 'हाई ब्लड प्रेशर' यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। दुनिया भर में बच्चों और किशोरों में बीपी बढ़ रहा है। बच्चों में मोटापा भी इसका एक बड़ा कारण है। अब तक माना जाता था कि योग, कसरत और खान-पान का ध्यान रखकर इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। मगर बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित पत्रिका में छपे एक लेख में बताया गया है कि उनमें उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए जरूरी है कि वे पूरी नींद लें। जिन बच्चों को बीपी की समस्या है, उनकी काउंसलिंग के वक्त उन्हें सही समय पर सोने की हिदायतें दी जानी चाहिए। डॉक्टर उनके अभिभावकों को भी जागरूक करें। उच्च रक्तचाप से ग्रसित 539 बच्चों और किशोरों पर किए गए अध्ययन के निष्कर्ष इस पत्रिका में छापे गए हैं। डॉक्टरों ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि जो बच्चे ज्यादा देर तक गहरी नींद लेते हैं, उनका रक्तचाप संतुलित रहता है। इसलिए ज्यादा नींद और जल्दी सोना जरूरी है।

मगर दिक्कत यह है कि आजकल बच्चे भी आधी रात तक जागते रहते हैं। उनका बहुत सारा समय मोबाइल पर बीतता है। ऐसी कई रिपोर्ट आ ही चुकी हैं कि काफी बच्चों को मोबाइल की ऐसी लत लग चुकी है कि वे न बाहर खेलते-कूदते हैं और न ही किसी शारीरिक काम में दिलचस्पी लेते हैं। यहां तक कि वे दोस्तों से भी नहीं मिलते। स्क्रीन देखते हुए वे कुछ न कुछ खाते रहते हैं। खाने-पीने की इन चीजों में भी जंक फूड अधिक होता है, जिससे उनका मोटापा भी बढ़ता है। इससे न केवल बल्ड प्रेशर, बल्कि डायबिटीज और जोड़ों की समस्याएं भी बढ़ती हैं।

ताजा शोध के मुताबिक, भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों में से लगभग सात प्रतिशत बच्चे 'हाई ब्लड प्रेशर' से पीड़ित हैं। दुनिया भर में बच्चों और किशोरों में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है।

दुनिया भर में बच्चों में मोटापा एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। इस पर नियंत्रण के लिए अक्सर बताया जाता है कि बच्चों को स्क्रीन से ज्यादा से ज्यादा दूर रखें। उन्हें मोबाइल थोड़े समय के लिए दें, मगर ऐसा हो नहीं पाता। बहुत से माता-पिता कहते हैं कि अगर हम बच्चों को मोबाइल देना बंद करते हैं, तो वे अपने दोस्तों के मुकाबले खुद को हीन समझते हैं। दोस्त उनका मजाक भी उड़ाते हैं। बच्चों के बीच एक से एक नए ब्रांड का मोबाइल उनकी हैसियत का प्रतीक बन गया है। दूसरी तरफ, डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब है, देर से सोना। इसके अलावा बहुत से मामलों में नींद ही न आना। विशेषज्ञों के अनुसार, अच्छी नींद का हमारे हृदय के स्वास्थ्य से भी संबंध है। दिमागी स्वास्थ्य के लिए भी गहरी और लंबी नींद जरूरी है। छह से बारह साल के बच्चों को कम से कम बारह घंटे सोना चाहिए। यही नहीं, सोने से कम से कम आधा घंटे पहले टीवी, मोबाइल कुछ नहीं देखना चाहिए। ये तो ऐसी हिदायतें हैं, जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए जरूरी हैं। मगर बच्चों की सेहत के लिए ये अनिवार्य हैं।

छोटी उम्र में उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्या का मतलब है, पूरी जिंदगी उसे भुगतना। भारत में यदि सात प्रतिशत बच्चे इसके शिकार हैं, तो सोचिए कि उनकी संख्या कितनी बड़ी है और ये प्रतिशत भी सिर्फ उन बच्चों का है, जो स्कूल जाते हैं। बहुत से बच्चे, जो स्कूल नहीं जाते, उनकी समस्या का निपटारा कैसे हो? हर जगह सही जांच के तौर-तरीके भी उपलब्ध नहीं हैं। फिर यह भी सोचा जाता है कि बच्चों को कोई गंभीर बीमारी होती ही नहीं। ऐसे में, इस चिंताजनक स्थिति पर अभिभावकों का ध्यान देना भी जरूरी है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आइल गवनवा की बारी

कबीर इतने लोकप्रिय क्यों हैं? दरअसल, उनकी परंपरा कहने-सुनने की परंपरा रही है, मौखिक परंपरा रही है। वह पूर्णतः लोक के लिए कह रहे थे, लोक से लेकर कह रहे थे और लोक में रहते हुए कह रहे थे। यह अकस्मात नहीं है कि कबीर की बानियों में लोक के अनगिनत शब्द उनके अर्थ और अनुभव समाए हुए हैं, बल्कि लोक के अनुभव और लोक की प्रसिद्धियों को माने बिना साहित्य और दर्शनशास्त्र का परमार्थ नहीं सधता। कुम्हार और जुलाहे के हस्त कौशल व लौकिक अनुभवों के कई उदाहरण दर्शन शास्त्र के ग्रंथों में मिल जाते हैं। कबीर ने दर्शन के शास्त्रीय संदर्भों को लोक जीवन और लोक भाषा से जोड़ा।

लोक का संबंध मनुष्य की सनातन संवेदना और आस्थाओं से जुड़ा है। लोक को साधारण सी भी ठेस पूरे समाज को झनझनाहट और उद्वेलन से भर देती है। इस लोक-शक्ति के आधार पर ही भारतीय संस्कृति पूरे विश्व या ब्रह्मांड को एक मानवीय रिश्ते में गूंथ देती है। इस अद्भुत लोक को लेकर चलते हैं कबीर। उनका धर्म और कर्म साथ-साथ चलता है। करघे पर ताना-बाना बुनते हुए ज्ञान की ऐसी चादर बुनते हैं, जो काल के किसी भी स्पर्श से मैली नहीं होती। मृत्यु की ओर से जीवन को देखने वाले कबीर विवाह के रूपक में भी मौत का मुखौटा लगाते हैं और 'आइल गवनवा की बारी' के बहाने जीवन की संध्या बेला, उसकी क्षणभंगुरता की ओर इंगित करते हैं।

कबीर की भाषा को समझने के लिए गांव-गली, खेत-खलिहान, नट-बाजीगर, मल्लाहों, जुलाहों, कामगरों की घरेलू व जातीय-प्रजातीय भाषा की संपदा का संग्रह अपेक्षित है। इसके बिना कबीर के शब्द अपरिभाषित और अविश्लेषित रह जाएंगे।

नीरजा माधव

शेखर कपूर | अभिनेता

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उचित कहा है कि उपभोक्ता उत्पादों का प्रचार करने वाली हस्तियों का यह फर्ज बनता है कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए भ्रामक या हानिकारक न हों!

अनुलोम-विलोम

मांसाहार बनाम शाकाहार

अपने जायके के लिए जीव-हत्या अनुचित

इन दिनों शाकाहार बनाम मांसाहार की बहस फिर से तेज हो गई है। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि प्रकृति ने हर किसी के लिए आहार शृंखला तय कर रखी है, जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है। चूंकि यह प्रकृति द्वारा तय नियम है, इसलिए हमें मांसाहार को लेकर दुराग्रह नहीं पालना चाहिए। मगर ऐसा कहते हुए वे भूल जाते हैं कि धरती के तमाम जीवों में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है, जिसमें सोचने-समझने और हालात के अनुकूल खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता है। जब मनुष्य अन्य तमाम जीवों से श्रेष्ठ है, तो उसे क्यों ऐसी आहार शृंखला अपनानी चाहिए, जिसकी बुनियाद किसी दूसरे जीव की जान हो। हमें अपने जीवन में न्यूनतम हिंसा का पालन करना चाहिए। कुछ मांसाहारी तो ईश्वर के नाम पर मांसाहार को उचित ठहराते हैं। मगर भक्ति के नाम पर किसी की प्राण-शक्ति को नष्ट कर देना पापपूर्ण ही है, क्योंकि ईश्वर को उन्हीं द्वारा रचित जीव का जीवन अर्पित करके भला कैसे खुश किया जा सकता है? जीवन देना निश्चित तौर पर ईश्वर का काम है, लेकिन किसी के प्राण बचाना तो हमारे हाथ में है। अगर जीव का अंत तय है, तो उसकी मौत होगी ही, लेकिन उसे हम अपने हाथों से क्यों मारें? जब तक संभव है, उसकी रक्षा क्यों न करें? किसी एक प्राणी के जीवन की भी हम रक्षा कर सके, तो हमें करनी ही चाहिए। इसीलिए, जितनी जल्दी हो, हमें शाकाहार अपना लेना चाहिए। मांसाहार को छोड़ देना मानव समाज के लिए बेहतर होगा।

सौरभ, टिप्पणीकार

शाकाहार चुनिए

ओशो ने मांसाहार और शाकाहार पर बहुत सटीक बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि फल और सब्जियां रंगदार और खुशबूदार होती हैं, वे आपको मोहक लगती हैं, जबकि मांस देखने में भद्दा और बदबूदार होता है। किसी फल के बगीचे में चले जाएं, तो मन खिल जाता है। एक-दो फल तोड़कर खाने का मन करता है, वहीं किसी बूचरखाने में चले जाएं, तो अच्छा-खासा स्वस्थ मन भी खराब हो जाए। फल या सब्जी तोड़ने या काटने पर आपको कोई ग्लानि नहीं होती, उनकी पीड़ा, उनका रोना-चीखना आपको सुनाई या दिखाई नहीं देता, वहीं किसी पशु की हत्या करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए देखा जाए, तो प्रकृति ने आपकी इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि जिह्वा के अलावा बाकी सभी इंद्रियां मांसाहार के खिलाफ हैं। इससे आपको समझना चाहिए कि प्रकृति आपको क्या इशारा कर रही है? इस इशारे को समझकर ही अपना भोजन चुनें।

कमलेश कुमार, टिप्पणीकार

मांसाहार की निंदा का कोई तुक नहीं

मांसाहारी, शाकाहारी, वीगन इत्यादि की तरह भविष्य में शायद कोई और प्रजाति भी आएगी और उसका नामकरण भी इन्हीं की तरह हो जाएगा। इंसान फिर अपने आपको एक नए समूह का सदस्य घोषित कर देगा। साथ ही खुद के श्रेष्ठ होने का तमगा भी खुद लगा लेगा, क्योंकि उसके हिसाब से नया तमगा पुराने तमगों से बेहतर है, जबकि कुदरत का सिस्टम तमगों पर नहीं, बल्कि संतुलन पर चलता है। इसके लिए उसका अपना जैविक सिस्टम है, जिसमें दखल देकर इंसान अपना सिस्टम बनाने की कोशिश में लगा रहता है। यह इंसान की प्रकृति है। इसके लिए वह नाना प्रकार के तर्क-कुतर्क देकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता रहता है। मगर ऐसा करते हुए वह भूल जाता है कि कुदरत उससे पहले भी थी और बाद में भी होगी। उसे समझना चाहिए कि जिसका स्वभाव मांसाहार से जुड़ा है, वह मांसाहारी ही होगा, जिसका शाकाहार से, वह शाकाहारी होगा और जिसका वीगन से जुड़ा है, वह वीगन रहेगा। इसमें अच्छा या बुरा होने जैसा कुछ नहीं। सभी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने खान-पान का चयन करते हैं। इंसान के अलावा कोई भी अन्य जीव मांसाहारी, शाकाहारी या वीगन होने का अभिमान नहीं पालता और न ही किसी दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। कुदरत ने किसी भी जीव को अपने पर निर्भर नहीं रखा, बल्कि वह शृंखलाओं द्वारा दूसरे प्राणियों पर निर्भर है। खान-पान प्रकृति का नियोजन है। यहां एक जीव ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे का भोजन है। जैविक चक्र इसके बिना पूरा नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने स्वभाव में रहो। मांसाहारी हो, तो मांस खाने में कोई बुराई नहीं और शाकाहारी हो, तो शाकाहार खाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीगन हो, तो फूल-पत्तियों से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने शरीर के स्वभाव, उसकी जरूरत और अपने उपार्जित संस्कारों के अनुरूप खान-पान का चयन करें। किसी खास तमगे में पड़कर अपने स्वभाव को विकृत न करें।

वहाब, टिप्पणीकार

मिथ्याभिमान

यह बात गलत है कि देश में शाकाहारियों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक, हर दो में से एक भारतीय न सिर्फ मांसाहार पसंद करता है, बल्कि हफ्ते में एक बार जरूर खाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 57.3 फीसदी पुरुष और 45.1 प्रतिशत महिलाएं सप्ताह में कम से कम एक बार मांसाहार का सेवन करते हैं। इसलिए शाकाहारी मिथ्याभिमान में जीना बंद करें और मांसाहारी को न कोसें।

समीर, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण

समस्या कभी पैसे की नहीं होती, हमेशा विचार की होती है

जम्मू-कश्मीर में चुनाव

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहकर जम्मू-कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जगाने का काम किया कि यहां के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल किया जाएगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी उल्लेख किया। इन तैयारियों का संकेत चुनाव आयोग की ओर मतदाता सूचियां ठीक करने की घोषणा से भी मिला था और भाजपा की ओर से चुनाव प्रभारी नियुक्त करने से भी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में इस वर्ष सितंबर के पहले तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है, इसलिए यहां हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही चुनाव होने के आसार बढ़ गए हैं। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को इसलिए भी बल मिला है, क्योंकि हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में जम्मू के साथ-साथ कश्मीर के लोगों ने भी बढ़-चढ़कर मतदान में भाग लिया। इससे यही स्पष्ट हुआ कि घाटी के लोग मुख्यधारा में शामिल होने को तैयार हैं और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की महत्ता भी समझ चुके हैं। यह स्थिति बनी तो इसीलिए, क्योंकि एक ओर जहां कश्मीर में आतंक का असर कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया निष्पक्षता से आयोजित की गई। इसका श्रेय चुनाव आयोग को भी जाता है और केंद्रीय सत्ता के साथ सुरक्षा बलों को भी।

निःसंदेह प्रधानमंत्री के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली चुनाव के पहले होगी या बाद में। चूंकि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की प्रतिबद्धता कई बार व्यक्त कर चुकी है, इसलिए एक न एक दिन तो यह होना ही है, लेकिन उचित यह होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली है और दूसरे विभाजनकारी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ अभी भी नहीं उठाए जा सके हैं। उदाहरणस्वरूप पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते कश्मीर से जो लाखों कश्मीरी हिंदू पलायन के लिए विवश हुए थे, वे अभी अपने घरों को लौटने में सक्षम नहीं। इसका मुख्य कारण उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं और देश के दूसरे हिस्सों से गए लोगों को रह-रहकर निशाना बनाया जाता रहता है। ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के पहले ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाए, जिससे जो कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौटना चाहते हैं, वे ऐसा करने में समर्थ रहें। इसके साथ ही यहां ऐसे उपाय भी अवश्य किए जाने चाहिए, जिससे अलगाव और आतंक के समर्थक चुनाव प्रक्रिया का लाभ न उठाने पाएं।

एक था अकबरनगर

कुकरैल नदी की जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर लखनऊ प्रशासन ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सभी छोटी नदियों को कब्जा मुक्त करने में प्रेरक हो सकता है। इस नदी पर 40 साल से अकबरनगर बसा हुआ था और अतिक्रमण करने वालों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि उन्होंने बड़े-बड़े शापिंग माल तक खोल लिए थे और करोड़ों रुपये का व्यवसाय कर रहे थे। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नदी के बहाव क्षेत्र के एक लाख वर्गमीटर क्षेत्र को मात्र आठ दिन में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अब नदी के पुनर्जीवन की संभावनाएं बन गई हैं और गोमती में जा रही शहर के नालों की गंदगी भी रोकी जा सकेगी। कुकरैल नदी की जमीन को कब्जा मुक्त कराने को सभी छोटी नदियों की आजादी की एक सार्थक पहल के रूप में देखा जा सकता है। अगर लखनऊ का प्रशासनिक तंत्र इतने बड़े अभियान का सफल संचालन कर सकता है तो अन्य जिलों का क्यों नहीं। आखिर सभी जगह नदियों पर वर्षों से अवैध कब्जे बरकरार हैं। कुकरैल नदी पर अतिक्रमण का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और अब कब्जा करके बसे अकबरनगर का अस्तित्व समाप्त है। इस नदी के बहाव क्षेत्र में हटाए गए अवैध निर्माण में राजनीति के दो पक्ष देखे जा सकते हैं। एक पक्ष अपने राजनीतिक लाभ के लिए वहां लोगों को बसाता है जबकि दूसरा जल संरक्षण के सरोकारों को प्रमुखता देते हुए नदी को ऐसे कब्जेदारों से मुक्त कराता है। राजनीतिक दलों के लिए वोट महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नदियों की कीमत पर उनकी लालसा नहीं होनी चाहिए। अब राज्य सरकार को कुकरैल के संरक्षण, संवर्धन के साथ उसके सौंदर्य की चिंता करनी चाहिए। इसे ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो।

लोकसभा अध्यक्ष के चयन की चुनौती

राज कुमार सिंह

लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राजग के घटक दलों में परस्पर विश्वास की पहली अग्निपरीक्षा होगी और उससे गठबंधन की स्थिरता के संकेत भी मिलेंगे

किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर सदन में पीठासीन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि नई लोकसभा के गठन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासी दांवपेच के सिलसिले ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में विपक्ष जहां राजग के सहयोगी दलों को लोकसभा अध्यक्ष पद पर दावेदारी के लिए उकसा रहा है वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अपना दावा भी ठोक रहा है। उसने संकेत दिए हैं कि उपाध्यक्ष पद न दिए जाने पर वह अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। ऐसी स्थिति में पहली बार इस पद के लिए चुनाव देखने को मिल सकता है और आम सहमति से लोकसभा अध्यक्ष चुनने की परंपरा खंडित हो सकती है। पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिपरिषद के गठन और महत्वपूर्ण विभागों के आवंटन का पेच तो सुलझा चुके हैं, लेकिन उनके लिए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की चुनौती का तोड़ निकालना अभी शेष है। चूंकि लगातार दो बार भाजपा को अपने दम पर बहुमत प्राप्त था तो पार्टी अपनी पसंद के लोकसभा अध्यक्ष को चुनती आई थी और ऐसी सरकारों में अध्यक्ष का रणनीतिक महत्व भी उतना नहीं रहा।

इस बार हालात बदले हुए हैं। बड़े फैसलों के लिए मोदी सरकार को सहयोगी दलों के समर्थन की दरकार होगी। मंत्रिमंडल गठन में दबाव बनाने से तेदेपा के चंद्रबाबू नायडू और जदयू के नीतीश कुमार ने शायद इसलिए भी परहेज किया हो कि उन पर 'सौदेबाज' का ठप्पा न लगे, लेकिन अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज तथा अपने दल की सुरक्षा की दृष्टि से लोकसभा अध्यक्ष न सही, लेकिन उपाध्यक्ष का पद मांगने से शायद ही वे चूकें। भाजपा के बाद तेदेपा और जदयू ही राजग में दूसरे और तीसरे बड़े दल हैं। सदन संचालन और सरकार के संकटकाल में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निर्णायक होती है। लोकसभा अध्यक्ष को दलगत राजनीति से परे निष्पक्ष रूप से सदन के संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन पीए संगमा और सोमनाथ चटर्जी जैसे ऐसे कुछ स्पीकर सिर्फ अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। वर्ष 1967 में लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर नीलम संजीव रेड्डी ने तो कांग्रेस की सदस्यता से भी यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि स्पीकर को किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वही संजीव रेड्डी 1977 में दूसरी बार अध्यक्ष बने। कुछ समय बाद वह देश के निर्विरोध राष्ट्रपति भी बने। वर्ष 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु संधि के विरोध में मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने पर माकपा चाहती थी कि उसके सदस्य सोमनाथ चटर्जी स्पीकर पद छोड़ दें, लेकिन उन्होंने खुद को दलगत राजनीति से ऊपर बताते हुए इससे इन्कार कर दिया। बाद में माकपा ने चटर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया।

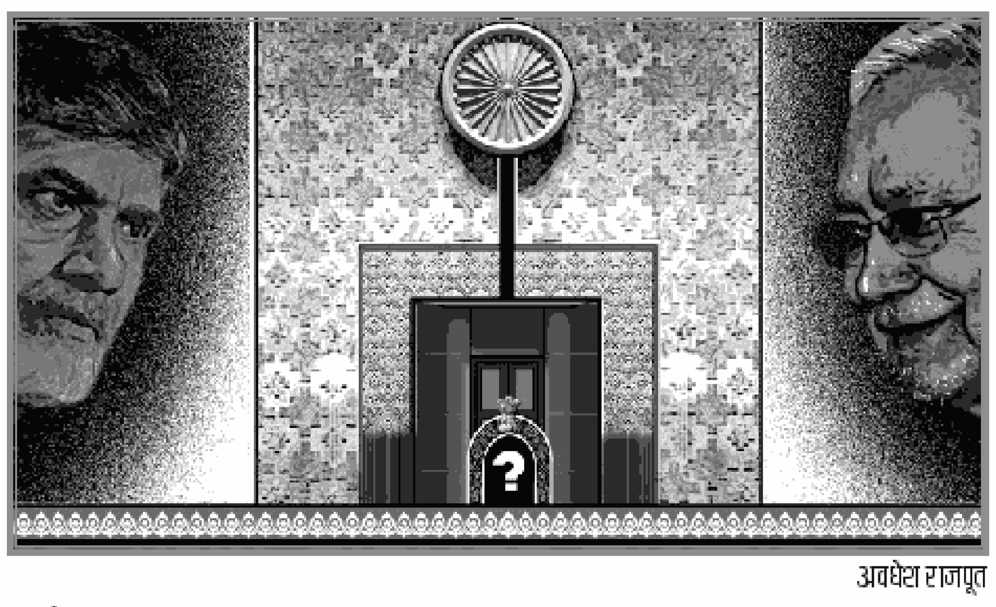

अवधेश राजपूत

विडंबना यह है कि पिछले कुछ दशकों में स्पीकर का पद दलगत राजनीति का अखाड़ा बन गया है। संवेदनशील मुद्दे पर बहस या अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय में तो स्पीकर की भूमिका अहम रहती ही है, किसी दल में बगावत या विभाजन में वह निर्णायक बन जाता है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के घटनाक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका की राजनीतिक गलियारों से लेकर न्यायपालिका तक में कड़ी आलोचना हुई। पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्वकाल में तत्कालीन स्पीकर शिवराज पाटिल ने अजित सिंह के जनता दल में विभाजन को एक जारी प्रक्रिया करार दिया था। शायद ऐसे उदाहरणों के चलते भी 16 सांसदों वाली तेदेपा और 12 सांसदों वाला जदयू लोकसभा अध्यक्ष के मुद्दे पर जोखिम मोल न लेना चाहें। सत्तारूढ़ दल के लिए छोटे दलों में विभाजन कराना मुश्किल नहीं होता। फिर इन दोनों दलों के अतीत में भाजपा से खट्टे-मीठे रिश्ते रहे हैं। दूसरी ओर मोदी भी इतना महत्वपूर्ण पद अपने सहयोगियों को देने के लिए आसानी से राजी नहीं होंगे, क्योंकि तब सरकार पर सहयोगियों के अंकुश के विकल्प बढ़ जाएंगे।

भाजपा 15 अप्रैल, 1999 को वाजपेयी सरकार का एक वोट से नाटकीय पतन भी नहीं भुला सकती। तब तेदेपा के ही जीएमसी बालयोगी स्पीकर थे। अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापसी पर स्वयं ही बहुमत साबित करने के क्रम में गिरने वाली उस पहली सरकार के पतन में बसपा द्वारा कदम पीछे खींचने की बड़ी भूमिका रही, लेकिन अंत में ओडिशा के मुख्यमंत्री बन चुके कांग्रेसी सांसद गिरधर गोमांग को मतदान में भाग लेने की स्पीकर द्वारा दी गई अनुमति निर्णायक साबित हुई। गोमांग के वोट बिना पक्ष-विपक्ष के वोट समान होते और स्पीकर निर्णायक वोट दे पाते। गठबंधन की सरकारों में स्पीकर पद सहयोगी दलों को दिए जाने की एक अघोषित परंपरा भी रही है। वाजपेयी की राजग सरकार में तेदेपा के जीएमसी बालयोगी के बाद शिवसेना के मनोहर जोशी भी स्पीकर बने। मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार में भी माकपा के सोमनाथ चटर्जी स्पीकर बनाए गए। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 24-25 जून को शपथ दिलाने के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। फिर 26 जून को नए स्पीकर का चुनाव सदन में मौजूद सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। मोदी सरकार के नजरिये से तो पिछली लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का कार्यकाल अच्छा ही रहा। बिरला फिर चुनकर आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों के निलंबन के मद्देनजर राजग सहयोगियों को भी उनके नाम पर आपत्ति हो सकती है। राजग में सहमति की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। भाजपा आंध्र प्रदेश से अपनी सांसद डी. पुरंदेश्वरी का नाम आगे बढ़ा रही है। उनका सशक्त पक्ष यह है कि वह तेदेपा के संस्थापक स्वर्गीय एनटी रामाराव की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं। इस बार भाजपा और तेदेपा में गठबंधन कराने में भी उनकी भूमिका बताई जा रही है। पिछले चुनाव के परिणामों के मद्देनजर गठबंधन दोनों दलों की जरूरत भी थी, लेकिन नायडू अपनी राजनीति की चाबी पुरंदेश्वरी के हाथ शायद ही देने को राजी हों। ऐसे में नए लोकसभा अध्यक्ष का चयन राजग के घटक दलों में परस्पर विश्वास की पहली अग्निपरीक्षा भी बनता दिख रहा है। भविष्य का संकेत भी इससे मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय सदन के संरक्षक की विश्वसनीयता को लेकर उठने वाले सवाल का होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

घातक सिद्ध होती प्रकृति से छेड़छाड़

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मानसून के आगमन के बीच हम सब इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि इस बार कितनी अधिक गर्मी पड़ रही है और लू का कहर किस तरह जानलेवा सिद्ध हुआ। गर्मी और लू के प्रकोप का सामना दुनिया के अन्य देशों को भी करना पड़ रहा है। निःसंदेह मानसून राहत देगा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मौसम में अप्रत्याशित बदलाव खतरे की एक घंटी है। पर्यावरणविदों के अध्ययनों के आधार पर यह पहले ही साफ हो चुका था कि 2024 में गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है। पर्यावरणविदों के अनुसार इस वर्ष अल नीनो का असर होगा और फिर उसके तत्काल बाद ला नीना का भी। अल नीनो गर्मी को बढ़ाएगा तो ला नीना शीतकालीन परिस्थितियों को और गंभीर कर देगा। एक अध्ययन के अनुसार 2023 में अल नीनो ने पिछले साल जुलाई को अत्यधिक गर्म किया। वैसे ही हालात इस साल जून के आसपास दिखे। अपने देश में देखें तो दिल्ली में तापक्रम 50 के आसपास पहुंच गया। अन्य शहरों में भी इसी के आसपास तामपान पहुंचा। पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ी तो जैसलमेर में तापमान ने 55 का आंकड़ा छू लिया। अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 2024 तापक्रम वृद्धि को लेकर अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। 2016 से 2019 के बाद 2023 में ही अल नीनो दूसरी बार आया और दिसंबर 2023 में यह अपने चरम पर था। समुद्री वायुमंडल के हालात बिगड़ने के कारण अगस्त 2024 में यह और प्रभाव डालेगा। इसके तुरंत बाद ला नीना के प्रभाव की आशंका है।

इस बार जापान और मेक्सिको में बसंत से पहले ही फूल खिलने लगे थे। इसी तरह यूरोप में फरवरी-मार्च में ही हिमखंड पिघलने लगे। इसी समय अमेरिका के टेक्सास में तापक्रम 38 डिग्री के पार चला गया था। भारत में भी गर्मी के जल्दी आने से वनों की आग ज्यादा घातक हो गई। जापान से मेक्सिको तक तापक्रम की वृद्धि पिछले कई महीनों से लगातार देखी रही है और पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ बड़े मूलभूत परिवर्तन आ रहे हैं। अपने देश में जनवरी-फरवरी कुछ इस तरह से बीते, जैसे बसंत आ गया हो। बीते जाड़े में भी ठंड का अधिक प्रभाव नहीं था। वास्तव में लगातार लंबे समय से मौसम के व्यवहार का सही अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है।

अनिल जोशी

मौसम में अप्रत्याशित बदलाव लंबे समय से देखने को मिल रहा है, लेकिन हम चेत नहीं रहे हैं

मुसीबत बढ़ाता प्रतिकूल मौसम। फाइल

देश में बसंत वाली गर्मी पहले ही आ गई थी और उसने वनाग्नि जैसे दावानल के लिए दरवाजे खोल दिए। यह भी संज्ञान में लेना जरूरी है कि पश्चिमी विक्षोभ, जो पहले नवंबर-दिसंबर के महीने में आता था, इस बार फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में ही दिखाई दे गया। यह एक बहुत बड़ा लक्षण है कि अब मौसम का समयानुसार प्रभाव नहीं रहा। मौसम के अनुकूल न होने के कारण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ रहा है। इसके असर को खेती-बाड़ी से लेकर वनों में बढ़ती हुई आग को लेकर देखा जा सकता है। इसके साथ तूफान और बाढ़ कब आ जाए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकेगी। मौसम विभाग अब आने वाले समय में मौसम के हालात का सटीक विश्लेषण मुश्किल से कर पाएगा।

मौसम में अप्रत्याशित बदलाव का सीधा असर पूरे आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ना तय है। तापक्रम के बढ़ने के कारण इसका असर वन्य जीव से लेकर मनुष्यों पर दिखाई देगा। कई तरह की बीमारियां भी पनपेंगी। खास तौर से वे, जो उमस के कारण आती हैं। उमस भरी गर्मी को झेलने के लिए एसी का उपयोग वातावरण में और गर्मी तो पैदा करेगा ही, वायु प्रदूषण के हालात और भी गंभीर हो जाएंगे, जो सीधे ही पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत असर डालेंगे। इसका सीधा मतलब है कि जल, जंगल, जमीन बढ़ते तापक्रम के कारण आदर्श व्यवहार नहीं कर पाएंगे।

एक लंबे समय से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहा है, लेकिन हम चेत नहीं रहे हैं। यह कड़वा सच है कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा कि हम अपनी पुरानी परिस्थितियों को वापस ला पाएं। हम जहां हालात को ले जा चुके हैं, वहां से हमारी वापसी पांच से 10 प्रतिशत ही बची है। इसका कारण यह है कि हम अपने जीवन को आरामदेह बनाने में लगे हैं। आरामदायक जीवनशैली आज की आवश्यकता बन गई है, लेकिन हम यह देखने से इन्कार कर रहे हैं कि आधुनिक जीवनशैली के चलते हमने पृथ्वी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अपने प्रतिकूल बना लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर धरती को प्रतिकूल मौसम से बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतना तो हमारी समझ में आना ही चाहिए कि हम पृथ्वी को उतना ही भोगें, जितना उसमें जोड़ पाएं। पिछले दो-तीन सौ वर्षों में हमने पृथ्वी से जितना कुछ लिया है, उसका पांच प्रतिशत भी उसे वापस नहीं कर पाए हैं।

हम अपने काम का तो नफा-नुकसान जांचते हैं, पर धरती के पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब-किताब में फेल हैं। प्रकृति के पास कई तरीके हैं कि वह हमें रास्ते पर लाए। कुछ अप्रत्याशित रूप में प्रकट होगा, जो हमसे कुछ छीन लेगा। कोविड की मार तो याद होगी ही। वह प्रकृति कहर ही था, जिसने हमें बताया था कि हमें समय रहते अपनी सीमाएं तय कर लेनी चाहिए। प्रकृति हमारी मनमानी ज्यादा सहन नहीं करेगी। हम सुनार की तरह ही गए हैं, जो जीवन की चमक-दमक देखते हैं, जबकि प्रकृति लोहार की तरह है, जो तप-खप कर बनी है। यह कहावत तो हमें पता ही होगी कि सौ सुनार की और एक लोहार की। मतलब टुकड़ों-टुकड़ों में हमारी चोटों के बदले लोहार की एक ही चोट हमें नेस्तनाबूद करने के लिए काफी होगी।

(लेखक पर्यावरणविद् हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

संकट से कैसे उबरें

समय एक-सा नहीं रहता। छोटी-बड़ी कठिनाइयां और चुनौतियां आती-जाती रहेंगी, सफलता का मार्ग इन्हीं से जूझ कर मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में दो विकल्प रहते हैं- घुटने टेक दें या उसका सामना करें। घुटने टेकना सरल है। औसत सोच वाला यही करता है। फिर वह अपनी दुर्दशा हर किसी को बांचता, भाग्य को कोसता है। दूसरी ओर, स्वयं की अथाह शक्ति के प्रति आश्वस्त व्यक्ति विकट परिस्थिति से कतराता नहीं, बल्कि उससे भिड़ता और विजयी हो कर यश का भागी बनता है। अपनी व्यथा दूसरों से साझा करना स्वीकारोक्ति है कि संबद्ध व्यक्ति को कुछ नहीं सूझ रहा और उसे सहानुभूति चाहिए। अपनी चिंताएं दूसरों पर डालता व्यक्ति घर-परिवार और समाज पर बोझ होता है। अधिसंख्य जन उससे दूरी बना लेते हैं। समाज और राष्ट्र निर्माण में हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए, जो दूसरों को सशक्त बनाएं, वे नहीं जो स्वयं पर बोझ हों।

जीवन का भरपूर आनंद वे लोग उठाते हैं, जो संकट के क्षणों में शिकायती मुद्रा में ढल जाने की अपेक्षा अपने मन का दीप प्रज्वलित करते हैं। संकट जितना गहरा होता है उसी अनुपात में अंतर्निहित दीप को प्रकाशवान करना होता है। फिर एक नवनिर्मित आभा सभी दिशाओं से अनुकूल शक्तियों को आकृष्ट करती है। तब अप्रत्याशित स्रोतों से सहायतार्थ प्रकट हुए अनेक हाथ पूछने लगते हैं कि "तुम्हें क्या चाहिए?" मनुष्य प्रेम, सौंदर्य और प्रकाश की ओर आकृष्ट होता है। दूसरों पर सवार रहने का अवसर तलाशने वाले का दीप नहीं जलता। विपन्नता और नैराश्य के दौर में मुख मुद्रा को प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त रखने के अभ्यस्त हो जाएंगे तो राह अवश्य मिलेगी। जिसने कालचक्र के थपेड़े सहे, उनसे सीखा और स्वयं को तराशा, उसी ने बुलंदियां छुईं। अतः प्रत्येक समस्या को उपहार मानें।

हरीश बड़थ्वाल

स्कूली पाठ्यक्रम में समाचार पत्र

देवेंद्रराज सुथार

केरल के सभी स्कूलों में हर कक्षा के बच्चों को समाचार पत्र उपलब्ध कराने और इसे पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने की पहल की जा रही है, जो एक जागरूक, साक्षर और सक्रिय पीढ़ी को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कदम है। केरल राज्य शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा उठाया गया यह कदम छात्रों के बीच पढ़ने की संस्कृति और भाषा कौशल को बढ़ाने में समाचार पत्र की भूमिका की समझ को दर्शाता है। डिजिटल स्क्रीन के वर्चस्व वाले युग में समाचार पत्र पढ़ने की आदत सूचना उपभोग के लिए अधिक विचारशील दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है।

समाचार पत्र ज्ञान के समृद्ध भंडार होते हैं, जो पाठकों को राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, संस्कृति और खेल से जुड़ी वर्तमान घटनाओं के साथ लगातार अपडेट करते रहते हैं। स्कूल के पाठ्यक्रम में समाचार पत्र को शामिल करने से छात्रों को वास्तविक समय की जानकारी और

स्कूली पाठ्यक्रम में समाचार पत्र को शामिल करके केरल उदाहरण स्थापित कर रहा है, जिसका अनुसरण अन्य राज्यों को भी करना चाहिए

विविध दृष्टिकोणों तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी, जिससे उन्हें अपने आस-पास की दुनिया की सूक्ष्म समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण लाभ भाषा कौशल में वृद्धि है। समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ने से छात्रों को शब्दावली, परिष्कृत वाक्य संरचनाओं और विभिन्न लेखन शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला से परिचित होने का अवसर मिलेगा। उच्च गुणवत्ता वाली भाषा में यह तल्लीनता पढ़ने की समझ, लेखन क्षमता और समग्र साक्षरता में सुधार के लिए अमूल्य है। इसके अलावा समाचार पत्र पढ़ने का अभ्यास छात्रों के बोलने और सुनने के कौशल को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इससे उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद मिलेगी। वे विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने में रुचि दिखाएंगे। यह अभ्यास आलोचनात्मक सोच, संवाद और बहस की संस्कृति को बढ़ावा देगा, जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है।

आज की सूचना-समृद्ध दुनिया में मीडिया साक्षरता एक आवश्यक योग्यता है। समाचार पत्र की सामग्री के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ने से छात्र विश्वसनीय समाचार और गलत सूचना के बीच अंतर करना सीखेंगे। यह कौशल ऐसे युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं व्याप्त हैं, जो अक्सर भ्रम और गलतफहमी का कारण बनती हैं। पाठ्यक्रम में समाचार पत्र को शामिल करने से सीखने के लिए कई रचनात्मक रास्ते भी खुलेंगे। स्कूली पाठ्यक्रम में समाचार पत्रों को शामिल करके केरल उदाहरण स्थापित कर रहा है जिसका अनुसरण अन्य राज्यों को करना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

एनटीए और पेपर लीक

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए परीक्षा कराने के लिए एनटीए का गठन हुआ था, लेकिन यह संस्थान आज पेपर लीक कराने के मामले में सुर्खियां बटोर रहा है। 'एक और परीक्षा से खिलवाड़' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में उचित ही कहा गया है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा इतना संवेदनशील कार्य ठेके पर क्यों कराया जाता है? वह भी ऐसे लोगों को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाता है जिन्हें इसका कोई अनुभव नहीं होता। नेताओं के लिए ड्राइवर से लेकर खाना बनाने वाले तक सबके सब कर्मचारी अनुभवी रखे जाते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। बस, ट्रेन आदि से सफर करने के लिए जनता पैसे देकर टिकट लेती है और यदि कोई बिना टिकट के सफर करता पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगता है। यदि कोई कोर्ट का कीमती समय नष्ट करता है तो उस पर भी जुर्माना लगता है। ऐसे ही जब इतनी बड़ी सरकारी संस्था लाखों अभ्यर्थियों के समय, संसाधन और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो प्रशासन चुप क्यों है? वह भी तब जब इससे जुड़े तमाम सुबूत सामने आ रहे हैं। क्या अभ्यर्थियों का समय कीमती नहीं है? सब नियम-कानून क्या सिर्फ जनता के लिए हैं? नीट-यूजी, नेट, यूपी पुलिस भर्ती, आरओ/एआरओ आदि कितनी ही परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, पर जितनी तेजी से पेपर लीक हो रहे हैं उतनी तेजी से अभ्यर्थियों को न तो इंसाफ मिल रहा है और न ही अपने भविष्य के लिए कोई उचित राह। ऐसे में छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं से भरोसा उठना जायज है। जब देश का पढ़ा-लिखा युवावर्ग इस प्रकार की मानसिक पीड़ा से गुजरेगा तो देश का विकास कैसे होगा? यह अत्यंत ही गंभीर विषय है।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

किसानों की कमाई बढ़ाए सरकार

कृषक वर्ग की आशंकाओं को खारिज करते हुए नरेन्द्र मोदी सरकार ने खरीफ सीजन की 14 फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे कर सराहनीय काम किया है। किसानों को उनकी उपज के लिए उचित दाम मिल जाए तो इससे कृषि कार्य करने का कष्ट कम और आनंद अधिक हो जाएगा। धान, चावल, मक्का, मूंग एवं अरहर दाल, सोयाबीन और मूंगफली आदि कई फसलों की खेती करने वाले किसान लाभान्वित होंगे। हालांकि भुगतान में देरी के कारण कई किसानों का समय, धन और ऊर्जा एमएसपी का लाभ प्राप्त करने में व्यर्थ हो जाते हैं। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों पर खर्च बढ़ने से किसान की कमाई का शुद्ध लाभ कम हो रहा है। किसानों की कमाई बढ़ाने में केंद्र और राज्य सरकारें और प्रयास करें।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

राष्ट्रीय अखंडता जरूरी

"राष्ट्रीय हितों पर बने सहमति" शीर्षक से प्रकाशित आलेख में विवेक काटजू ने प्रधानमंत्री की नैतिकता, परिपक्वता तथा देश के प्रति कटिबद्धता को सटीक अंकित किया है। गठबंधन सरकार का कुशलतापूर्वक नेतृत्व बहुत कठिन है। निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निपुणता, कुशाग्रता तथा लोकप्रियता का डंका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार की नीतियों तथा कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होने और सहयोगियों के पूर्ण समर्थन के बावजूद आगामी संसद की कार्यवाही के दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच अधिक तनाव और खींचतान की आशंका है। पक्ष-विपक्ष में वाद-विवाद टकराव के बजाय संवाद से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जहां तक चीन-पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों का मुद्दा है, देशवासियों को एकमत तथा एकजुट होकर सामना करने की जरूरत है। माना कि सत्तारूढ़ दल की मनमानी नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है, लेकिन स्मरण रहे, अबकी बार संख्या में अधिक 'आइएनडीआइए' के उत्तेजनापूर्वक रवैये के कारण देश को क्षति नहीं पहुंचे, इसके लिए जज्बा-ए-हिंद की आवश्यकता है।

कृष्ण खन्ना, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

संपादकीय जागरण

(12) शनिवार, 22 जून, 2024 : ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा वि . 2081

समस्या कभी पैसे की नहीं होती, हमेशा विचार की होती है

जम्मू-कश्मीर में चुनाव

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कहकर जम्मू-कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जगाने का काम किया कि यहां के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल किया जाएगा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी उल्लेख किया। इन तैयारियों का संकेत चुनाव आयोग की ओर मतदाता सूचियां ठीक करने की घोषणा से भी मिला था और भाजपा की ओर से चुनाव प्रभारी नियुक्त करने से भी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में इस वर्ष सितंबर के पहले तक विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है, इसलिए यहां हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही चुनाव होने के आसार बढ़ गए हैं। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को इसलिए भी बल मिला है, क्योंकि हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में जम्मू के साथ-साथ कश्मीर के लोगों ने भी बढ़-चढ़कर मतदान में भाग लिया। इससे यही स्पष्ट हुआ कि घाटी के लोग मुख्यधारा में शामिल होने को तैयार हैं और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की महत्ता भी समझ चुके हैं। यह स्थिति बनी तो इसीलिए, क्योंकि एक ओर जहां कश्मीर में आतंक का असर कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया निष्पक्षता से आयोजित की गई। इसका श्रेय चुनाव आयोग को भी जाता है और केंद्रीय सत्ता के साथ सुरक्षा बलों को भी। निःसंदेह प्रधानमंत्री के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली चुनाव के पहले होगी या बाद में। चूंकि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने की प्रतिबद्धता कई बार व्यक्त कर चुकी है, इसलिए एक न एक दिन तो यह होना ही है, लेकिन उचित यह होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद से पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली है और दूसरे विभाजनकारी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ अभी भी नहीं उठाए जा सके हैं। उदाहरणस्वरूप पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते कश्मीर से जो लाखों कश्मीरी हिंदू पलायन के लिए विवश हुए थे, वे अभी अपने घरों को लौटने में सक्षम नहीं। इसका मुख्य कारण उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं और देश के दूसरे हिस्सों से गए लोगों को रह-रहकर निशाना बनाया जाता रहता है। ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के पहले ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाए, जिससे जो कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौटना चाहते हैं, वे ऐसा करने में समर्थ रहें। इसके साथ ही यहां ऐसे उपाय भी अवश्य किए जाने चाहिए, जिससे अलगाव और आतंक के समर्थक चुनाव प्रक्रिया का लाभ न उठाने पाएं।

अब पौधरोपण अभियान चले

तीखी गर्मी के दिनों में शुरू हुआ पेड़ लगाने का विमर्श मानसून की पहली फुहार के साथ कमजोर हो जाएगा। अधिक वर्षा हुई तो उसमें यह विमर्श जो डूबेगा, अगले साल गर्मी के समय ही निकल पाएगा। प्रकृति के प्रति यही मौसमी दृष्टिकोण कोप की जड़ में है। शहर में लोग घर बनाएंगे तो उसमें छायादार वृक्ष क्या फूल-छोटा पौधा लगाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ेंगे। शौक के लिए गमले में फूल लगाएंगे और डींग हांकेंगे कि देखो, हमने हरियाली का कितना ख्याल रखा है। बिहार विभाजन के बाद जब राज्य के हिस्से में वनों का क्षेत्रफल कम हुआ तो पेड़ लगाने के लिए अभियान चला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें खूब रुचि दिखाई। सरकार के कई विभाग इस काम में लगे। हरित अभियान और जल-जीवन-हरियाली मिशन चल रहा है। चौदह साल पहले तो सत्तारूढ़ जदयू ने दल की सदस्यता के लिए शर्त रख दी। पेड़ लगाइए। सदस्यता पाइए। लोग पौधे के साथ तस्वीर लेकर आए और सदस्य बन गए। बाद में पता चला कि कुछ लोगों ने पौधा के बदले टहनियों को रोप कर फोटो बना लिया था। यह पुरानी बात है। अब, जबकि हर आदमी सहमत है कि पर्यावरण और उससे भी अधिक जीवन को बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है, इस अभियान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कोई सरकारी अभियान जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता है। सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक करोड़ पौधा लगाए और उसकी सुरक्षा-देखरेख के लिए दस-पांच लाख कारिंदे बहाल कर दे। समाज अगर ऐसा सोचे तो फिर भगवान भी उसका मालिक नहीं बनना चाहेगा। सो, अगर लोग सचमुच अपने जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंतित हैं तो इस बरसात में पौधरोपण अभियान से जुड़ें।

> अगर सचमुच अपने जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंतित हैं तो इस बरसात में पौधरोपण अभियान से जुड़ें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

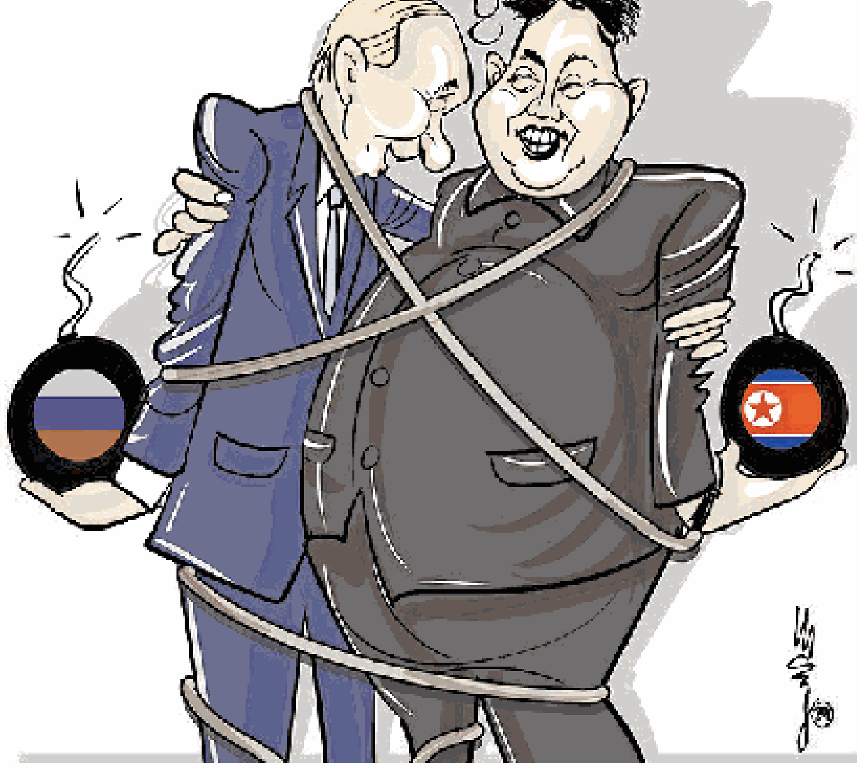

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एक दिन बाद ही यूजीसी नेट परीक्षा को रद किया जाना एनटीए की अक्षमता को उजागर करता है?

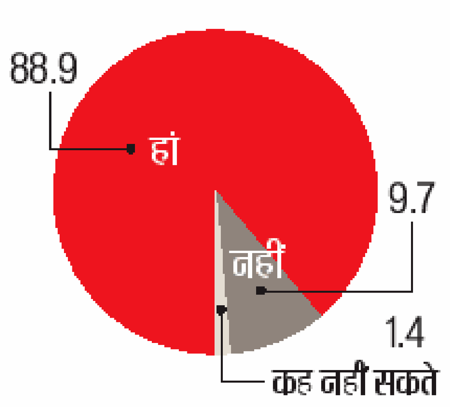

आज का सवाल
क्या सभी प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होने से पेपर लीक के मामले रुक जाएंगे?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

लोकसभा अध्यक्ष के चयन की चुनौती

राज कुमार सिंह

लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राजग के घटक दलों में परस्पर विश्वास की पहली अग्निपरीक्षा होगी और उससे गठबंधन की स्थिरता के संकेत भी मिलेंगे

किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर सदन में पीठासीन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि नई लोकसभा के गठन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासी दांवपेच के सिलसिले ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में विपक्ष जहां राजग के सहयोगी दलों को लोकसभा अध्यक्ष पद पर दावेदारी के लिए उकसा रहा है वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अपना दावा भी ठोक रहा है। उसने संकेत दिए हैं कि उपाध्यक्ष पद न दिए जाने पर वह अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। ऐसी स्थिति में पहली बार इस पद के लिए चुनाव देखने को मिल सकता है और आम सहमति से लोकसभा अध्यक्ष चुनने की परंपरा खंडित हो सकती है। पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिपरिषद के गठन और महत्वपूर्ण विभागों के आवंटन का पेच तो सुलझा चुके हैं, लेकिन उनके लिए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की चुनौती का तोड़ निकालना अभी शेष है। चूंकि लगातार दो बार भाजपा को अपने दम पर बहुमत प्राप्त था तो पार्टी अपनी पसंद के लोकसभा अध्यक्ष को चुनती आई थी और ऐसी सरकारों में अध्यक्ष का रणनीतिक महत्व भी उतना नहीं रहा।

इस बार हालात बदले हुए हैं। बड़े फैसलों के लिए मोदी सरकार को सहयोगी दलों के समर्थन की दरकार होगी। मंत्रिमंडल गठन में दबाव बनाने से तेदेपा के चंद्रबाबू नायडू और जदयू के नीतीश कुमार ने शायद इसलिए भी परहेज किया हो कि उन पर 'सौदेबाज' का ठप्पा न लगे, लेकिन अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज तथा अपने दल की सुरक्षा की दृष्टि से लोकसभा अध्यक्ष न सही, लेकिन उपाध्यक्ष का पद मांगने से शायद ही वे चूकें। भाजपा के बाद तेदेपा और जदयू ही राजग में दूसरे और तीसरे बड़े दल हैं। सदन संचालन और सरकार के संकटकाल में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका निर्णायक होती है। लोकसभा अध्यक्ष को दलगत राजनीति से परे निष्पक्ष रूप से सदन के संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन पीए संगमा और सोमनाथ चटर्जी जैसे ऐसे कुछ स्पीकर सिर्फ अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। वर्ष 1967 में लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर नीलम संजीव रेड्डी ने तो कांग्रेस की सदस्यता से भी यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि स्पीकर को किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वही संजीव रेड्डी 1977 में दूसरी बार अध्यक्ष बने। कुछ समय बाद वह देश के निर्विरोध राष्ट्रपति भी बने। वर्ष 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु संधि के विरोध में मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने पर माकपा चाहती थी कि उसके सदस्य सोमनाथ चटर्जी स्पीकर पद छोड़ दें, लेकिन उन्होंने खुद को दलगत राजनीति से ऊपर बताते हुए इससे इन्कार कर दिया। बाद में माकपा ने चटर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया।

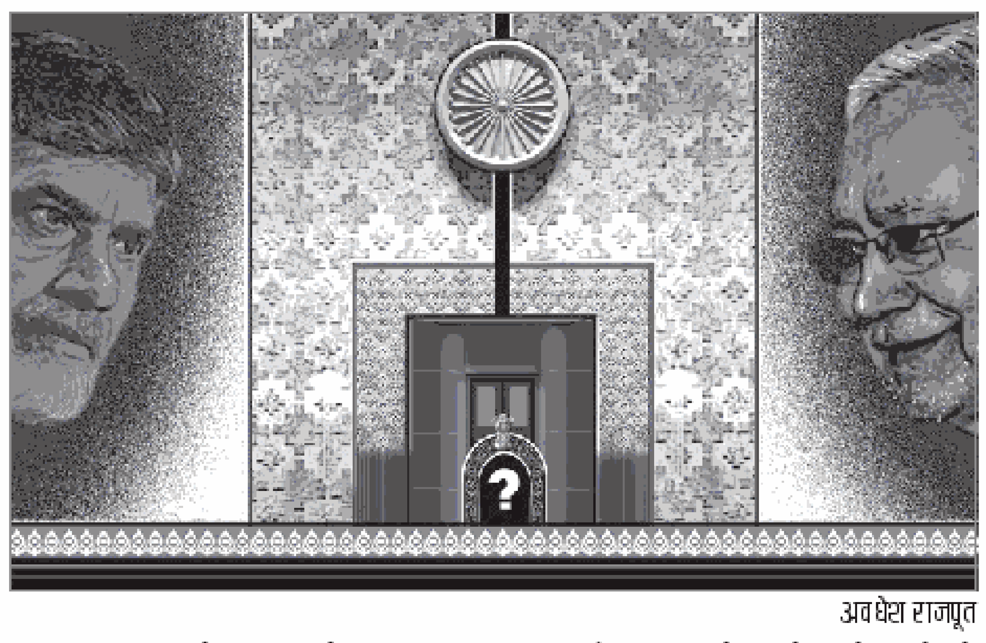

अवधेश राजपूत

विडंबना यह है कि पिछले कुछ दशकों में स्पीकर का पद दलगत राजनीति का अखाड़ा बन गया है। संवेदनशील मुद्दे पर बहस या अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय में तो स्पीकर की भूमिका अहम रहती ही है, किसी दल में बगावत या विभाजन में वह निर्णायक बन जाता है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के घटनाक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका की राजनीतिक गलियारों से लेकर न्यायपालिका तक में कड़ी आलोचना हुई। पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्वकाल में तत्कालीन स्पीकर शिवराज पाटिल ने अजित सिंह के जनता दल में विभाजन को एक जारी प्रक्रिया करार दिया था। शायद ऐसे उदाहरणों के चलते भी 16 सांसदों वाली तेदेपा और 12 सांसदों वाला जदयू लोकसभा अध्यक्ष के मुद्दे पर जोखिम मोल न लेना चाहें। सत्तारूढ़ दल के लिए छोटे दलों में विभाजन कराना मुश्किल नहीं होता। फिर इन दोनों दलों के अतीत में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से खट्टे-मीठे रिश्ते रहे हैं। दूसरी ओर मोदी भी इतना महत्वपूर्ण पद अपने सहयोगियों को देने के लिए आसानी से राजी नहीं होंगे, क्योंकि तब सरकार पर सहयोगियों के अंकुश के विकल्प बढ़ जाएंगे।

भाजपा 15 अप्रैल, 1999 को वाजपेयी सरकार का एक वोट से नाटकीय पतन भी नहीं भुला सकती। तब तेदेपा के ही जीएमसी बालयोगी स्पीकर थे। अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापसी पर स्वयं ही बहुमत साबित करने के क्रम में गिरने वाली उस पहली सरकार के पतन में बसपा द्वारा कदम पीछे खींचने की बड़ी भूमिका रही, लेकिन अंत में ओडिशा के मुख्यमंत्री बन चुके कांग्रेसी सांसद गिरधर गोमांग को मतदान में भाग लेने की स्पीकर द्वारा दी गई अनुमति निर्णायक साबित हुई। गोमांग के वोट बिना पक्ष-विपक्ष के वोट समान होते और स्पीकर निर्णायक वोट दे पाते। गठबंधन की सरकारों में स्पीकर पद सहयोगी दलों को दिए जाने की एक अघोषित परंपरा भी रही है। वाजपेयी की राजग सरकार में तेदेपा के जीएमसी बालयोगी के बाद शिवसेना के मनोहर जोशी भी स्पीकर बने। मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार में भी माकपा के सोमनाथ चटर्जी स्पीकर बनाए गए। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 24-25 जून को शपथ दिलाने के लिए सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। फिर 26 जून को नए स्पीकर का चुनाव सदन में मौजूद सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। मोदी सरकार के नजरिये से तो पिछली लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का कार्यकाल अच्छा ही रहा। बिरला फिर चुनकर आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों के निलंबन के मद्देनजर राजग सहयोगियों को भी उनके नाम पर आपत्ति हो सकती है। राजग में सहमति की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। भाजपा आंध्र प्रदेश से अपनी सांसद डी. पुरंदेश्वरी का नाम आगे बढ़ा रही है। उनका सशक्त पक्ष यह है कि वह तेदेपा के संस्थापक स्वर्गीय एनटी रामाराव की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं। इस बार भाजपा और तेदेपा में गठबंधन कराने में भी उनकी भूमिका बताई जा रही है। पिछले चुनाव के परिणामों के मद्देनजर गठबंधन दोनों दलों की जरूरत भी थी, लेकिन नायडू अपनी राजनीति की चाबी पुरंदेश्वरी के हाथ शायद ही देने को राजी हों। ऐसे में नए लोकसभा अध्यक्ष का चयन राजग के घटक दलों में परस्पर विश्वास की पहली अग्निपरीक्षा भी बनता दिख रहा है। भविष्य का संकेत भी इससे मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय सदन के संरक्षक की विश्वसनीयता को लेकर उठने वाले सवाल का होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

घातक सिद्ध होती प्रकृति से छेड़छाड़

अनिल जोशी

मौसम में अप्रत्याशित बदलाव लंबे समय से देखने को मिल रहा है, लेकिन हम चेत नहीं रहे हैं

मानसून के आगमन के बीच हम सब इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि इस बार कितनी अधिक गर्मी पड़ रही है और लू का कहर किस तरह जानलेवा सिद्ध हुआ। गर्मी और लू के प्रकोप का सामना दुनिया के अन्य देशों को भी करना पड़ रहा है। निःसंदेह मानसून राहत देगा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मौसम में अप्रत्याशित बदलाव खतरे की एक घंटी है। पर्यावरणविदों के अध्ययनों के आधार पर यह पहले ही साफ हो चुका था कि 2024 में गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है। पर्यावरणविदों के अनुसार इस वर्ष अल नीनो का असर होगा और फिर उसके तत्काल बाद ला नीना का भी। अल नीनो गर्मी को बढ़ाएगा तो ला नीना शीतकालीन परिस्थितियों को और गंभीर कर देगा। एक अध्ययन के अनुसार 2023 में अल नीनो ने पिछले साल जुलाई को अत्यधिक गर्म किया। वैसे ही हालात इस साल जून के आसपास दिखे। अपने देश में देखें तो दिल्ली में तापक्रम 50 के आसपास पहुंच गया। अन्य शहरों में भी इसी के आसपास तामपान पहुंचा। पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ी तो जैसलमेर में तापमान ने 55 का आंकड़ा छू लिया। अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि 2024 तापक्रम वृद्धि को लेकर अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। 2016 से 2019 के तीन साल के लंबे दौर के बाद 2023 में ही अल नीनो दूसरी बार आया और दिसंबर 2023 में यह अपने चरम पर था। समुद्री वायुमंडल के हालात बिगड़ने के कारण अगस्त 2024 में यह और प्रभाव डालेगा। इसके तुरंत बाद ला नीना के प्रभाव की आशंका है।

इस बार जापान और मेक्सिको में बसंत से पहले ही फूल खिलने लगे थे। इसी तरह यूरोप में फरवरी-मार्च में ही हिमखंड पिघलने लगे। इसी समय अमेरिका के टेक्सास में तापक्रम 38 डिग्री के पार चला गया था। भारत में भी गर्मी के जल्दी आने से वनों की आग ज्यादा घातक हो गई। जापान से मेक्सिको तक तापक्रम की वृद्धि पिछले कई महीनों से लगातार देखी रही है और पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ बड़े मूलभूत परिवर्तन आ रहे हैं। अपने देश में जनवरी-फरवरी कुछ इस तरह से बीते, जैसे बसंत आ गया हो। बीते जाड़े में भी ठंड का अधिक प्रभाव नहीं था। वास्तव में लगातार लंबे समय से मौसम के व्यवहार का सही अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है। देश में बसंत वाली गर्मी पहले ही आ गई थी और उसने वनाग्नि जैसे दावानल के लिए दरवाजे खोल दिए। यह भी संज्ञान में लेना जरूरी है कि पश्चिमी विक्षोभ, जो पहले नवंबर-दिसंबर के महीने में आता था, इस बार फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में ही दिखाई दे गया। यह एक बहुत बड़ा लक्षण है कि अब मौसम का समयानुसार प्रभाव नहीं रहा। मौसम के अनुकूल न होने के कारण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ रहा है। इसके असर को खेती-बाड़ी से लेकर वनों में बढ़ती हुई आग को लेकर देखा जा सकता है। इसके साथ तूफान और बाढ़ कब आ जाए, इसकी कल्पना नहीं की जा सकेगी। मौसम विभाग अब आने वाले समय में मौसम के हालात का सटीक विश्लेषण मुश्किल से कर पाएगा।

मुसीबत बढ़ाता प्रतिकूल मौसम ● फाइल

मौसम में अप्रत्याशित बदलाव का सीधा असर पूरे आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ना तय है। तापक्रम के बढ़ने के कारण इसका असर वन्य जीव से लेकर मनुष्यों पर दिखाई देगा। कई तरह की बीमारियां भी पनपेंगी। खास तौर से वे, जो उमस के कारण आती हैं। उमस भरी गर्मी को झेलने के लिए एसी का उपयोग वातावरण में और गर्मी तो पैदा करेगा ही, वायु प्रदूषण के हालात और भी गंभीर हो जाएंगे, जो सीधे ही पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत असर डालेंगे। इसका सीधा मतलब है कि जल, जंगल, जमीन बढ़ते तापक्रम के कारण आदर्श व्यवहार नहीं कर पाएंगे।

एक लंबे समय से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहा है, लेकिन हम चेत नहीं रहे हैं। यह कड़वा सच है कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा कि हम अपनी पुरानी परिस्थितियों को वापस ला पाएं। हम जहां हालात को ले जा चुके हैं, वहां से हमारी वापसी पांच से 10 प्रतिशत ही बची है। इसका कारण यह है कि हम अपने जीवन को आरामदेह बनाने में लगे हैं। आरामदायक जीवनशैली आज की आवश्यकता बन गई है, लेकिन हम यह देखने से इन्कार कर रहे हैं कि आधुनिक जीवनशैली के चलते हमने पृथ्वी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को अपने प्रतिकूल बना लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर धरती को प्रतिकूल मौसम से बचाना मुश्किल हो जाएगा। इतना तो हमारी समझ में आना ही चाहिए कि हम पृथ्वी को उतना ही भोगें, जितना उसमें जोड़ पाएं। पिछले दो-तीन सौ वर्षों में हमने पृथ्वी से जितना कुछ लिया है, उसका पांच प्रतिशत भी उसे वापस नहीं कर पाए हैं।

हम अपने काम का तो नफा-नुकसान जांचते हैं, पर धरती के पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब-किताब में फेल हैं। प्रकृति के पास कई तरीके हैं कि वह हमें रास्ते पर लाए। कुछ भी अप्रत्याशित रूप में प्रकट होगा, जो हमसे कुछ न कुछ छीन लेगा। कोविड की मार तो याद होगी ही, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। वह प्रकृति कहर ही था, जिसने हमें बताया था कि हमें समय रहते अपनी सीमाएं तय कर लेनी चाहिए। प्रकृति हमारी मनमानी ज्यादा सहन नहीं करेगी। हम सुनार की तरह ही गए हैं, जो जीवन की चमक-दमक देखते हैं, जबकि प्रकृति लोहार की तरह है, जो तप-खप कर बनी है। यह कहावत तो हमें पता ही होगी कि सौ सुनार की और एक लोहार की। मतलब टुकड़ों-टुकड़ों में हमारी चोटों के बदले लोहार की एक ही चोट हमें नेस्तनाबूद करने के लिए काफी होगी।

(लेखक पर्यावरणविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संकट से कैसे उबरें

समय एक-सा नहीं रहता। छोटी-बड़ी कठिनाइयां और चुनौतियां आती-जाती रहेंगी, सफलता का मार्ग इन्हीं से जूझ कर मिलता है। सुदूर गंतव्य का राही संकट की शिकायत नहीं करता। प्रतिकूल परिस्थितियों में दो विकल्प रहते हैं- घुटने टेक दें या उसका सामना करें। घुटने टेकना सरल है। औसत सोच वाला यही करता है। फिर वह अपनी दुर्दशा हर किसी को बांचता, भाग्य को कोसता है। दूसरी ओर, स्वयं की अथाह शक्ति के प्रति आश्वस्त व्यक्ति विकट परिस्थिति से कतराता नहीं, बल्कि उससे भिड़ता और विजयी हो कर यश का भागी बनता है। अपनी व्यथा दूसरों से साझा करना स्वीकारोक्ति है कि संबद्ध व्यक्ति को कुछ नहीं सूझ रहा और उसे सहानुभूति चाहिए। अपनी चिंताएं एवं सरोकार दूसरों पर डालता व्यक्ति घर-परिवार और समाज पर बोझ होता है। अधिसंख्य जन उससे दूरी बना लेते हैं। समाज और राष्ट्र निर्माण में हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए, जो दूसरों को सशक्त बनाएं, वे नहीं जो स्वयं पर बोझ हों।

जीवन का भरपूर आनंद वे लोग उठाते हैं, जो संकट के क्षणों में शिकायती मुद्रा में ढल जाने की अपेक्षा अपने मन का दीप प्रज्वलित करते हैं। संकट जितना गहरा होता है उसी अनुपात में अंतर्निहित दीप को प्रकाशवान करना होता है। फिर एक नवनिर्मित आभा सभी दिशाओं से अनुकूल शक्तियों को आकृष्ट करती है। तब अप्रत्याशित स्रोतों से सहायतार्थ प्रकट हुए अनेक हाथ पूछने लगते हैं कि "तुम्हें क्या चाहिए?" मनुष्य प्रेम, सौंदर्य और प्रकाश की ओर आकृष्ट होता है। दूसरों पर सवार रहने का अवसर तलाशने वाले का दीप नहीं जलता। विपन्नता और नैराश्य के दौर में मुख मुद्रा को प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त रखने के अभ्यस्त हो जाएंगे तो राह अवश्य मिलेगी। जिसने कालचक्र के थपेड़े सहे, उनसे सीखा और स्वयं को तराशा, उसी ने बुलंदियां छुईं। अतः प्रत्येक समस्या को उपहार मानें।

हरीश बड़थ्वाल

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

एनटीए और पेपर लीक

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए परीक्षा कराने के लिए एनटीए का गठन हुआ था, लेकिन यह संस्थान आज पेपर लीक कराने के मामले में सुर्खियां बटोर रहा है। 'एक और परीक्षा से खिलवाड़' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में उचित ही कहा गया है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा इतना संवेदनशील कार्य ठेके पर क्यों कराया जाता है? वह भी ऐसे लोगों को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाता है जिन्हें इसका कोई अनुभव नहीं होता। नेताओं के लिए ड्राइवर से लेकर खाना बनाने वाले तक सबके सब कर्मचारी अनुभवी रखे जाते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। बस, ट्रेन आदि से सफर करने के लिए जनता पैसे देकर टिकट लेती है और यदि कोई बिना टिकट के सफर करता पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगता है। यदि कोई कोर्ट का कीमती समय नष्ट करता है तो उस पर भी जुर्माना लगता है। ऐसे ही जब इतनी बड़ी सरकारी संस्था लाखों अभ्यर्थियों के समय, संसाधन और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो प्रशासन चुप क्यों है? वह भी तब जब इससे जुड़े तमाम सुबूत सामने आ रहे हैं। क्या अभ्यर्थियों का समय कीमती नहीं है? सब नियम-कानून क्या सिर्फ जनता के लिए हैं? नीट-यूजी, नेट, यूपी पुलिस भर्ती, आरओ/एआरओ आदि कितनी ही परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, पर जितनी तेजी से पेपर लीक हो रहे हैं उतनी तेजी से अभ्यर्थियों को न तो इंसाफ मिल रहा है और न ही अपने भविष्य के लिए कोई उचित राह। ऐसे में छात्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं से भरोसा उठना जायज है। जब देश का पढ़ा-लिखा युवावर्ग इस प्रकार की मानसिक पीड़ा से गुजरेगा तो देश का विकास कैसे होगा? यह अत्यंत ही गंभीर विषय है।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

पेपर लीक रोकना बड़ी चुनौती

21 जून को प्रकाशित संपादकीय आलेख एक और परीक्षा से खिलवाड़ पढ़ा । अभी नीट परीक्षा में अनियमितता की जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि यूजीसी नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद उसे रद कर दिया गया और इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है । प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करना एक उद्योग- धंधा का रूप ले चुका है, क्योंकि कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है । यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है । इस तरह की घटनाओं सें छात्रों का शारीरिक आर्थिक और मानसिक शोषण होता है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल करना हर विद्यार्थी का सपना होता है, लेकिन सरकारों की कुव्यवस्था की वजह से विद्यार्थियों का सपना साकार होने से पहले ही चकनाचूर हो जा रहा है। हर बार सरकार द्वारा जांच का आदेश दिया जाता है, लेकिन समस्या बदस्तूर जारी है। इस घृणित एवं असंवैधानिक कार्य में अधिक मुनाफा होने की वजह से आसानी से प्रभावशाली लोगों का संरक्षण भी हासिल हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकना एवं प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या को समाप्त करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। देश के प्रतिभावान युवाओं के भविष्य की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया।

योग पर्यटन का दौर

जब योग स्वाभाविक रूप से जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो इसका हर पल लाभ होता है। योग जब जीवन से जुड़ता है तो एक सहज क्रिया बन जाती है। योग से लोगों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। ध्यान हमारे एकाग्रता से जुड़ा विषय है। कम से कम थकान से अधिक से अधिक संतोष मिलता है। व्यक्तिगत जीवन को प्रशिक्षित करने के लिए योग है। योग आपकी विकास यात्रा का मजबूत पहलू बन जाएगा। योग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। दुनिया के नेता अब योग पर बात कर रहे हैं। योग पर अब रिसर्च हो रहे हैं। योग पर्यटन का नया चलन चला है। ऋषिकेश और काशी से लेकर केरल तक, भारत में योग टूरिज्म का एक नया दौर उभरते हुए देखा जा सकता है। प्रामाणिक योग सीखने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आ रहे हैं। आतिथ्य और पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में योग से जुड़ी समर्पित सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। आज दुनियाभर में 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार योग दिवस का थीम 'योग स्वयं और समाज के लिए' रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में योग दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए दुनिया भर के लोगों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और कहा कि दुनिया में योग करने वालों की तादात बढ़ रही है। विश्व के कई देशों में योग दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। सऊदी में तो योग शिक्षा में ही शामिल है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार।

X पोस्ट

आरक्षण उनका बंद होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से दबे हुए, शैक्षणिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को मिलना चाहिए, ताकि कमजोर वर्गों को मजबूत होने का मौका मिल सके। देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए।

अरुण राजभर@ArunrajbharSbsp

जब समस्या दिल्ली जल बोर्ड में है, तब टैंकर माफिया को नियंत्रित करने के बजाय आतिशी अनशन क्यों कर रही हैं। इससे क्या होगा? निधि बहुगुणा@vinirish

'चुनाव से पहले अगर कोई उन्हें मारना चाहता था तो उसे डर रहता था, अब वह डर खत्म हो गया है।' राहुल गांधी का यह बयान सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। वह गांधी परिवार, जो इस बार चुनाव प्रचार में अपने परिवार की शहादत याद कर रहा था, उसके शीर्ष नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसा बोल रहे हैं। रोमाना ईसार खान@romanaisarkhan

जब दक्षिण कोरिया और जापान अमेरिका के रास्ते यूक्रेन को हथियार देने पर सहमत हुए थे, तभी यह लगने लगा था कि रूस कुछ करेगा। अब व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ रक्षा समझौता कर उसे हथियार देने की बात कह दी। ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

जनपथ

गलती दिखी न देश में दलबदलू की दाल,
बदल-बदल कर पार्टी जो खाते हैं माल।
जो खाते हैं माल न कोई विचारधारा,
जहां टिकट मिल जाय वहीं जाकर मुंह मारा।
जो रहते प्रतिबद्ध उन्हें ही दुनिया छलती,
पर भारी इस बार पड़ गई ये ही गलती!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 71

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी सभी तरह की राजनीति की तरह सत्ता के लिए संघर्ष है। -हैंस जे मॉर्गेंथाउ

हेनले ऐंड पार्टनर्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, करोड़पतियों के पलायन के मामले में चीन और यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत बेशक तीसरे स्थान पर आता हो, लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि पिछले तीन साल में भारत में यह संख्या घटी है और नए करोड़पतियों की संख्या तेजी से बढ़ी भी है।

क्यों जाते हैं करोड़पति

अंतरराष्ट्रीय फर्म हेनले ऐंड पार्टनर्स की ताजा रिपोर्ट का यह अनुमान एकबारगी चिंतित तो करता है कि इस वर्ष चार हजार से ज्यादा करोड़पति देश छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है, जो आश्वस्त करता है। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में दौलतमंदों के पलायन के मामले में चीन और यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत तीसरे पायदान पर आता है। लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि जहां पूरी दुनिया में अपना मुल्क छोड़कर पलायन करने वाले धनी लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं भारत में यह संख्या पिछले तीन साल से लगातार कम हो रही है। हालांकि यह सच है कि अगर धनी लोग इतनी बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हों, तो किसी भी देश के लिए इसे अमूमन अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जैसा रिपोर्ट बताती है, इस मामले में भारत की स्थिति कुछ अलग है। भारत से पलायन करने वाले ज्यादातर लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए अपनी कुछ संपत्ति वगैरह भारत में भी रखते हैं। जाहिर है कि हेनली ऐंड पार्टनर्स की रिपोर्ट देश से दौलतमंदों के पलायन को लेकर सोचने का एक नया नजरिया देती है। भारतीय करोड़पति विदेश में व्यवसाय शुरू करते हैं, सफल होते हैं, तो इससे भारत की प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, चूंकि वे भारत में निवेश भी करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचता है। इसके अतिरिक्त, वे वहां के समाज में अपनी संस्कृति और मूल्यों का प्रचार भी करते हैं, जिससे कुल मिलाकर भारत की छवि ही मजबूत होती है और उसे एक सॉफ्ट पावर बनने में भी मदद मिलती है। एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर करोड़पति भारत से पलायन कर रहे हैं, तो उतनी या उससे तेज गति से नए करोड़पति पैदा भी हो रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में एक करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देश में आयकर रिटर्न भरने वालों

की संख्या में हो रही निरंतर वृद्धि से इसी तथ्य की पुष्टि होती है। हेनले की रिपोर्ट के अनुसार भी पिछले दस वर्षों में भारत में करोड़पतियों की संख्या में 85 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल, लोग बेहतर जीवन-शैली, व्यवसाय के लिए अनुकूल अवसर, करों में लाभ और बच्चों की शिक्षा में संभावनाएं व स्वास्थ्य देखभाल की सहूलियतों की वजह से सुविधाओं से संपन्न अमीर देशों का रुख करते हैं। ऐसे में, अगर पिछली बार की तरह इस वर्ष भी दुनिया भर के सबसे ज्यादा करोड़पति संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में बसना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह समझी जा सकती है।

आखिर त्रूदो की समस्या क्या है?

इटली में संपन्न जी-7 देशों के सम्मेलन में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो एक ओर तो भारत और कनाडा के बीच के मुद्दों को आपसी सद्भाव के साथ हल करने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर कनाडा की संसद में भारत द्वारा आतंकवादी घोषित निज्जर की हत्या की बरसी पर उसे श्रद्धांजलि दी जाती है।

इन दिनों भारत और कनाडा के संबंध काफी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। ताजा मामला कनाडाई संसद द्वारा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बरसी पर एक मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि देने का है। भारत ने जिस निज्जर को 2020 में आतंकवादी घोषित कर दिया था, उसकी पिछले साल 18 जून को कुछ अज्ञात लोगों ने कनाडा के वैंकूवर शहर के सिख इलाके के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो ने इस हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया था, लेकिन उसी वक्त से दोनों देशों के संबंधों में कटुता का समावेश हो गया।

रवींद्र दुबे
वरिष्ठ पत्रकार

विगत 18 जून को सिख प्रदर्शनकारियों ने निज्जर की हत्या की बरसी कनाडा स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खून का प्रतीकात्मक मुकदमा चला कर मनाई। होव स्ट्रीट के एक ब्लॉक पर हुए इस मुकदमे में अभिनेताओं द्वारा बनाई गई एक फर्जी जूरी और सफेद घुंघराले विग में एक जज भी सम्मिलित था, जिसने 'अभियोजक' को पिछले साल सरी में हुई इस हत्या में मोदी की संलिप्तता के सबूत पेश करने के लिए आमंत्रित किया था। इस मुकदमे की शुरुआत से पहले एक पिंजरे में जेल की धारियों वाली पोशाक में मोदी के पुतले का जुलूस भी निकाला गया।

इससे पहले, 11 जून को टोरंटो के ब्राम्पटन इलाके में ऑपरेशन ब्लू स्टार की चालीसवीं बरसी पर इंदिरा गांधी हत्याकांड की एक झांकी भी निकाली गई थी। इस साल कनाडा में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के बाहर भी कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने भारतीय झंडे जलाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट को पैरों से रौंदा और उस पर थूका। दरअसल इस साल कनाडा स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के सामने इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और पिछले साल

से लेकर अब तक तो कुछ ज्यादा ही। भारत और विदेश में खालिस्तान आंदोलन को लेकर तनाव का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कनाडा को एक ऐसे देश के रूप में देखा जाता है, जहां आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत है, और इसलिए, भारत में इसकी तीखी आलोचना हुई है, खासकर त्रूदो के आरोपों के मद्देनजर कि भारत निज्जर की हत्या में शामिल है।

वर्ष 2012 में भारत के विदेश मंत्री ने देश की छह दिवसीय यात्रा पर आए, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के समक्ष 'कनाडा में भारत विरोधी बयानबाजी को फिर से शुरू करने' का मुद्दा उठाया था। हार्पर ने कहा था कि कनाडा एकजुट भारत का समर्थक है, लेकिन उन्होंने खालिस्तान के समर्थन में शांतिपूर्ण बातचीत को चुप कराने से इन्कार कर दिया था। हार्पर ने कहा, 'हम अभिव्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।' त्रूदो से जब पिछले सितंबर में नई दिल्ली में जी-20 सम्मेलन के दौरान कनाडा में सिख खालिस्तानी आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने भी हार्पर की प्रतिक्रिया का समर्थन किया।

भारत के बाहर कनाडा में सिखों की सबसे बड़ी आबादी है, जहां उनकी संख्या लगभग 7,70,000 है, जो उस देश की आबादी का लगभग 2.1 प्रतिशत है। अन्य देशों में सिखों की आबादी एक प्रतिशत से भी कम है। गौरतलब है कि कनाडा की राजनीति में भी सिखों की सक्रियता अच्छी-खासी है और उन्होंने अपने मकसद तक पहुंचने में राष्ट्रीय राजनीतिक मंच का जबर्दस्त उपयोग किया है। इनमें से कुछ ऐसे भी कारण हैं, जिन्हें भारत अपने हितों के खिलाफ मानता है। उदाहरण के लिए, संघीय नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह, जो सिख हैं, ने ओंटारियो में एक सांसद के रूप में अपने शुरुआती राजनीतिक कॅरिअर का अधिकांश समय भारत के 1984 के सिख विरोधी दंगों को नरसंहार के रूप में मान्यता दिलाने के लिए पैरवी करने में बिताया। 1984 के दंगों को नरसंहार के रूप में निंदा करने वाला एक प्रस्ताव 2017 में ओंटारियो में पारित किया गया था। वर्ष 2018 में सिंह, जो तब तक संघीय एनडीपी नेता बन गए थे, ने कहा कि संघीय स्तर पर भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि कनाडा सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया है।

जगमीत सिंह की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी कनाडाई संसद में चौथे नंबर की पार्टी है। इसके अलावा, इस पार्टी के राजनीतिक प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश कोलंबिया और मनिटोबा जैसे प्रांतों में उसकी सरकार है और अलबर्टा, सस्काच्वान और ओंटारियो में वह प्रमुख विपक्षी पार्टी है और क्यूबेक, न्यू ब्रनस्विक और प्रिंस एडवर्ड आईलैंड को छोड़कर कई प्रांतों की विधायिका में उसके सदस्य हैं। पिछले दिनों ही इटली में संपन्न जी-7 देशों के सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन त्रूदो की एक अनौपचारिक मुलाकात हुई थी, जिसमें आपसी सद्भाव और सहयोग से दोनों देशों के बीच सामान्य मुद्दों को हल करने के प्रयासों की दुहाई दी गई थी। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें भारतीय और कनाडाई मीडिया में छाई हुई थीं। इस मुलाकात की अल्पावधि में ही ये सब घटनाएं हो गईं।

बहरहाल, कनाडाई संसद द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बरसी पर उसके सम्मान में एक मिनट का मौन रखने से आहत भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने कनाडा के वैंकूवर में 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 (कनिष्क) बम विस्फोट के पीड़ितों के लिए एक स्मारक सेवा का आयोजन किया है। 23 जून, 1985 को कनाडा से लंदन होते हुए भारत आने वाले एयर इंडिया के विमान में आयरिश तट पर विस्फोट हो गया, जिसमें 86 बच्चों सहित सभी 329 लोग मारे गए थे। कनाडा की धरती पर यह सबसे बड़ी आतंकवादी घटना थी। यह स्मारक सेवा 23 जून, 2024 को शाम स्टेनली पार्क के सेपरले खेल के मैदान क्षेत्र में एयर इंडिया मेमोरियल में निर्धारित की गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कनाडा इस घटना को किस तरह से लेता है।

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

परमहंस योगानंद

जब आप अच्छे कार्य करने का निश्चय कर लेते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही अपने कार्य में सफल होंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों।

'नहीं कर सकता' का भाव सफलता में बाधक

सफलता कोई साधारण बात नहीं है। सफलता का अर्थ आपके पास मौजूद धन और भौतिक संपदा से कहीं अधिक गहन है। सफलता को केवल आपकी आंतरिक शांति और मानसिक नियंत्रण की उस मात्रा से आंका जा सकता है, जो आपको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के योग्य बनाती है। सच्ची सफलता का पैमाना यही है। सफलता और सुख का रहस्य आपके ही भीतर है। यदि आपने बाहरी सफलता प्राप्त की है, लेकिन भीतर से खुश नहीं हैं, तो वास्तव में आप सफल इन्सान नहीं हैं। एक करोड़पति व्यक्ति जो सुखी नहीं है, वह सही मायने में सफल नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि यदि आपके पास करोड़ों रुपये हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। चाहे आप गरीब हों अथवा अमीर, यदि आप जीवन में सुखी हैं, तो आप वास्तव में सफल हैं।

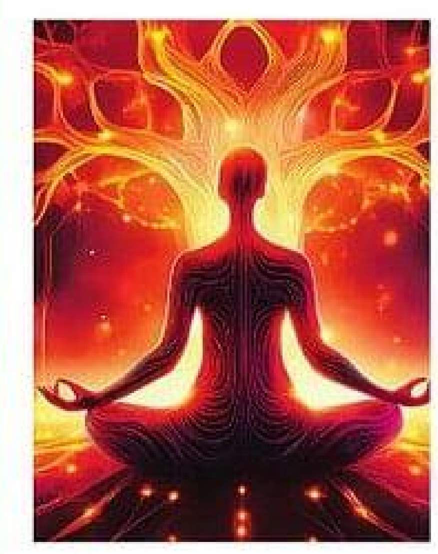

नश्वर प्राणी के रूप में तो आप सीमित हैं, परंतु ईश्वर की संतान के रूप में आप असीम हैं। अपनी एकाग्रता को ईश्वर पर केंद्रित करें। इस एकाग्रता से आप वह संपूर्ण शक्ति अर्जित कर लेंगे, जिसे आप किसी भी कार्य में प्रयोग करना चाहते हैं। इच्छाशक्ति आपके भीतर ईश्वर के प्रतिबिंब का माध्यम है। इच्छाशक्ति में प्रकृति की सारी शक्तियों को नियंत्रित करने वाली ईश्वर की असीम शक्ति निहित होती है।

आप ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में बनाए गए हैं, इसलिए वह शक्ति आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए है। जब आप अच्छे कार्य करने का निश्चय कर लेते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही अपने कार्य में सफल होंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। यदि आप प्रयत्न करते रहेंगे, तो ईश्वर ऐसा साधन बना देंगे, जिसके द्वारा आपकी इच्छाशक्ति को उसका उचित फल मिल ही जाएगा। यही वह सत्य है, जिसका जीसस ने उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि 'यदि तुम विश्वास करो, और कोई शंका न करो, तो यदि तुम इस पर्वत को कहोगे, यहां से हट जाओ और सागर में गिर जाओ, तो ऐसा ही हो जाएगा।' सांसारिक व्यक्ति का दिमाग 'यह मैं नहीं कर सकता' से ही भरा रहता है। कुछ विशेष गुणों और आदतों वाले परिवार में जन्म लेने के कारण वह इनसे प्रभावित होकर सोचने लगता है कि वह कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। जैसे-वह ज्यादा चल नहीं सकता, वह अमुक चीज खा नहीं सकता, वह उसको सहन नहीं कर सकता।

जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है उन सभी 'नहीं कर सकता' के भावों को खत्म करना। आप जो कुछ भी करना चाहें, उसे कर पाने की शक्ति आपके भीतर है। यदि आप सक्रिय इच्छाशक्ति के साथ किसी विचार को पकड़े रखते हैं, तो यह अंततः साकार रूप धारण कर ही लेता है।

इच्छाशक्ति का प्रयोग

सूत्र

आप इच्छाशक्ति के विकास के ऐसे लक्ष्य को चुनें, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप उसे हासिल नहीं कर सकते। फिर अपनी पूरी ताकत से उसी एक कार्य को करने में जुट जाएं। जब आपको सफलता मिल जाए, तो और बड़े कार्य को हाथ में लें और इसी प्रकार अपनी इच्छाशक्ति के अभ्यास को जारी रखें। आपको अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी हों, या आप कोई भी हों।

दूसरा पहलू

विकास पृथ्वी तक सीमित नहीं, जैसा डार्विन का सिद्धांत दावा करता है। नए शोध की मानें, तो पूरा ब्रह्मांड हर क्षण बदल रहा है।

ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं

हम कौन हैं और अन्य प्रजातियां क्या हैं, यह प्राकृतिक चयन का परिणाम है, जैसा कि डार्विन का सिद्धांत दावा करता है। डार्विन का सिद्धांत इस तथ्य तक सीमित है कि इसमें केवल जीवन को प्रभावित करने वाले भूलोक के कारकों को ही ध्यान में रखा गया है। लेकिन विकास केवल पृथ्वी की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। यह अलौकिक पिंडों में भी मौजूद है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा पदार्थ और संरचनात्मक घटक क्रमिक और प्रासंगिक परिवर्तनों से गुजर रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन के साथ-साथ नए ग्रहों, नए सितारों, नई आकाशगंगाओं में भी विकास की हलचल हो रही है। यह सिर्फ जैविक विकास नहीं है, जो पृथ्वी पर सहस्राब्दियों से हो रहा है। एक खगोल-जैविक विकास की भी सुगबुगाहट है, जो कॉस्मिक टाइम स्केल या कॉस्मिक स्टैंडर्ड टाइम (सीएसटी) की लय के साथ ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में अन्य खगोलीय पिंडों-ग्रहों और चंद्रमाओं पर खिलेगा।

पुष्पा धामी

खगोल-जैविक विकास का नया सिद्धांत *फर्टिलाइजिंग द यूनिवर्सः ए न्यू चैप्टर ऑफ अनफोल्डिंग इवोल्यूशन* ब्रिटेन के कैंब्रिज स्कॉलर्स ने प्रकाशित किया है।

खगोल-जैविक विकास का नया आकर्षक और दिमाग चकराने वाला सिद्धांत *फर्टिलाइजिंग द यूनिवर्स : ए न्यू चैप्टर ऑफ अनफोल्डिंग इवोल्यूशन* ब्रिटेन के कैंब्रिज स्कॉलर्स ने प्रकाशित किया है। इस अद्भुत सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले लेखक डॉ. वीर सिंह उत्तराखंड में पंतनगर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। प्रो. वीर सिंह कहते हैं, 'विकास मूलतः ब्रह्मांडीय प्रकृति का है। डार्विन का जैविक विकास का बहुप्रशंसित सिद्धांत पृथ्वी को ब्रह्मांड से काट कर देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। मानो जीवन स्वयं एकमात्र पृथ्वी की ही देन है, ब्रह्मांड की नहीं!' 'ब्रह्मांड का निषेचन' में उनका सिद्धांत तीन सर्वव्यापी कारकों के इर्द-गिर्द घूमता है। ये हैं : प्रकाश, विकास और समय या काल। इन तीनों सर्वव्यापी कारकों का निश्चित प्रभाव संयुक्त होता है। प्रकाश विश्व की सारी ऊर्जाओं का मूल स्रोत है। ऊर्जा ही विकास को जन्म देती है। विकास, अर्थात परिवर्तन। समय का सर्वव्यापी अस्तित्व ब्रह्मांड का एक सत्य है। विकास समय के रथ पर सवार होकर चलता है, इसलिए उसकी अपनी एक लय है। इस सिद्धांत में वीर सिंह लिखते हैं कि प्रकाश, विकास और काल सनातन मान्यताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में हैं। प्रकाश अस्तित्व की कहानी लिखता है, विकास उसे आकार-प्रकार देता है और काल सबको अपने चक्र में बांधता है। उनका तर्क है, 'जैसा कि डार्विन ने करने का प्रयास किया था, विकास को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह अपने आप में समग्र है। यह सर्वव्यापी है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है।'

सिद्धांत के प्रतिपादक हैं उत्तराखंड में पंतनगर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग में प्रोफेसर एमेरिटस प्रो. वीर सिंह। उनका सिद्धांत तीन सर्वव्यापी कारकों के इर्द-गिर्द घूमता है। ये हैं : प्रकाश, विकास और समय या काल।

आंकड़े

यूनिकॉर्न स्टार्टअप

देश में एक अरब डॉलर से अधिक बाजार पूंजी वाले यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, जो बेहतर अर्थव्यवस्था का संकेत है।

स्रोत : FinLib

पूजन के लिए कुश लाते वक्त भक्त मंकणक की उंगली से खून निकलने पर वह इतने नाचे कि उन्हें रुकवाने के लिए स्वयं भगवान शंकर को आना पड़ा।

मंकणक संग नाचा सारा संसार

अंतर्यात्रा
संकलित

सरस्वती नदी के किनारे तपस्वी ब्राह्मण मंकणक रहते थे। एक दिन वह पूजा के लिए कुश लेकर आए, लेकिन कुश की नोक उनके हाथ में गड़ गई। उनके हाथों से खून बहने लगा। उसे देखकर मंकणक काफी खुश हुए। वह हर्ष के आवेश में आकर नाचने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से संसार के सभी प्राणी उनके नृत्य की गति में अपनी गति मिलाकर नृत्य करने लगे।

जब सभी नृत्य करने लगे, तो इंद्र और ऋषियों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कोई उपाय बताइए, जिससे इनका नृत्य बंद हो जाए। ब्रह्मा ने रुद्रदेव से कहा कि मंकणक आपके परमभक्त हैं। आप ही मनाइए। ब्रह्मा की बात मानकर महादेव मंकणक के पास गए और पूछा नृत्य क्यों कर रहे हो? मंकणक ने देखे बिना कहा, क्या आप देख नहीं रहे मेरे हाथ से खून निकल रहा है? इसलिए हर्ष से नाच रहा हूं। महादेव ने कहा, तुम मेरी ओर तो देखो। मंकणक ने सोचा, ये कौन हैं, जो मुझे नाचने से रोक रहे हैं। उस वक्त महादेव ने अपने अंगूठे को दबा रखा था। मंकणक ने देखा कि उनके हाथ से श्वेतवर्ण की भस्म निकल रही थी। मंकणक लज्जित होकर महादेव के चरणों में गिर गए और क्षमा-याचना की। बोले-प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया। भगवान शंकर बोले-इसमें अपराध की क्या बात है? भक्त के नृत्य बंद करने पर महादेव ने वरदान दिया कि आज से मैं तुम्हारे साथ यहां सरस्वती नदी के किनारे सदैव निवास करूंगा।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 31 दिसंबर, 1950

काठमांडू में प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार

६ व्यक्ति शहीद होगये
प्रदर्शनकारियों व पुलिस की झड़पें
हिन्दू महासभा को संदेश राष्ट्रपति ने नहीं, राष्ट्रपति के कार्यालय भेजा

नेपाल की राजधानी काठमांडू में कल राणा शाही की पुलिस और फौजियों ने 30 हजार से भी अधिक प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बौछार की, जिसके फलस्वरूप छह व्यक्तियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।

'करीबी मित्र' को करीब रखने की चुनौती

भारत का दूसरा दौरा कर शेख हसीना ने संदेश दे दिया है। देखना यह है कि भारत राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बगैर बांग्लादेश को क्या दे सकता है।

महेंद्र वेद — विदेश नीति

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पंद्रह दिनों के भीतर दूसरी बार भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। पर यह इस पर भी निर्भर करता है कि भारत बांग्लादेश को क्या दे सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और हसीना, दोनों दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जटिल राजनीतिक व भू-राजनीतिक गतिशीलता से वाकिफ हैं, जिसमें क्वाड चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन को अलग-थलग करने के लिए भारत ऐसे प्रस्ताव देगा, जिन्हें वह आसानी से मना नहीं कर पाएंगी। इससे हसीना को अगले महीने चीनियों से बातचीत में भी कुछ लाभ मिलेगा।

शेख हसीना ने चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास स्थगित कर दिया है। भारत रक्षा पर 50 करोड़ डॉलर की क्रेडिट लाइन का शीघ्र कार्यान्वयन चाहता है। हसीना ने तीस्ता नदी के विकास में वित्त पोषण और

भागीदारी के चीन के प्रस्ताव को भी टाल दिया। समझौते के अनुसार, इसके पानी के समान बंटवारे की बांग्लादेश की पुरानी मांग है। लेकिन भारत इसे पूरा करने में असमर्थ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल इससे सहमत नहीं है। इस बार भी समझौते की संभावना नहीं दिखती है। वर्ष 2026 में गंगा जल संधि खत्म हो जाएगी, जिसे परस्पर संतुष्टि के लिए फिर से नवीनीकृत किया जाना चाहिए। यदि भारत इसमें चूक जाता है, तो चीन को बांग्लादेश को अपने पाले में लाने की कोशिश करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए भारत को अपने 'सबसे करीबी' और 'मित्रवत' पड़ोसी की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश, दोनों के पास दीर्घकालिक दृष्टिकोण हैं, जिसे पूरा करने के लिए सहयोग की जरूरत है। भारत 2047 तक 'विकसित' राष्ट्र बनना चाहता है और बांग्लादेश, 'स्मार्ट' राष्ट्र। आर्थिक विकास व सामाजिक सामंजस्य दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। मनुष्यों (कथित अपराधियों समेत), मवेशियों, हथियारों और नशीले पदार्थों की सीमा पार अवैध आवाजाही पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

बांग्लादेश को भारत से ऋण की उम्मीद है। इसके लिए वह चीन से भी संपर्क करेगा। हालांकि हसीना की इस यात्रा के दौरान किसी नए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है, पर ऐसी घोषणा संयुक्त विज्ञप्ति में की जा सकती है। भारत परस्पर लाभ के लिए निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते का तेजी से क्रियान्वयन चाहता है।

वर्ष 2010 से भारत ने बांग्लादेश को 7.36 अरब डॉलर का ऋण देने का वादा किया है। बांग्लादेश इस साल अप्रैल तक केवल 1.73 अरब डॉलर या वादे का 23 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया है। मौजूदा भारतीय क्रेडिट लाइन की शर्तें बहुत सख्त हैं। जैसे, हर परियोजना के लिए लगभग 65-75 प्रतिशत सामान या सेवाएं भारत से खरीदी जानी चाहिए, जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। हसीना ने सोनादिया बंदरगाह को विकसित करने के चीनी प्रस्ताव पर कहा कि उसे उम्मीद है कि भारत इसकी भरपाई करेगा। भारत एक नई द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक है, और मोंगला समुद्री बंदरगाह में व्यापक भूमिका निभाना रहा है। हिंद-प्रशांत तक विस्तारित एक नया समुद्री मार्ग भी एजेंडे में है।

इसके अतिरिक्त, भारत का लक्ष्य समुद्री सहयोग को बढ़ाते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में 'सागर' परियोजना का विस्तार करना है। बांग्लादेश का लक्ष्य भूटान से अधिक जलविद्युत आयात करना है, जिसके लिए भारत की सहमति की आवश्यकता है। उम्मीद है कि भारत भूटान से बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने के लिए अपने क्षेत्र के इस्तेमाल पर सहमत हो सकता है।

दोनों देशों के बीच सार्वजनिक परिवहन के लिए फेनी मोइत्री (मैत्री) पुल का जल्द उद्घाटन करने और रामपाल मोइत्री बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई खोलने के लिए चर्चा चल रही है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों परियोजनाओं को प्रतीकात्मक रूप से खोले जाने की उम्मीद है। दक्षिण त्रिपुरा जिले में भारत-बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु के माध्यम से यात्री आवागमन इस साल सितंबर तक शुरू होने वाला है। इसमें शामिल जटिलताओं को देखते हुए शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया है। उस यात्रा के दौरान इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जाहिर है, दोनों पड़ोसियों को मिलकर काम करना चाहिए, चाहे चीन का प्रभाव हो या न हो।

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 22 जून, 2024

कल्पमेधा

जो व्यक्ति काम के तरीके या उसके सिद्धांत को समझे बिना अभ्यास करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है, जिसे मालूम नहीं होता कि जाना किस दिशा में है।
– लिओनार्दो दा विंची

विरासत की गरिमा

हमारे देश में वैसी उपलब्धियों और धरोहरों की एक लंबी शृंखला है, जिनकी वजह से दुनिया भर में भारतीयता को एक सम्मान की नजर से देखा जाता है। मगर हाल के वर्षों में योग एक ऐसे पहलू के रूप में उभरा है, जिसे न केवल भारत में एक नया आयाम मिला है, बल्कि इसे विश्व भर में लोगों ने बेहद रुचि के साथ देखा, सीखा और अपनाया। सच यह है कि एक ऐतिहासिक धरोहर और नायाब तोहफे के रूप में योग के सहारे स्वास्थ्य का कायाकल्प करने के लिए एक दृष्टि देने के लिहाज से भारत को दुनिया भर में नेतृत्व करने का मौका मिला है। यह बेवजह नहीं है कि आज भारत सहित दुनिया के कई देशों, बड़े-बड़े संस्थानों और विश्वविद्यालयों तक में व्यापक पैमाने पर लोगों के बीच योगासन बेहद लोकप्रिय हुआ है और इसके प्रत्यक्ष लाभ भी देखे जा रहे हैं। इसलिए योग और इसके दर्शन के महत्त्व को समझा जा सकता है। मगर दूसरे पहलू से देखें तो यह अफसोस की बात है कि 'योग दिवस' के रूप में इसे वर्ष में सिर्फ एक दिन के उत्सव की तरह देखा जाने लगा है। जबकि रोजमर्रा के जीवन में नियमित अभ्यास के रूप में ही इसकी अहमियत आंकी जा सकती है।

दरअसल, वैश्विक स्तर पर योग की लोकप्रियता के समांतर यह भी देखा जा रहा है कि एक ओर बहुत सारे देशों में लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और इसकी उपयोगिता के लिहाज से इसे अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने देश में कई बार इसे एक मौके को भुनाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसका एक नकारात्मक पहलू इस रूप में सामने आया है कि दिनचर्या के हिस्से के रूप में उपयोगी माने जाने वाले योग को मुख्यधारा के प्रचार माध्यमों में अब 'योग-दिवस' में केंद्रित करके देखा जाने लगा है। इस मौके पर खासतौर पर टीवी चैनलों पर जिस तरह के कार्यक्रम पेश किए जाने लगते हैं, प्रस्तुतियों में जैसी हरकतें दिखती हैं, एक विचित्र चकाचौंध दिखता है, उससे योग जैसे गंभीर और महत्त्वपूर्ण विषय की गरिमा कम होती है।

करीब दस वर्ष पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का एक प्रस्ताव रखा था, तब उसे बहुत सारे देशों का समर्थन मिला और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसे मंजूरी दी थी। आज समूची दुनिया भारत के इस मंत्र को मान रही है कि स्वस्थ रहने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं। भारत सहित विश्व भर में जहां भी यह लोकप्रिय हुआ, वहां लोगों ने इसके महत्त्व को समझते हुए स्वतः स्फूर्त तरीके से इसे अपनाया। योग के मूल दर्शन और इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे इसी रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपने भीतर की प्रेरणा से इसे अपनाएं। मगर विडंबना यह है कि विश्व के अनेक देशों में जहां योग को स्वस्थ रहने के लिए एक तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है, वहां हमारे देश में इसे अपने-अपने विज्ञापन और प्रचार का जरिया भी बनाया जा रहा है। टीवी चैनलों पर योग के नाम पर पेश किए कार्यक्रमों का मकसद टीआरपी हासिल करना रह गया लगता है, जो शर्मनाक और चिंता का विषय है। इतिहासबोध के साथ देखें तो एक नायाब विरासत के रूप में योग की जो गरिमा रही है, उसके मद्देनजर इसे अपने प्रचार का जरिया बनने से बचाना होगा। मानव स्वास्थ्य के लिए योग का महत्त्व इसकी सादगी में रहा है और इसकी उपयोगिता को इसी रूप में स्थापित होना चाहिए।

अवैध की त्रासदी

किसी त्रासद घटना का सबक यह होना चाहिए कि उसमें हुई हानि को ध्यान में रख कर बाकी जगहों पर भी ऐसे उपाय किए जाएं जिससे वैसी घटनाओं से बचा जा सके। मगर विडंबना यह है कि ज्यादातर घटनाओं को स्थानीय समस्या मान कर दूसरी जगहों पर उसकी अनदेखी कर दी जाती है या फिर उसे महज एक खबर की तरह देखा जाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों से अक्सर जहरीली शराब का सेवन करने से लोगों के मरने की खबरें आती रहती हैं। मगर वैसी घटनाओं में कारणों और परिणाम को लेकर एक व्यापक चिंता ठोस शक्ल नहीं लेती। गौरतलब है कि तमिलनाडु के कल्लाकुरिचि जिले में अवैध देसी शराब पीने की वजह से कम से कम सैंतालीस लोगों की जान चली गई और अन्य तीस लोगों की हालत बेहद गंभीर हो गई। इस शराब के सेवन से एक सौ पैंसठ लोग बीमार हुए थे, जिन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यह अवैध तरीके से शराब बना कर लोगों को बेचने वाले की आपराधिक लापरवाही का नतीजा है, लेकिन जिस तमिलनाडु को कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर बेहतर स्थिति में माना जाता है, वहां पुलिस-प्रशासन की नाक के नीचे शराब के नाम पर जहर परोसने का गैरकानूनी कारोबार करने वालों को यह सुविधा कैसे मिली कि वे बेधड़क अपना धंधा चला रहे थे और उनके पास भारी संख्या में लोग शराब पीने पहुंचते थे।

जाहिर है, इतने सारे लोगों के मारे जाने के बाद अब सरकार और प्रशासन की ओर से एक औपचारिकता पूरी करने के लिए घटना की जांच, गहन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। सरकार ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। सरकार ने उस इलाके में प्रभावित लोगों की वास्तविक संख्या जानने के लिए घर-घर जाकर गणना करने की भी बात कही है। यह अपील की गई है कि जिन लोगों ने अवैध शराब का सेवन किया है, वे जल्द से जल्द जांच कराएं और जरूरी होने पर इलाज कराएं। इसे सरकार की संवेदनशीलता के तौर पर देखा जा सकता है। मगर यह समझना मुश्किल है कि सरकारी तंत्र की इस तरह की सक्रियता किसी त्रासद घटना के सामने आने और उसके तूल पकड़ लेने के बाद ही क्यों दिखाई देती है!

खुदरा बाजार में जादुई बदलाव

हमारे देश में 'क्विक ई-कामर्स बाजार' लगभग पांच अरब डालर का हो चुका है। यह कुल किराना बाजार का 45 फीसद है। अगले चार-पांच वर्षों में इसके 60 अरब डालर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

जयप्रकाश त्रिपाठी

हाल के वर्षों तक विच्छिन्न रहा भारत का किराना बाजार नए जमाने के ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से तेजी से बदल रहा है। यह वैश्विक माध्यमों तक अपनी सीधी पहुंच बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते किराना बाजारों में से एक है और अगले वर्ष तक आठ फीसद की विकास दर के साथ इसके 21 से 25 अरब डालर तक पहुंच जाने का अनुमान है। ई-किराना कंपनियां तेजी से उपभोक्ताओं की मांगें पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं, तो उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता, डिब्बाबंद वस्तुओं की मांग, ब्रांड सहमेल, उपभोक्ता मानसिकता में बदलाव आदि कारक भी इस क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हमारे देश में 'क्विक ई-कामर्स बाजार' लगभग पांच अरब डालर का हो चुका है। यह कुल किराना बाजार का 45 फीसद है। अगले चार-पांच वर्षों में इसके 60 अरब डालर तक पहुंच जाने का अनुमान है। मगर ग्राहकों की बदलती आदतों की मार छोटे दुकानदारों पर पड़ रही है। खुदरा सामान की मासिक बिक्री में 60 फीसद की गिरावट दर्ज हो रही है। कुछ वर्ष पहले तक आम धारणा थी कि आनलाइन सेवा झूठ से भरी है। मगर अब यह हकीकत में बदल चुकी है। हर हाथ में मोबाइल आ जाने के बाद से तो जैसे सब कुछ आनलाइन संभव हो चुका है। एक आकर्षक व्यावसायिक अवसर के रूप में इससे बढ़ती आबादी तक नाना प्रकार के उत्पादों की पहुंच आसान हो चुकी है।

बाल्टीमोर (अमेरिका) का रोलैंड पार्क बिजनेस ब्लाक 1907 में खुला और दुनिया के पहले शापिंग सेंटर के रूप में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज हो गया था। कालांतर में इसका एक योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकास और विस्तार होता गया। पश्चिमी जगत के युद्धोत्तर उपनगरीय मध्यवर्ग की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आउटडोर शापिंग सेंटरों की एक अलग तरह की श्रेणी ने भी करवट ली। समय के साथ छोटी खुदरा दुकानों के साथ 'डिपार्टमेंटल स्टोर' जोड़ने के क्रम में 1980-90 के दशक तक शापिंग माल संस्कृति में आपसी प्रतिस्पर्द्धा की गतिविधियां भी तेज होने लगी थीं। खुदरा खरीदारी के लिए माल की अवधारणा पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में बहुत पुरानी नहीं है। भारत में पहला शापिंग माल 1999 में दिल्ली में खुला था। उसके बाद मुंबई और चेन्नई में खुला। वर्ष 2003 के बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे जैसे मेट्रो शहरों, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद आदि में मालों की संख्या बढ़ने लगी, और अब यह अवधारणा उपनगरों तक फैल चुकी है। वर्ष 2011 के बाद भारत में उन्नत या 'एडवांस्ड माल' बनने लगे। उनमें मल्टीप्लेक्स भी शामिल होने लगे।

इस बीच कुछ ही वर्षों में देखते-देखते, सोशल मीडिया, ईमेल और खोज इंजन जैसे विभिन्न डिजिटल चैनलों के माध्यम से छोटे व्यवसायों, स्टार्ट-अप, गैर-लाभकारी संस्थानों के रूप में भी चारों ओर उद्योगों की एक नई कतार खड़ी होती जा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2025 तक भारतीय डिजिटल मार्केटिंग उद्योग 160 अरब डालर तक पहुंच सकता है। कुछ साल पहले कोरोना महामारी में जब घर बैठे खरीदारी अत्यंत मुफीद लगी, तो माल आधारित डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटे शापिंग माल नाटकीय गिरावट के साथ तेजी से बंद होने लगे। डिजिटल मार्केटिंग ने छोटे-मंझोले दुकानदारों और शापिंग माल संचालकों की तो जैसे कमर ही तोड़ दी है।

आनलाइन बिक्री में जोरदार वृद्धि हुई है, इस बदलते हालात का खुदरा रोजगार यानी स्थानीय श्रम बाजारों पर गंभीर प्रभाव देखा जा रहा है। शापिंग माल, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में हाल के वर्षों में अन्य प्रकार के खुदरा विक्रेताओं की तुलना में नौकरियों में भारी गिरावट आई है। यह कार्यक्षेत्र आनलाइन शापिंग की लहर उठने के कारण सबसे अधिक असुरक्षित हो चुका है। एक दशक पूर्व तक, छोटे शापिंग माल, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि खुदरा बाजार के विक्रेताओं से जुड़े रोजगार के नजरिए से पूरी महानगरीय बाजार व्यवस्था को एक खास दिशा में ले जाने की हैसियत रखते थे।

बाजार की यह करवट देश के ग्राहकों को भी खूब रास आ रही है।

भारतीय ई-कामर्स बाजार ऊंची उड़ानें भर रहा है। 'एरिक्सन कंज्यूमरलैब' की रपट के मुताबिक भारतीय अब प्रतिदिन औसतन 3.4 घंटे आनलाइन और स्मार्टफोन पर पांच-छह घंटे बिता रहे हैं। जिस रफ्तार से आनलाइन खरीदारी विस्तार पा रही है, फैशन, प्रौद्योगिकी, घरेलू सजावट जैसी आनलाइन शापिंग का भी विशाल उपभोक्ता वर्ग डिजिटल मार्केटिंग उद्योग की रणनीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता जा रहा है। 'इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया' (आईएएमएआइ) का एक अध्ययन बताता है कि हजारों लाख खातों के साथ डिजिटल क्षेत्र आम जीवन में संचार का एक अपरिहार्य उपकरण बन चुका है। एक समय में लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाने की दृष्टि से ईमेल मार्केटिंग सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हो चुकी है।

दूसरी तरफ, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म 'नाइट ऐंड फ्रैंकलिन' की एक ताजा रपट के अनुसार हमारे देश में छोटे शापिंग माल बहुत तेजी से बंद हो रहे हैं। आनलाइन खरीदारी से उन्हें तेज झटके लग रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण महानगरीय आधुनिकता के अंधाधुंध प्रवाह में निम्न और मध्यवर्गीय प्राथमिकताओं में बदलाव आना है। पिछले वर्ष तक देश में माल के अंदर किराए के लिए तैयार खाली दुकानों की संख्या 238 फीसद बढ़ी है। इस गिरावट ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को भी हवा दी है। देश के व्यावसायिक क्षेत्र में इससे मझोले दर्जे के व्यापारियों को झटका लगा है। 'नाइट फ्रैंक' की भारत के 29 शहरों के सर्वे पर आधारित 'थिंक इंडिया थिंक रीटेल-2024' शीर्षक रपट में आगाह किया गया है कि बचे-खुचे 132 छोटे शापिंग माल भी देर-सवेर बंद होने के कगार पर हैं। इनकी 36.2 फीसद से ज्यादा दुकानें खाली पड़ी हैं। इस तरह भवन निर्माताओं को 67 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बड़े शापिंग माल ही ऐसे झटकों से बचे हुए हैं। बीते वर्ष तक, दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु समेत देश के आठ महानगरों के 263 शापिंग माल बंद हो गए। बंद होने वाले माल में सर्वाधिक दिल्ली एनसीआर के हैं।

आनलाइन बिक्री में जोरदार वृद्धि हुई है, इस बदलते हालात का खुदरा रोजगार यानी स्थानीय श्रम बाजारों पर गंभीर प्रभाव देखा जा रहा है। शापिंग माल, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में हाल के वर्षों में अन्य प्रकार के खुदरा विक्रेताओं की तुलना में नौकरियों में भारी गिरावट आई है। यह कार्यक्षेत्र आनलाइन शापिंग की लहर उठने के कारण सबसे अधिक असुरक्षित हो चुका है। एक दशक पूर्व तक, छोटे शापिंग माल, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि खुदरा बाजार के विक्रेताओं से जुड़े रोजगार के नजरिए से पूरी महानगरीय बाजार व्यवस्था को एक खास दिशा में ले जाने की हैसियत रखते थे। अचानक आनलाइन शापिंग के हस्तक्षेप के बाद लाखों लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं।

सुखद है कि अन्य खुदरा क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। दूसरा सच यह भी है कि 'डिपार्टमेंटल स्टोर' को अपने कर्मचारियों को सामान्य आबादी के वितरण के अनुपात में फैलाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उनका व्यवसाय निजी होता है, पूरे देश में उनके उत्पादों की मांग होती है। इसलिए वे रोजगार के वैकल्पिक आधार भी दे रहे हैं। सच यह भी है कि साधारण नौकरियों की गिनती ही, श्रम बाजार की स्थितियों के ब्योरों का एकमात्र प्रासंगिक तथ्य नहीं है। तकनीकी की बहुस्तरीय चालढाल के साथ इसके और भी कई भिन्न आयाम प्रकट होते जा रहे हैं।

शांति की खोज

शिशिर शुक्ला

शांति शब्द कहने में जितना सहज और सरल प्रतीत होता है, वास्तव में अर्थ की दृष्टि से यह उतना ही अधिक गहरा और गूढ़ है। संसार का प्रत्येक मनुष्य आज शांति की खोज में बिल्कुल उसी तरह से लगा हुआ है जैसे कि बड़े-बड़े तपस्वी ईश्वर की तलाश में पूरी तन्मयता के साथ लगे रहते थे। अंतर सिर्फ इतना है कि ऋषि-मुनियों को तो यह भलीभांति पता था कि ईश्वर को कैसे ढूंढ़ा जा सकता है, लेकिन आज के भौतिकतावादी मनुष्य को सही मायने में शांति का अर्थ ही नहीं पता है। फिर भी वह भेड़चाल का अनुसरण करते हुए भांति-भांति के तरीकों से शांति को प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ नजर आता है। कभी शांति प्राप्त करने के लिए एकांत स्थान ढूंढ़ा जाता है, तो कभी लोग साधु और संतों के प्रवचन सुनने जाते हैं और कभी प्रकृति की गोद में जाकर शांति को ढूंढ़ने का प्रयत्न किया जाता है।

सवाल है कि क्या प्रत्येक मनुष्य के लिए ये सारे प्रयत्न सार्थक सिद्ध होते हैं? संभवतः नहीं, क्योंकि शांति को हासिल करने में इन कारकों की भूमिका सदैव गौण होती है। दरअसल, शांति एक ऐसा सुंदर भाव है जो हमारे अंतर्मन में अपने आप ही प्रस्फुटित होता है, बशर्ते कि उसके प्रस्फुटन के लिए आवश्यक दशाएं हमारे मन मस्तिष्क में विद्यमान हों। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी बीज को धरती के अंदर बो देने के उपरांत उसका पौधे के रूप में प्रस्फुटित होना। बीज से पौधे में रूपांतरण तभी संभव होता है जब उस रूपांतरण के लिए अनुकूल दशाएं पर्यावरण के द्वारा प्रदान की जाएं।

शांति एक ऐसा फल है जिसकी प्राप्ति के लिए अंतर्मन की भूमि को किसी भी तरह के बीज की आवश्यकता नहीं होती। अगर दशाएं अनुकूल हैं तो शांति का प्रस्फुटन अंतःकरण के द्वारा अपने आप ही कर दिया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार वे कौन-सी दशाएं हैं जो मन के अंदर शांति के भाव को जन्म देने के लिए अनिवार्य हैं। हम सभी जानते हैं कि योग के आठ अंगों में से पहला अंग 'यम' है और 'यम' के अंतर्गत भी पांच गुणों का समावेश होता है। ये पांच गुण हैं- सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। माना जाता है कि जीवन में इन गुणों का पालन सुनिश्चित कर लिया जाए तो हम अपने अंतर्मन को शांति की दिशा में मोड़ सकने में सक्षम होंगे। लेकिन इस पर विचार की दुनिया में अलग-अलग मत रहे हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। मनुष्य द्वारा ऊपर से तो शांति की तलाश का दिखावा किया जाता है, लेकिन उसके अंतर्मन में लालच, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, धन, दौलत और भी न जाने ऐसे कितने विचार एवं विषय बादलों की तरह उमड़-घुमड़ कर रहे होते हैं। ये विचार और दुर्गुण इस तरह छिपे होते हैं कि हमें यह एहसास नहीं होने देते कि उनका हमारे साथ होना ही हमारी प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है।

दरअसल, ये सभी ऐसे कारक हैं जो हमारी अक्ल पर पर्दा डालने का काम बखूबी करते हैं। लिहाजा हम यह समझ नहीं पाते कि शांति की तलाश के लिए हमें जब भी निकलना होगा, इन सभी कारकों को त्याग देना होगा। बुद्धि और विवेक पर पड़ा हुआ यह अस्थायी आवरण हमें बिना कुछ सोचे-समझे निर्णय लेने के लिए विवश कर देता है और हम अपने अंतर्मन को शांति का उपहार देने के लिए भांति-भांति के निरर्थक प्रयत्नों की शृंखला को आरंभ कर देते हैं। परिणाम यह निकलता है कि अनेक अनावश्यक प्रयासों की वजह से हमारे अंतःकरण में अशांति का स्तर और अधिक बढ़ जाता है।

हम कभी जल पर गौर करें तो यह पाएंगे कि यह जब भी स्थिर रहता है तो इसमें किसी भी प्रकार की तरंगें उत्पन्न नहीं होती। ज्यों ही किसी कंकड़ या पत्थर की चोट के माध्यम से इसे आघात पहुंचाया जाता है, तब उस स्थिति में यह जल स्थिर नहीं रहता, बल्कि इसकी सतह पर लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। आघात की तीव्रता अगर अधिक है तो ये लहरें सतह से लेकर भीतरी भागों तक भी पहुंच जाती हैं। हमारे अंतर्मन की स्थिति ठीक ऐसी ही है। जैसे ही सांसारिक मोहमाया, विषय, लोभ, लिप्सा हमारे शांत अंतर्मन पर चोट करती हैं, तत्काल ही इसके अंदर अशांति की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। एक विशेष बात यह है कि अशांति की हलचल का उठना तो नितांत सरल प्रक्रिया है, लेकिन इनसे मुक्ति पाना यानी इस अशांति का फिर शांति की अवस्था में परिणत होना एक बहुत कठिन कार्य है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक बार अशांति के आवरण में प्रवेश करने के बाद फिर शांति की ओर लौट पाना नितांत दुस्साध्य कार्य है।

शांति एक ऐसा रत्न है जो वास्तव में बहुत दुर्लभ है और खास बात यह है कि संसार में इस रत्न के कई नकली प्रतिरूप भी पाए जाते हैं। यह हमारी बुद्धिमता पर निर्भर करता है कि हम असली और नकली में विभेद करके वास्तविक शांति की ओर अपना कदम बढ़ाएं। मगर कदम आगे बढ़ाने से पहले हमें यह भलीभांति सुनिश्चित कर लेना होगा कि हमारा अंतर्मन पूरी तरह से निष्कलुष हो और इसके अंदर किसी भी प्रकार की उथल-पुथल विद्यमान न रहे। जब तक हम आसक्ति के पाश में बंधे रहेंगे तब तक हम चाह कर भी शांति की दिशा में अपना कदम नहीं बढ़ा सकते।

दुनिया मेरे आगे

शांति एक ऐसा फल है जिसकी प्राप्ति के लिए अंतर्मन की भूमि को किसी भी तरह के बीज की आवश्यकता नहीं होती। अगर दशाएं अनुकूल हैं तो शांति का प्रस्फुटन अंतःकरण के द्वारा अपने आप ही कर दिया जाता है। वे कौन-सी दशाएं हैं जो मन के अंदर शांति के भाव को जन्म देने के लिए अनिवार्य हैं।

पोषण की जंग

विश्व स्तर पर भारत अनाज से लेकर फलों तक के मामले में आत्मनिर्भर है। यह उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र और दक्षिण के आंध्र प्रदेश तक गेहूं, चावल और प्रसिद्ध श्रीअन्न की फसल वाले दस से अधिक कृषि प्रधान राज्यों से समृद्ध है और लगभग आधी कार्यरत जनसंख्या कृषि में संलग्न है। विडंबना यह है कि इस सबके बाद भी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत एक सौ ग्यारहवें स्थान पर है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसके लिए एक समय के भोजन की व्यवस्था हो पाना भी दुर्लभ है तो दूसरी तरफ एक वर्ग वह भी है जिसकी आदतें इस समस्या को और अधिक बढ़ा रही हैं। विवाह, उत्सव, आयोजन आदि में बने हुए भोजन का एक बड़ा हिस्सा आए दिन बर्बाद होता है। लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक भोजन अपनी थालियों में सजाते हैं। इस प्रकार जो भोजन बच जाने पर किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता था, वह खाद्य अपशिष्ट का रूप धारण कर पर्यावरण के लिए नई-नई समस्याओं को जन्म देता है, जिसे रोकने का दायित्व केवल सरकार और प्रशासन पर डाल दिया जाता है। यह जरूरी है कि विषय की गंभीरता को समझा जाए और आदतों में बदलाव लाए जाएं।

– खुशी श्रीवास्तव, शाहदरा, दिल्ली

कैसी परीक्षा

तमाम दावों और कथित कवायदों के बावजूद महत्त्वपूर्ण परीक्षाओं के प्रश्न पत्र समय से पहले बाहर आ जाने की घटनाओं को रोका नहीं जा पा रहा है। ऐसे में परीक्षाएं बेमानी होती जा रही हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नेट परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। यह घटना फिर न केवल लाखों परीक्षार्थियों के लिए एक झटका है, बल्कि पूरे शिक्षा और शोध समुदाय के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा दुखद पहलू है उन छात्रों के साथ प्रकारांतर से हुआ दुर्व्यवहार, जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद परीक्षा दी थी। यह घटना सरकार और नेशनल टेस्ट एजंसी की लापरवाही को उजागर करती है। सरकार को इस घटना की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय करने होंगे। इस घटना ने एक बार फिर हमारी शिक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया है।

– चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

सुविधा का संजाल

मनुष्य एक समाजिक प्राणी है। सभी लोग परिवार और अपने मित्रों के साथ रहना चाहते हैं। सोशल मीडिया ने मानव जीवन में एक क्रांति लाने का काम किया है। अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। आज एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी इसके अलग-अलग मंचों पर जुड़े हुए है। मगर इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी उभर कर सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई बार अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। राजनीति के क्षेत्र में भी सोशल मीडिया ने अपनी ताकत का अहसास कराया है। आज लोगों को सोशल मीडिया की आदत पड़ चुकी है। उस आदत की वजह से लोग अकेले रहना पसंद करने लगे हैं। इसके परिणामों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ध्यान रखने की जरूरत है कि सोशल मीडिया हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमें उसका गुलाम नही बनना चाहिए।

– हिमांशु शेखर, केसपा, गया

जिम्मेदारी का कठघरा

हाल ही में आई खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध रूप से निर्मित हुए पक्के मकानों को तोड़ा गया। तोड़े जाने वाले हजारों मकान, दुकानें, मंदिर-मस्जिद और कारखाने एक दिन में तो बनकर नहीं ही तैयार हुए होंगे। लोगों ने अपने खून-पसीने की कमाई से एक-एक ईंट जोड़कर निर्माण कार्य कराया होगा। सवाल है कि जब लोग इस प्रतिबंधित क्षेत्र में तत्समय अवैध निर्माण कार्य कर रहे थे या करा रहे थे तो क्या अवैध निर्माणों को रोकने की जिम्मेदारी इन संस्थाओं के अधिकारियों-अभियंताओं की नहीं थी? अगर शुरुआत में ही वे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते तो आज पूरे प्रशासन को इतना हलकान न होना पड़ता और लोगों को दर-दर न भटकना पड़ता। इसलिए अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-अभियंताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

– रतन कुमार श्रीवास्तव 'रतन', लखनऊ

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

समर्थन मूल्य बढ़ाना ही काफी नहीं, खरीद भी हो

केंद्र सरकार ने हाल ही में 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का जो फैसला किया है, उसे किसानों के लिए राहत के रूप में देखा जा सकता है। देश के किसानों के लिए पिछला कुछ समय अच्छा नहीं रहा है। इसलिए, उन्हें हर तरह की मदद की जरूरत है। किसानों का उत्साह बना रहना चाहिए। कृषि एकमात्र ऐसा पेशा है, जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति रूठ गई तो समझो किसान की किस्मत रूठ गई। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी-तूफान, पाला व सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जितने भी रूप हैं, उन पर किसी का भी बस नहीं है। मौसम साथ न दे तो किसान की मेहनत और उसके द्वारा लगाया गया धन बर्बाद होते देर नहीं लगती।

किसानों के लिए पिछले कुछ समय की प्रतिकूलता प्रकृति से संबद्ध तो रही है, कुछ कारण सरकारों से उनकी उम्मीदों से भी जुड़े हैं। देश के कुछ हिस्सों में किसानों का लम्बा आंदोलन भी इन्हीं उम्मीदों से जुड़ा रहा है। पैदावार का उचित दाम न मिलने या फसल की बर्बादी और कर्ज से घिर जाने पर आत्महत्या करने को मजबूर किसानों की डरावनी तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद उम्मीद की जा सकती है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी। इस बढ़ोतरी से किसानों की झोली में दो लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आने की बात कही जा रही है। यह बड़ी रकम है, जो किसानों को संबल देने में सक्षम है। यह बात दूसरी है कि कृषि क्षेत्र से ऐसी आवाजें भी आ रही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो वृद्धि की गई है वह 'ऊंट के मुंह में जीरे' के बराबर है और इससे किसानों को खास लाभ नहीं होगा। सरकार का कहना है कि उसने खुले दिल से मदद की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार की वृद्धि पिछले दस वर्ष में सर्वाधिक है। हालांकि देश के अन्नदाता को जितनी राहत दी जाए उतनी ही कम है क्योंकि हाड़-तोड़ मेहनत के बाद ही खेतों से पैदावार निकल पाती है। यह भी नहीं मानना चाहिए कि सरकार का काम यहां ही खत्म हो गया है। असल में जिन राज्यों में किसान की पूरी फसल की सरकारी खरीद हो जाती है, उन राज्यों के किसानों को अधिकतम लाभ मिलता है, जबकि कम खरीद करने वाले राज्यों के किसानों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता।

यह भी उजागर तथ्य है कि गेहूं जैसी कई उपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कम हुई है। सरकार खरीद कम करे या फिर नहीं के बराबर करे, व्यापारियों से समर्थन मूल्य जितना भी दाम नहीं मिले तो फिर किसान क्या करेगा? यह बुनियादी सवाल कृषक समुदाय लगातार उठाता रहा है। इसलिए समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून की मांग भी उठ रही है। सरकार को इस समस्या का भी समाधान निकालना चाहिए। इसके साथ ही किसानों की दूसरी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। जैसे कृषि बीमा में फसल मुआवजे की विसंगतियां और इसके त्वरित भुगतान की राह में अवरोध भी दूर करने होंगे।

योग की दृष्टि से प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। पूरक (सांस लेना), कुंभक, रेचक (सांस छोड़ना) - तीन भेद प्राणायाम के होते हैं। बाहर के वायु का भीतर लेना अपान, वायु को बाहर निकालना प्राण कहलाता है। कुछ लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं।

प्राणायाम - ब्रह्म का यात्रा पथ

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

> बाहर की वायु को प्राणादि पंचवायु कहते हैं। ये ही मुख्य प्राणशक्ति की तरंग-लहरियां हैं। यही वायु रूप में इस देह-मन को जीवित बनाए रखती हैं। मन में नाना प्रकार की इच्छा शक्ति को स्फुरित करती हैं। बाह्य वायु को स्पन्दित करने से पंचप्राण तथा 49 मरुत फलित होते हैं। यही कुण्डलिनी शक्ति कहलाती है। इसी से हमारा जीवन-प्रवाह ऊर्ध्व और अधोमुख प्रवाहित होता रहता है। यही हमारे अनुभव और ज्ञान का मूल है।

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः।
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्।।
(गीता 6.13)

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव।
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्।। *(गीता 8.10)*

गीता में कृष्ण कहते हैं–स्थिर होकर, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर, इधर-उधर न देखता हुआ, मन को रोककर मेरे परायण हो जाए। यह भी बताया है कि अन्तकाल में प्राण को भ्रूमध्य में रखकर, मन से स्मरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है।

प्राण ही ब्रह्म है। अक्षर सृष्टि है, अदृश्य संस्था है। हम प्राणायाम करते हैं तब वायु की गति का संचालन करते हैं। वायु हमारे पंच महाभूतों में से एक है। शरीर का संचालन करता है। प्राण आत्मा का क्षेत्र है, शरीर माध्यम मात्र है। यह व्यायाम नहीं हो सकता। दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। श्वास-प्रश्वास में मुख्यतया वायु का आदान-प्रदान होता है। प्राणों का आदान-प्रदान चक्रों एवं प्राणवाहिनी नाड़ियों से होता है। प्राणों से इन्द्रियों के कार्यों का संचालन भी होता है। कारण और स्थूल शरीर का सेतु भी प्राण ही है।

गीता के ही चौथे अध्याय में यह स्पष्ट हो रहा है कि कुछ योगीजन इन्द्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। कुछ समस्त विषयों का इन्द्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। कुछ योगी इन्द्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं का आत्मसंयम-योगरूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कुछ योगी ब्रह्म को ही मूलतत्त्व (अग्नि) मानकर 'यज्ञ' अर्थात् शरीर, इन्द्रिय आदि से उपाधि सहित जीव का ग्रहण करते हैं एवं कुछ उपाधि रहित जीव का। जब इन्द्रियादि उपाधियों का त्याग कर दिया जाएगा, तब स्वतः ही कर्म संन्यास हो जाएगा। आत्मा तो कर्म रहित है। संयम का अर्थ है-ध्यान, धारणा तथा समाधि का एक स्थान में नियोग करना। इन्द्रियों की स्वाभाविक गति को एक स्थान पर रोककर, उन्हें इष्ट की ओर मोड़ देना ही उनका हवन हो जाता है। विषयों से हटा देने पर इन्द्रियां अपना स्वरूप खोकर नष्ट हो जाती हैं।

कुछ योगी अपानवायु को प्राणवायु में, कुछ प्राणवायु को अपान वायु में हवन करते हैं। कुछ योगी प्राणायाम द्वारा प्राण-अपान की गति रोककर प्राणों का ही प्राणों में हवन करते हैं।

योग की दृष्टि से प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। पूरक (सांस लेना), कुंभक, रेचक (सांस छोड़ना)-तीन भेद प्राणायाम के होते हैं। बाहर के वायु का भीतर लेना अपान, वायु को बाहर निकालना प्राण कहलाता है। कुछ लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं। वायु को भीतर खींचने का अभ्यास बहुत काल तक करते हैं। कुछ प्राण में अपान का हवन करते हैं। भीतर की वायु को बाहर निकालने का बार-बार अभ्यास किया करते हैं। कुछ दोनों को रोककर स्थिर करने (कुंभक) का ही अभ्यास करते हैं। हृदय में ये ही कार्य ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र के हैं।

एक अन्य प्राणायाम में आहार का नियमन कर प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। जो वायु शरीर के जिन-जिन स्थानों में

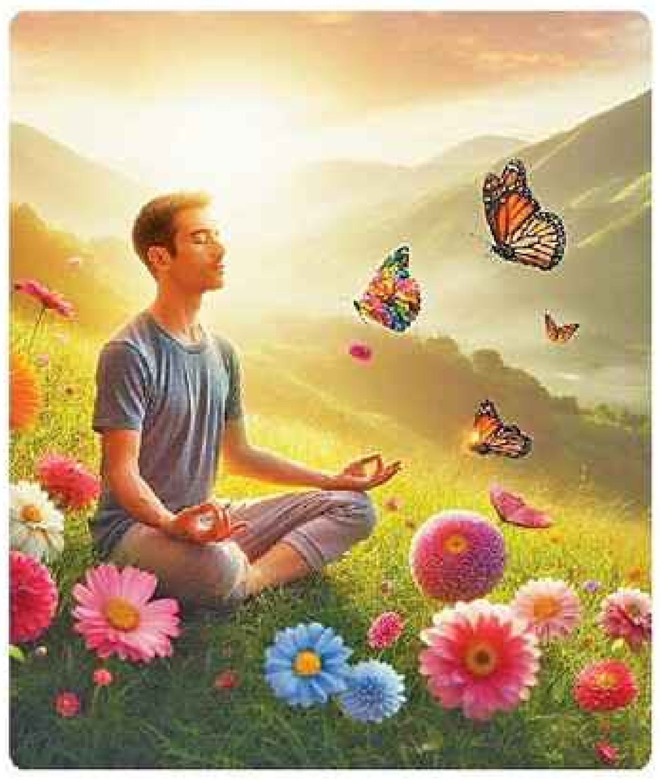

व्याप्त है उसे वहां का वहां ठहरा देते हैं। जिस वायु को (प्राण-अपानादि) ठहरा दिया उसमें अन्य सभी का हवन कर देते हैं। ऐसा भी कहा है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले (अमृत) ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उक्त सभी प्राणायाम-यज्ञों में अन्न की भूमिका ही नहीं है। अतः यज्ञ के अनुष्ठान में जो समय बचे, उसमें भोजन कर लेना चाहिए-**यज्ञशिष्टाशिनः** यज्ञ शिष्ट का अर्थ समय है।

प्राणायाम में एक है प्राण, दूसरा है वायु। अक्षर संस्था का प्राण ही क्षर संस्था में वायु (49 मरुत) के साथ भी युक्त होकर कार्य करता है। प्राण मूलतः आत्मा का अवयव है। मन-प्राण-वाक् ही आत्मरूप हैं। प्राण सदा मन का अनुसरण करता है। शरीर में प्राण के दस भेद हो जाते हैं–प्राण वायु बाहर जाता है, अपान का कर्म अधोगमन, व्यान आकुंचन-प्रसारण धर्मा, समान वायु खाये हुए और पीये हुए द्रव्यों को रस-रक्त आदि धातुओं में परिणत करने का कार्य करता है। उदान का कार्य शरीर को उठाये/कड़क रखना है। नाग का कर्म डकार लेना आदि, कूर्म का पलकों को झपकाना आदि, कृकल का छींक आदि, देवदत्त का जृम्भण (जम्हाई/उबासी), धनंजय का कर्म शरीर का संरक्षण है।

ब्रह्म निर्गुण है। उसकी षोडश कलाओं में एक कला ही व्यक्त है, शेष अव्यक्त हैं। व्यक्त कला ही त्रिगुणमयी प्रकृति है। प्रकृति से त्रिगुण और त्रिगुण से विश्व/शरीर है। यही ब्रह्म की सृष्टि-कामना- नाना होने की वासना है। त्रिगुण ही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में प्राण-वायु रूप संसार लीला का सम्पादन कर रहे हैं। इससे ही सूक्ष्म प्राण शक्ति या अव्याकृत प्रकृति का पता चलता है। उस प्रकृति या प्राणशक्ति से ही यह त्रिगुणात्मक जगत बार-बार उत्पन्न और लय होता है। प्राण के बाहर विचरण करने से ही जीव की संसारवासना उत्पन्न होती है। इसी कारण किसी को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। मन की विषय ग्रहण करने की लालसा ही अज्ञान या वासना है। प्राण का अवरोध ही मन का अवरोध है। इसीलिए प्राणायाम करते हैं। श्रुति कहती है- **'तपो न परं प्राणायामात् ततो विशुद्धिर्मलानौ दीप्तिश्च ज्ञानज्योति'** — अर्थात् प्राणायाम से श्रेष्ठ कोई तप नहीं है। इससे सारे मल शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश होता है। वासना की तरंगें चित्त को उद्वेलित करती हैं। प्राणायाम ही इससे मुक्त करता है।

बाहर की वायु को प्राणादि पंचवायु कहते हैं। ये ही मुख्य प्राणशक्ति की तरंग-लहरियां हैं। यही वायु रूप में इस देह-मन को जीवित बनाए रखती हैं। मन में नाना प्रकार की इच्छा शक्ति को स्फुरित करती हैं। बाह्य वायु को स्पन्दित करने से पंचप्राण तथा 49 मरुत फलित होते हैं। यही कुण्डलिनी शक्ति कहलाती है। इसी से हमारा जीवन-प्रवाह ऊर्ध्व और अधोमुख प्रवाहित होता रहता है। यही हमारे अनुभव और ज्ञान का मूल है। चिद्शक्ति मूलाधार में शरीर के अवयवों को स्थिर रखती है। हृदय में आकर स्थितिपद प्राप्त करती है। सूक्ष्म मृणाल (कमल नाल) तन्तु के समान हृदय में गमनागमन करती है (यत्+जू)। भ्रूमध्य में यही बिन्दु रूप दिखाई पड़ती है। तब उसका नाम और रूप होता है। बिन्दु ही प्रकाश की दिशा में आदि रूप है। किन्तु ब्रह्म 'रूपातीत और निरंजन' ही है।

यह प्राण जब नाड़ियों में प्रवेश कर शरीर में संचरण करता है तभी जीव बाह्य कर्मों की चेष्टा में लगता है। इन्द्रियां बाह्य विषयों की ओर जाती हैं। श्वास-प्रश्वास का प्रवाह चलता है। प्राण के कम्पन को रोकने से मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं। आत्मा के साथ मिला हुआ मुख्य प्राण ही ब्रह्म भाव है। श्वास पर विजय पाने के सिवा मन को स्थिर करने का अन्य मार्ग नहीं है। प्राणायाम ही इसका उत्तर है। योगसूत्र के अनुसार–**तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः** अर्थात् श्वास-प्रश्वास के गति-विच्छेद को ही प्राणायाम कहते हैं। श्वास बाहर जाकर भीतर प्रवेश न करे, भीतर आकर बाहर न निकले, यह कुंभ अवस्था ही हवन-क्रिया है। चंचलता मन का प्रधान मल है। प्राणायाम से इनका परिष्कार होता है। इससे प्राप्त स्थिरता ही "यज्ञ का अवशेष" है।

योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी के अनुसार- भ्रूमध्य में दृष्टि रखने पर नाना प्रकार के दर्शन-श्रवण हो सकते हैं। विराट् पुरुष-सहस्त्रशीर्षा- सबके भ्रूमध्य से ब्रह्मरंध्र तक दश अंगुल के बीच है। नासाग्र पर ध्यान प्राणवायु भाग को स्थिर करता है। मूलाधार से जुड़ा होने से इस केन्द्र को भी पूर्ण रूप से गतिमान करता है। अतः प्राण की गति मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक सहज हो सकती है। यह प्राणवायु भ्रू-मध्य पर रूपान्तरित होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है। यह क्षर से अक्षर क्षेत्र में प्रवेश की स्थिति है। भ्रू-मध्य पर ध्यान प्राण की स्थिरता लाता है। प्राणवायु यहां पर लीन हो जाता है। सहस्त्रार तक अक्षर की यात्रा है। गुणातीत अवस्था ही मोक्ष है। क्योंकि अन्तकाल में जो भाव मन को संक्रान्त करते हैं, वैसी ही जीव की भावी दशा होती है।

क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

नियोग – काम में लगाना/नियोजित करना। **ऊर्ध्व** – ऊपर। **अधोमुख** – नीचे की ओर। **गमनागमन** – जाना-आना। **परिष्कार** – स्वच्छ।

इवागुमी एयर स्केप: सिंगापुर मरीना बे पर जगमग 16 'चट्टानें'

सिंगापुर के मरीना बे में करीब 4900 वर्ग मीटर क्षेत्र में रखी गई ये 16 चट्टानें वास्तविक नहीं हैं, बल्कि गुब्बारे की तरह हैं, जिन्हें हवा से फुलाया गया है। प्रकृति की सुंदरता का उत्सव मनाने वाली 'इवागुमी एयर स्केप' नामक यह कलाकृति रात में जगमगाती है। इसके लिए कलाकार और मेलबर्न स्थित कला और प्रौद्योगिकी स्टूडियो 'ईएनईएसएस' के संस्थापक निमरोड वीस ने जापानी अवधारणा इवागुमी से प्रेरणा ली, जिसका अर्थ है रॉक फॉर्मेशन। यह कलाकृति आगंतुकों को दरारों और रास्तों के माध्यम से सैर कराती है और आनंदित करती है। रात में चट्टानें अंगारे या लावा जैसी दिखाई देती हैं, जिससे दर्शक धरती की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। 'आइ लाइट सिंगापुर' के तहत इस कलाकृति का प्रदर्शन 23 जून तक जारी रहेगा।

सामयिक: नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एकजुट हो रहे हैं रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और चीन

'बुराई के गठबंधन' को बढ़ावा देने वाली है रूस-उत्तर कोरिया संधि

मैक्स बूट
'द रोड नॉट टेकन: एडवर्ड लैंसडेल एंड द अमेरिकन ट्रेजेडी इन वियतनाम' के लेखक
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

> लोकतांत्रिक दुनिया को भी उसी एकजुटता से जवाब देना चाहिए, जितनी एकजुटता निरंकुश सरकारें प्रदर्शित कर रही हैं। यूरोप और एशिया में अपने सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध बनाना अमरीका के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी।

रूस के अधिनायक व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' संधि आज वैश्विक मामलों में सबसे भयावह और चिंतित करने वाली स्थितियों में एकजुटता का सबसे नया प्रदर्शन है। अमरीका के नेतृत्व वाली और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और चीन मिलकर काम कर रहे हैं।

यह गठबंधन वह 'बुराई की धुरी' भी नहीं है, जो राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने इराक पर अपने हमले को उचित ठहराने के लिए ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया के लिए इस्तेमाल किया था। इन देशों का एक-दूसरे से बहुत ही कम संबंध था। ये सहयोगी होने से बहुत दूर थे। ईरान और इराक तो एक-दूसरे के दुश्मन थे जो 1980 के दशक में खूनी युद्ध लड़ चुके थे। मौजूदा हालात का सबसे सटीक वर्णन करते हुए इजरायल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्यूरिटी स्टडीज के एक वरिष्ठ शोधकर्ता योएल गुजांस्की ने इसे 'बुराई का गठबंधन' कहा है। चारों तानाशाही तंत्र - रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और चीन - नाटो या पुरानी वारसा संधि की तरह इसे औपचारिक सुरक्षा गठबंधन तो नहीं कहते हैं पर वे अमरीका और उसके सहयोगी देशों को यूक्रेन से लेकर इजरायल और दक्षिण कोरिया तक चुनौती देने के वास्ते मोटे तौर पर एकजुट हैं।

उत्तर कोरिया ने रूस को दर्जनों शॉर्ट-रेंज मिसाइल और लगभग 50 लाख ऑर्टिलरी शेल्स उपलब्ध कराए हैं ताकि वह यूक्रेन के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके। बदले में, रूस ने मार्च में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पर वीटो कर दिया जिसमें उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए एक पैनल को अधिकृत किया जाना था। एक समय था जब रूस ने ही उत्तर कोरिया के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का समर्थन किया था। रूस को उत्तर कोरिया की मदद से यूक्रेन के लिए तो उत्तर कोरिया को रूस की सहायता से दक्षिण कोरिया, जापान और अमरीका के लिए जोखिम बढ़ सकता है। ईरान दूसरा देश है जो रूस को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। ईरान ने अपने सेल्फ-डेटोनेटिंग ड्रोन उत्पादन के लिए रूस में एक कारखाना भी खोला है। बदले में तेहरान को एसयू-35 लड़ाकू विमान, एमआइ-28 लड़ाकू हेलिकॉप्टर और अन्य रूसी सैन्य उपकरण मिलेंगे। रूस और ईरान के बीच घनिष्ठता 2015 से ही बढ़ रही है जब पुतिन ने सीरिया में रूसी वायु सेना भेजने का फैसला किया था। उत्तर कोरिया या ईरान की तरह, चीन प्रत्यक्ष रूप से रूस को युद्धक सामग्री की आपूर्ति तो नहीं कर रहा, पर उसने माइक्रोचिप्स, मशीन टूल्स और अन्य जरूरी पुर्जे दिए हैं जो रूस के हथियार बनाने वाले कारखानों की क्षमता बढ़ा रहे हैं।

अनुदार मूल्यों को बढ़ावा देने वाली दुनिया की ताकतें नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को तार-तार करने के लिए करीब आ रही हैं। इस 'बुराई के गठबंधन' को रोकने की कोशिशों में दुनिया के लोकतंत्रों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए।

आर्ट एंड कल्चर

संपूर्ण जीव जगत से जोड़ता है नल्लामुथु का सिनेमा

नल्लामुथु बाघिन को जानवर समझने ही नहीं देते। वे अहसास कराते हैं कि बाघ भी हमारी तरह हैं

सुब्बैया नल्लामुथु ने 9 वर्ष एक बाघ के पीछे व्यतीत कर दिए। 'एलिफेंट व्हिस्परर्स' को ऑस्कर मिलने के बाद निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्विस ने कहा था, उन्हें हाथियों की इस कहानी को शूट करने में 5 वर्ष लगे, यदि पंद्रह लगते तब भी वे देंती। वास्तव में वाइल्ड लाइफ पर बनीं फिल्में देखना जितना सहज लगता है, उसे तैयार करना उतना ही कठिन होता है। जंगली जानवरों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, न ही निर्देशित कर सकते। फिर भी ऐसी कहानी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जहां वे थोड़ी संवेदना और ढेर सारा प्यार महसूस कर सकें। वर्षों तक किसी जंगली जानवर की गतिविधियों को हर पल रिकॉर्ड करते जाना कि क्या पता सेकंड के किस हिस्से में कोई विलक्षण भाव दिख जाए, वाकई कौशल, असीम धैर्य और जिद की मांग करता है। ऐसे में बाघों के प्रति अपनी पूरी मेधा को समर्पित कर देने वाले फिल्मकार सुब्बैया नल्लामुथु को मुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवसर पर 'वी शांताराम लाइफटाइम अचिवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया जाना संतोष देता है। इस अवार्ड की चर्चा हालांकि थोड़ी कम होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में इसका महत्त्व 'दादा साहब फाल्के सम्मान' के बराबर ही माना जाता है।

विनोद अनुपम
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कला समीक्षक
@patrika.com

नल्लामुथु की विशेषता है कि अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता से उन्होंने अपने वृत्त चित्रों को कठोर यथार्थ से परे कोमल कहानियों में बदल दिया। वे कहते भी हैं कि बाघों में मनुष्य के समान ही तमाम संवेदनाएं होती हैं, जाहिर है जब मनुष्य की कहानियां कही जा सकती हैं तो उसी संवेदना से बाघों की क्यों नहीं। बाघों पर तो उन्होंने 5 वृत्त चित्र बनाए, जिसमें से अधिकांश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण 'द वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइगर' माना जाता है, जो रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन मछली पर बना है। 2007 से उन्होंने मछली को शूट करना शुरू किया और उसकी मृत्यु तक (2016) वे लगातार 9 वर्षों तक उसकी गतिविधियों को शूट करते रहे। इस फिल्म का जब उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन आरंभ किया तो उनके पास एक कैमरे से शूट किए 250 घंटे से अधिक के फुटेज थे, जिससे लगभग 45 मिनट की फिल्म तैयार की गई। इस फिल्म में एक बाघ का जीवन मात्र नहीं है, इसमें उसके दोस्त, उसके दुश्मन, उसके परिवार, उसके बच्चे, उसकी संवेदना सब कुछ पूरी संवेदनशीलता से दिखता है।

किस तरह एक मजबूत बाघिन अंतिम दिनों में लाचार हो जाती है, यह भी यहां नजर आता है। नल्लामुथु बाघ को जानवर समझने ही नहीं देते। वे अहसास कराते हैं कि बाघ भी हमारी तरह जीव हैं। वास्तव में हम जब सिनेमा की बात करते हैं, तो याद रखना चाहिए एक सिनेमा नल्लामुथु जैसे संवेदनशील प्रतिभाशाली फिल्मकारों का भी है, जिससे जुड़ना अपने संपूर्ण जीव जगत से जुड़ना है।

आपकी बात

ठोस कदम उठाए सरकार

नेट और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की महत्त्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आना चिंताजनक है। इससे युवा वर्ग में रोष पैदा हो रहा है। इससे सरकार की साख भी प्रभावित हो रही है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। इस मामले में अब देरी नहीं होनी चाहिए।

-ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उदयपुरा, मध्यप्रदेश

मेहनत पर पानी फिरने से निराशा

नीट के बाद अब नेट में भी पेपर लीक जैसी गड़बड़ी सामने आना अफसोसजनक है। इन परीक्षाओं के लिए युवा भारी खर्च करके कोचिंग भी करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, तो वे निराश हो जाते हैं। परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

-सुभाष बुडावन वाला, रतलाम, मध्यप्रदेश

भविष्य से खिलवाड़

परीक्षा में धांधली एवं प्रश्नपत्रों का परीक्षाओं से पूर्व बाहर आ जाना निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। इस प्रकार की घटनाओं से परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की तो साख गिरती ही है, साथ ही लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाना चाहिए।

-महेश आचार्य, नागौर

अभिभावकों में चिंता

परीक्षाओं की विश्वसनीयता घटने से विद्यार्थियों में और उनके अभिभावकों में हताशा व निराशा बढ़ रही है। अभिभावकों को बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे अपने अभिभावकों की अपेक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और परीक्षा रद्द होने, पेपर लीक होने से उनका भविष्य खतरे में है।

-सुनील कुमार माथुर, जोधपुर

आज का सवाल

भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

कल का सवाल था: परीक्षाओं की विश्वसनीयता घटने का क्या असर हो रहा है?

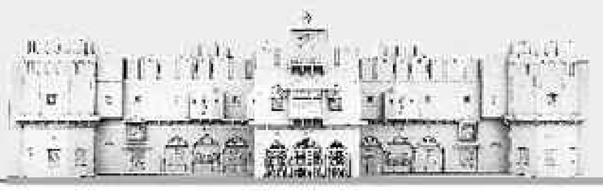

चिंतन

कश्मीर से योग कर पीएम का विश्व को शांति के संदेश

आज पूरी दुनिया योगमय हुई। विश्व ने 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इन दस वर्षों में दुनिया में योग की स्वीकार्यता बढ़ी, लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ी, योग के अनेक रूपों का विस्तार भी हुआ। जो योग पहले भारत तक सीमित था, उसमें भी कुछेक संपन्न लोगों तक था, आज यह वैश्विक है, आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय है। भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। कोरोना महामारी के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी, इसके बाद लोगों के खानपान की आदतें बदलीं, लोग योग व व्यायाम के प्रति आकर्षित हुए। आज योग के जरिये विश्व में करोड़ों लोग रोजगार भी पा रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। बड़ी बात है कि इस्लामिक देशों ने भी योग को खुले दिल से अपनाया है। भारत में देश भर में हजारों कार्यक्रम योग के हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर में योग दिवस मनाकर कर आतंकवादियों और आतंकपरस्तों को खुला संदेश दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीर में एक के बाद एक चार आतंकी हमले हुए हैं। जिस दिन मोदी सरकार ने शपथ ली, उसी दिन आतंकवादियों ने कश्मीर में तीर्थयात्रियों से से भरे बस पर हमला किया। कश्मीर में कई आतंकी हमले के बाद से सरकार सख्त है और सुरक्षा कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन क्लीन पहले से जारी है। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में योग दिवस मनाकर सबको शांति का संदेश दिया, आतंक के डर पैदा करने के मंसूबे पर पानी फेरा। भारत आतंकवाद के खिलाफ चार दशक से जंग लड़ रहा है। अब आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। योग दिवस पर प्रधानमंत्री दुनिया को संदेश भी दिया कि योग वैश्विक भलाई का एक शक्तिशाली माध्यम है। योग केवल एक विधा नहीं, बल्कि विज्ञान भी है और यह समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। ध्यान योग का हिस्सा है लेकिन जब इसकी बात होती है तो बहुत लोगों को लगता है कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। अल्लाह, ईश्वर या गॉड को प्राप्त करने का, उससे साक्षात्कार करने का ये कार्यक्रम है, यह योग का एक ध्येय है। योग ने लोगों को यह महसूस कराने में मदद की है कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। योग स्व के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार समाज को भी फायदा करता है, और जब समाज को लाभ होता है तो समस्त मानव जाति को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। तुर्कमेनिस्तान, सऊदी अरब, मंगोलिया और जर्मनी में योग की प्राचीन विधाएं वहां तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं और वहां लोग योग को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। फ्रांस की 101 वर्षीय महिला शारलोट चोपिन अपने देश में योग को लोकप्रिय बना रही है। भारत सरकार ने उनको योग में उनकी सेवाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। योग के वैश्विक स्तर पर प्रसार से इसके बारे में धारणा में बदलाव आया है, क्योंकि इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग भारत की यात्रा कर रहे हैं। योग मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय 'स्वयं और समाज के लिए योग' है। योग में जोड़ने की शक्ति है, खुद से, समाज से और ब्रह्मांड से। योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए।

दिल्ली जल संकट
योगेश कुमार सोनी

पानी पर नहीं हो राजनीति

> दिल्ली सरकार जो किसी भी मामले में दूसरे पक्ष पर आरोप लगाने में माहिर है,उसका कहना है कि हरियाणा सरकार हमें पानी नहीं दे रहा। बताया जा रहा है हिमाचल से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार नहीं दे रही, लेकिन इस बात को खारिज करते हुए हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से पानी नहीं मिला। अभय ने कहा कि यदि हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से पानी मिलता है, तो वह तुरंत उसे दिल्ली की ओर भेज देगा। आश्चर्य यह है कि इस मामले को लेकर केन्द्र कोई भी प्रतिक्रिया न देकर किसी भी प्रकार के समाधान पर बात नहीं कर रहा है। दिल्ली जल संकट पर केंद्र की चुप्पी खल रही है।

देश की राजधानी इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। दिल्ली में पानी की कमी होने के कारण दिल्लीवासी बहुत परेशान हैं। ज़रूरत के हिसाब से लगभग 25 से 30 फीसदी पानी की उपलब्धता कम हो गई है। इसका असर यह हुआ है कि दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाके के अलावा पॉश कॉलोनियों में भी लोगों को पानी के लिए बाल्टी लेकर व्यवस्था करनी पड़ रही है। दिल्ली के सबसे पॉश एरिया लुटियन जोन में भी कई इलाकों को इस समय पानी के टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली का जल संकट वर्षा शुरू होने के बाद ही सुधरेगा। फिलहाल तेज गर्मी से अभी कई दिनों तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है और इस जल संकट को लेकर हाल ही में हुई मीटिंग में पड़ोसी राज्यों से जल उपलब्धता पर कोई सहमति नहीं बनी। दिल्ली पानी की आपूर्ति के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पानी की अगाध आपूर्ति होती रही है। इस बार पानी की उपलब्धता में कमी राजनीतिक वजह से अधिक प्रतीत हो रही है, हालांकि हरियाणा खुद भी जल संकट का सामना कर रहा है।

इस आधार पर स्पष्ट है हो जाता है कि यह जल संकट कई दिनों तक बने रहने की संभावना है। हम इन सारी बातों से पूरी स्थिति से अवगत हो गए और जल संकट से रोज लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस मामले में केन्द्र व राज्य सरकार अपनी कितनी गंभीरता दिखा रही है यह स्थिति देखकर लग रहा है। हर रोज बहुत आसानी से मीडिया में बयान देकर एक-दूसरे पर आरोप लगाकर अपना-अपना बचाव कर रहे हैं। आम लोगों की मजबूरी कोई नही समझ रहा। पानी सर्वाधिक दैनिक जरूरत है, इसके बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है। दिल्ली सरकार जो किसी भी मामले में दूसरे पक्ष पर आरोप लगाने में माहिर है,उसका कहना है कि हरियाणा सरकार हमें पानी नहीं दे रहा। बताया जा रहा है हिमाचल से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार नहीं दे रही, लेकिन वहीं इस बात को खारिज करते हुए हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से पानी नहीं मिला। अभय ने कहा कि यदि हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से पानी मिलता है, तो वह तुरंत उसे दिल्ली की ओर भेज देगा। यह तो राज्यों की बीच की कहानी है लेकिन आश्चर्य यह है कि इस मामले को लेकर केन्द्र सरकार कोई भी प्रतिक्रिया न देकर किसी भी प्रकार के समाधान पर बात नहीं कर रही है। दिल्ली जलसंकट पर केंद्र की चुप्पी खल रही है, जैसा कि दिल्ली एक केन्द्रीय शासित राज्य है और इसलिए बहुत सारे मामलों में जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की बनती है तो,क्यों इसका समाधान नहीं निकाला जा रहा। जबकि जल शक्ति मंत्रालय केन्द्र के हाथ में हैं बावजूद इसके, आखिर दिल्ली की जनता को क्यों परेशान हो रही है। क्या अलग-अलग इंजन की सरकार होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी समझना चाहिए कि हाल ही में दिल्ली में हुए लोकसभा चुनाव में जनता सातों सीटें उन्हें जिताई है। ऐसे में जनता के प्रति इन सांसदों कीііі

जिम्मेदारी बनती है। जल संकट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्यों व केन्द्र सरकार के बीच कोई भी बैठक नहीं हुई। अंतरराज्यीय मामला होने के चलते केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि किसी राज्य में संकट आने के बाद पड़ोसी राज्यों से कैसे आपूर्ति करा सकती है। किसी भी घटना से लगातार ग्रसित होने से जनता बागी हो जाती है और फिर समाज में संदेश गलत जाता है। यह वैसे भी देश की राजधानी है जहां देश के प्रधानमंत्री के अलावा देश के सभी बड़े-छोटे मंत्री रहते हैं। जहां एक ओर हम डिजिटल युग में होने की हुंकार भरते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी दुर्लभ तस्वीर देखकर असहनीय पीड़ा का एहसास होता है। क्या आज पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए तरसते अच्छे लगते हैं।

पानी को लेकर हरियाणा में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दिल्ली में लोग एक बाल्टी पानी के लिए एक-दूसरे को जान से मारने पर उतारू हो जाते हैं। कई जगहों पर लडाई हुई जिसमें एक शख्स का सिर तक फट गया। इस मामले में हर किसी को अपना किरदार ईमानदारी से निभाना होगा। जैसा कि दिल्ली में जल संकट की स्थिति हर वर्ष ऐसी ही रहती है तो दिल्ली सरकरा को पहले से तैयारी या पड़ोसी राज्यों से बातचीत करनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली के जल संकट का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर पर्याप्त जल क्षेत्र नहीं है। कभी दिल्ली के कुल 1500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 18 वर्ग किलोमीटर इलाका जल क्षेत्र हुआ करता था। इसमें भी सबसे अधिक हिस्सा यमुना के बहाव क्षेत्र का हुआ करता था। एक जमाने में यह जल क्षेत्र लोगों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त हुआ करता था। लेकिन कई लोगों ने यमुना के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर घर बनाना शुरू कर दिया और यह अब थोड़े बहुत नहीं बहुत अधिक बन गए और हर रोज वहां कब्जा होता जा रहा है, जिसको लेकिन शासन-प्रशासन की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही।

ज्ञात हो कि पिछले वर्ष दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। इस दौरान दिल्ली की यमुना खादर मे रह रहे लोगों को बाहर आना पड़ा और जब यह बाहर आए तो प्रशासन के हाथ-पैर फूल गए थे चूंकि उनको बिल्कुल भी अंदाजा नही था कि इतने लोग यमुना खादर में इतने लोग रहे थे। जब उन लोगों को बाहर निकाल कर सड़कों के किनारे शिफ्ट किया गया तो ऐसा लगा कि कोई कॉलोनी बस गई हो। अब समझिए कि यहां दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से शेष जल क्षेत्र भी अतिक्रमण का शिकार हुए जिससे जल क्षेत्र सिकुड़ गया। इसका यह असर हुआ है कि दिल्ली का भूगर्भीय जल स्तर भी बहुत कम हो गया है। जब पानी एकत्रित होने की जगह मनुष्य ले लेंगे तो सृष्टि का नष्ट होना व मानव जीवन पर प्रहार होना तय है। दरअसल यहां सारा खेल वोट बैंक का है। राज्य सरकार इनके आधार कार्ड व वोटर आईडी बना देती है और समय आने पर उनके मत का प्रयोग करती है। जबकि जो लोग यहां आकर बसे हैं उनका इतिहास किसी को स्पष्ट नहीं पता। कोई कहता है यह काम की खोज में बाहरी राज्यों से आ लोग हैं तो कोई इनके विषय में अन्य अलग-अलग कारण बताता है लेकिन कारण कोई भी हो यहां रह रहे लोगों ने अपनी पूरी कॉलोनी सी बना ली जो बेहद रिस्की भी है, चूंकि यदि अचानक यहां पानी आ जाए तो कई लोगों की जान जा सकती है चूंकि बाढ़ के समय पर यहां फंसे लोगों को निकाला था तो इस बात का एहसास हुआ था। बहरहाल,दिल्ली की हाल की स्थिति के लिए सभी को राजनीति छोड़कर जनता के लिए पानी की व्यवस्था करनी होगी चूंकि अब पानी कम होने की वजह से पानी सर के ऊपर जा रहा है। राजनीति करने के लिए तमाम मुद्दे हैं लेकिन पानी जैसे बुनियादी चीज के लिए जनता तरसे तो यह सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद बेशर्मी की बात है चूंकि जल मानव जीवन का पर्यायवाची है और इंसान इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

कबीर जयंती

डॉ. अशोक कुमार भार्गव

सामाजिक क्रांति के अग्रदूत

भारतीय चिंतन परम्परा में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कबीर का चिंतन सामाजिक जड़ता, अराजकता, जन्म के आधार पर भेदभाव, साम्प्रदायिकता, अस्पृश्यता और उंच-नीच जैसी अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ शंखनाद है। वे ऐसे आदर्श मानवीय समाज की परिकल्पना करते हैं जहां सामाजिक समरसता पर आधारित मानवीय धर्म की प्रतिष्ठा हो। कहा जाता है कि काशी में लहरतारा तालाब पर नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपति को एक नवजात शिशु अनाथ रूप में प्राप्त हुआ। इन दोनों ने बालक का पालन पोषण किया जो संत कबीर के नाम से विख्यात हुए। निम्न और वंचित समझी जाने वाली जुलाहा जाति में पलकर भी तत्कालीन धर्म के दिग्गज पंडितों, मौलवियों को एक ही साथ फटकार सकने में समर्थ कबीर ने 'मसी' और 'कागद' न छूकर तथा कलम हाथ में न पकड़ कर भी केवल प्रामाणिक अनुभव के बल पर जो कुछ कहा उसे सुनकर बड़ी-बड़ी पोथियों के अध्येता भी चकित रह गए। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रणेता कबीर ने निराकार ब्रह्म के उपासक होकर भी अपने प्रियतम के वियोग में जो चिरंतन व्याकुलता प्रकट की, वह किसी भी सगुणोपासक अथवा प्रेमोपासक की विकलता से कहीं अधिक मार्मिक तीव्र एवं गहन बन गई। संत कबीर का उद्भव जिन युगीन परिस्थितियों मे हुआ वे अत्यंत संकीर्ण, विषम और विसंगति पूर्ण थी। उत्तर भारत में मुस्लिम साम्राज्य अपनी जड़ें पूरी तरह जमा चुका था। तुर्क, अफ़गान, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी वंश अपने-अपने काल में इन जड़ों को और गहरा बनाने में

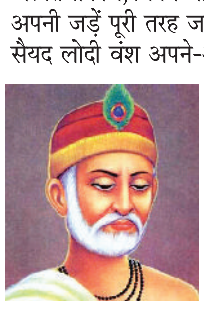

कामयाब रहे। हिंदुओं के छोटे-छोटे राज्य भी अब समाप्त हो चुके थे। राजनीतिक दृष्टि से हिंदुओं में अब कोई शक्ति शेष नहीं थी। धार्मिक क्षेत्र में भी भेदभाव का साम्राज्य था। देश के पूर्वी भागों में वज्रयानी सिद्धों के तंत्र-मंत्रों का और पश्चिमी भाग में नाथ संप्रदाय के हठयोग का प्रभाव था। हिंदू धर्म वैष्णव, शैव और शाक्त संप्रदायों में विभक्त था और इन धर्म साधनाओं में परस्पर प्रबल विरोध और संघर्ष की स्थिति थी। हिंदुओं में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। एकेश्वरवादी इस्लाम मूर्ति पूजा विरोधी था। इस्लाम के साथ सत्ता थी उनमें ऊंच, नीच का भेद नहीं था। कुछ वर्गों में सांप्रदायिक कट्टरता एवं संकीर्णता पनप रही थी। समाज में धर्मगत, जातिगत, वर्णगत संप्रदाय गत विषमताएं विकट थीं। फलस्वरूप समाज का निम्न और अछूत वर्ग शोषण, उत्पीड़न, उपेक्षा, अपमान और सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताओं का शिकार होने से इनमें आक्रोश, असंतोष और विक्षोभ प्रबल हो रहा था।

ऐसी विषम स्थिति में कबीर की क्रांत दर्शिता विभिन्न मतवादों को समन्वित कर 'सूप' का स्वभाव लेकर उभरी जो किसी भी मत और संप्रदाय के 'थोथे' तत्व को उड़ा सकने एवं उसके सार तत्व को ग्रहण कर सकने में समर्थ है। यही कारण है कि उनकी बानियां लोक मंगल की भावना से प्रेरित लोकमंगल की साधना को समर्पित है। कबीर का चिंतन आचरण शुद्धि, लोक कल्याण, सांप्रदायिक सद्भाव तथा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन पर केंद्रित है। कबीर ने तत्कालीन समाज में फैले कर्मकांडों, पाखंडों, जातिगत भेद-भावों अंधविश्वासों, बाह्यचारों और सामंती व्यवस्था की खुलकर आलोचना की। हिंदू हो या मुसलमान पंडित हो या मौलवी सबको समान रूप से फटकार लगाई। कबीर ने मुसलमान की हिंसात्मक प्रवृत्ति की निंदा की। मूर्ति पूजा का खंडन किया। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के विरुद्ध बगावत की।माला जपने, जप तप करने, व्रत रखने, रोजे रखने, मस्जिद में बांग लगाने आदि अनेक पाखंडों की आलोचना की। कबीर ने 'जाति-पांति पूछे नहि कोई। हरि को भजै सो हरि को होई' कहकर समाज को एक नई दिशा दी।

कबीर की कटु आलोचनाओं से समाज के ठेकेदारों के निहित स्वार्थ जब प्रभावित होने लगे तो इन्होंने बादशाह सिकंदर लोदी से शिकायत की। काजियों ने कहा कि कबीर लोगों को इस्लाम के विरुद्ध नसीहत देते हैं जिससे मुसलमान हिंदुओं की तरह ध्यान और भजन करने लगे हैं। पंडितों ने कहा कि कबीर परंपरा से चले आ रहे धार्मिक और सामाजिक नियमों का खंडन करते हैं। लोगों को ऐसे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं जिसे न हिंदू कहा जा सकता है न मुसलमान। बादशाह ने कबीर को ऐसा न करने का आदेश दिया। किंतु कबीर झुके नहीं और निर्भय होकर कहा कि पारस्परिक मतभेदों में समन्वय कर यदि जीवन को सार्थक बनाने योग्य समता मूलक सच्चे सिद्धांतों पर अमल किया जाए तो इसमें क्या दोष है? धर्म के ठेकेदारों को यह मंजूर नहीं था। कबीर के निर्भयता के पीछे उनके अनुभव की प्रामाणिकता, ईमानदारी, सच्चाई और नैतिकता कार्य कर रही थी।

(लेखक मोटिवेशनल स्पीकर, स्वतंत्र लेखक एवं पूर्व आईएएस हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

क्षमा करें और भूल जाएं

संकलित
दर्शन

जीवन में हमें कई बार चुनौतियों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में हमारा किसी न किसी ऐसी घटना से साक्षात्कार होता है, जो हमें पसंद नहीं होती या जिसके कारण हमें दुख होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारा किसी तरह अनुचित किया हो, शब्दों से हमें भावनात्मक रूप से दुख पहुंचाया हो या शारीरिक कष्ट पहुंचाया हो। परिणाम यह होता है कि हम निराश, दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते, तब तक हमारे साथ क्या होता है? हम हमेशा उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं या किसी और से भी उन बातों को दोहराते रहते हैं। कुछ लोग जिनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, वे शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं या अपना क्रोध किसी और पर निकालते हैं। ऐसा होने पर हम अपने चारों ओर नकारात्मक वातावरण पैदा कर लेते हैं। अपने मन की शांति खो देते हैं। कुछ क्षणों में घटित हुई घटना के लिए हम अपने जीवन के तमाम घंटे इस बात में लगा देते हैं कि उसका बदला कैसे लें। यदि हम इसके बजाय क्षमा कर दें तो हम इस समय का शांतिपूर्वक सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपना ध्यान उस ओर लगाएं, जो आध्यात्मिक रूप से मददगार हो। जैसे कि पिता-परमेश्वर को याद करना, ध्यान-अभ्यास करना, निष्काम सेवा करना और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना। आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान-अभ्यास में सफलता अपने मन को स्थिर करके अंतर में ध्यान टिकाने पर निर्भर है।

भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं

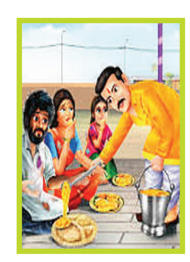

संकलित
प्रेरणा

एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन भजन कीर्तन स्मरण सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा- भाई! मैं तो हूं संसारी आदमी हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूं, तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपए मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से सौ रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। वह श्री जगन्नाथ पुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव जन, हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। भक्त भी वहीं रुक कर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। उसने सोचा क्यों ना सेठ के सौ रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूँ। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास दो रुपए बच गए उसने सोचा चलो अच्छा हुआ दो रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और अंत में उसने सेठ के दो रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणो में चढ़ा दिए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए और उस दो रुपए का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए।

अंतर्मन

आज की पाती

बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं की जड़

हमारा देश विकास और अन्य बहुत से अच्छे कामों में दुनिया भर में नंबर वन पर है और आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में भी हमारा देश दुनिया भर में एक नंबर पर पहुंच चुका है। इस मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई है और भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। अगर भारत सरकार और देश का आमजन बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए गंभीरता दिखाए तो भारत जनसंख्या वृद्धि के मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकना नितांत आवश्यक है क्योंकि इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं।

- पवन साहू, दुर्ग

करंट अफेयर

बेटे की शादी के लिए बिचौलिये भंडारी को मिली छूट

लंदन। कर चोरी और धन शोधन के आरोपों में भारत प्रत्यर्पित किए जाने से संबंधित मुकदमे का सामना कर रहे रक्षा क्षेत्र के बिचौलिये संजय भंडारी की जमानत शर्तों में शुक्रवार को ढील दी गई, ताकि वह अपने बेटे की शादी में शामिल हो सके। यह शादी दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड के एक होटल में होगी। भंडारी (62) ने इस वर्ष के प्रारंभ में लंदन के उच्च न्यायालय में अपने प्रत्यर्पण आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्राप्त की थी। उसने अपने वकीलों के माध्यम से शहर के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट न्यायालय में आवेदन कर कहा था कि उसे 7 से 11 जुलाई के बीच लंदन में एक होटल में रहने की अनुमति दी जाए। प्रत्यर्पण कार्यवाही में भारतीय प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 'क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस' (सीपीएस) के साथ हुए समझौते के तहत, प्रत्यर्पण अपील जारी रहने तक भंडारी की जमानत शर्तों में कुछ बदलाव किए गए हैं। न्यायाधीश ब्रियोनी क्लार्क ने का, "7 से 11 जुलाई के बीच जमानत में ढील दी जाएगी।"नवंबर 2022 में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के बाद पिछले साल ब्रिटेन की तत्कालीन विदेश मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भारत में कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।

ऑफ बीट

कंगारू के दांत हमेशा बढ़ते हैं उनकी उम्र-लिंग का रिकॉर्ड रखते

मेलबर्न। (द कन्वरसेशन) आप किसी जंगली जानवर की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? कुछ ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स के लिए, हमने पता लगाया है कि आप उनके दांतों से उनकी उम्र बता सकते हैं। विलियम पार्कर और एलिस्टेयर इवांस, मोनाश विश्वविद्यालय में शोध किया गया है। यहां के शोधकर्ताओं ने कहा, आर्काइव्स ऑफ ओरल बायोलॉजी में प्रकाशित एक नए पेपर में, हम दिखाते हैं कि कंगारुओं के सामने के दांत कई अलग-अलग तरीकों से उनकी उम्र दर्ज करते हैं - और वे हमें यह भी बता सकते हैं कि कंगारू नर है या मादा। किसी जंगली जानवर की उम्र का पता लगाना पशु चिकित्सकों, पारिस्थितिकीविदों और संरक्षणवादियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वन्यजीव कल्याण और आबादी के समग्र स्वास्थ्य का आकलन दोनों ही जानवरों की उम्र जानने पर निर्भर करते हैं। चूंकि कोई भी जन्मदिन नहीं गिनता, इसलिए वैज्ञानिक अक्सर जंगली जानवरों के दांतों की मदद से यह पता लगाते हैं कि उनकी उम्र कितनी है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश मार्सुपियल्स डिप्रोटोडोंटिया नामक समूह के सदस्य हैं। यह नाम उन जानवरों को संदर्भित करता है जिनके निचले जबड़े में बड़े, सीधे कुतरने वाले दांत होते हैं। कंगारू, वालबीज़, कोआला, वॉम्बैट और पोसम सभी डिप्रोटोडोंटियन मार्सुपियल्स हैं।

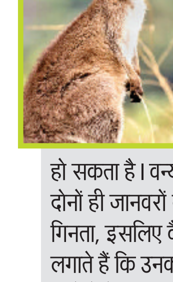

ट्रेंड

प्रभावित किया

श्रीनगर में मुझे जम्मू-कश्मीर के प्रतिभाशाली युवाओं से मिलने का अवसर मिला, जो स्टार्टअप में अग्रणी काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उनमें राष्ट्र और समाज के उत्थान की भावना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। युवा पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

योग एक विज्ञान

योग एक विज्ञान है, और यदि आप चाहें तो एक कला रूप है जिसके साथ आप अपनी व्यक्तिगत प्रकृति को उसकी अंतिम संभावना तक प्रकट कर सकते हैं और एक सचेतन ग्रह का निर्माण भी कर सकते हैं। योग में बहुत शक्ति है।

-सदगुरु, आध्यात्मिक गुरु

एकदम सही वक्त

दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज को पार करने वाली पहली ट्रेन। चूंकि यह योग दिवस है, यह यह दर्शाने के लिए एकदम सही वक्त है कि हमारा बुनियादी ढांचा जितना संभव हो सके आसमान की ओर बढ़ रहा है।

-आनंद महेंद्रा, उद्योगपति

अपराधियों के हौसले बुलंद

आपके योगा मैट की शक्ति आपकी सोच से कहीं अधिक है। इसे एक दिन, एक समय लो। यह केवल अभ्यास से ही बेहतर होता जाता है। झुकते रहें ताकि आप टूटें नहीं। फलदार पेड़ हमेशा झुके होते हैं।

-निकिता दत्ता, अभिनेत्री

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid